भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 | 26 आषाढ़, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 76, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

दिल्ली में चारमंजिला इमारत गिरी, तीन लोगों की मौत

एजेंसी, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-16 में बुधवार शाम एक नवनिर्मित चारमंजिला (ग्राउंड प्लस) इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर को कई घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे से जिंदा बाहर निकाल लिया गया। पुलिस, एनडीआरएफ, दमकल विभाग और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान चलाया। पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त शशांक जायसवाल ने वीरवार को बताया कि बुधवार शाम करीब 4:28 बजे पीसीआर पर सूचना मिली कि रोहिणी सेक्टर-16 के जी-4 पॉकेट स्थित मकान नंबर 151-152 में नवनिर्मित इमारत अचानक ढह गई है। सूचना मिलते ही केएन कटजू मार्ग थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

सुखेंदु-सुष्मिता समेत तीन पूर्व सांसद भाजपा में शामिल

एजेंसी, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को वीरवार को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के तीन पूर्व राज्यसभा सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया है। भाजपा में शामिल होने वालों में सुष्मिता देव, प्रकाश चिक बराइक और सुखेंदु शेखर रॉय शामिल हैं। तीनों नेताओं ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली।

कर्नाटक में सड़क हादसा, छह की मौत

एजेंसी, यल्लापुर। प्रदेश के उत्तर कन्नड़ जिले के यल्लापुर तालुक के अरबैल घाट स्थित बलगार के पास गुरुवार तड़के एक क्रूजर वाहन और ट्रक के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, धारवाड़ के पर्यटक धर्मस्थल और चिक्कमगलूर की यात्रा पर जा रहे थे। इसी दौरान अरबैल घाट में उनके क्रूजर वाहन की ट्रक से भिड़ंत हो गई। मृतकों में पांच की पहचान बसवराज (48), अभिषेक ईश्वर (28), अक्षय (26), अभिषेक (26), संजीव/संजय अंगडी के रूप में हुई है। एक व्यक्ति की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। घायलों में शिवराज दुर्गप्पा मडिवाल (22), मंजूनाथ अशोक चुलकी (32), सचिन तथा चेन्नबसैया बसलिंगैया संपगांव (28) शामिल हैं।

अरविंद और सुभाषिनी का सीजेपी को समर्थन

एजेंसी, नई दिल्ली। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने वीरवा को जंतर-मंतर पहुंच कर सोशल मीडिया अभियान कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के पिछले 20 दिनों से जारी विरोध-प्रदर्शन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने एक्स पर लिखा, 'सांसद अरविंद सावंत और पूर्व सांसद सुभाषिनी अली का इस आंदोलन में शामिल होना छात्रों के संघर्ष को और मजबूती देता है। छात्र समूह की तरफ से उन्हें धन्यवाद।'

भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा ऑस्ट्रेलिया

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नई गतिः रक्षा, ऊर्जा व प्रौद्योगिकी सहित 18 प्रमुख समझौते

एजेंसी, मेलबर्न। एजेंसी, मेलबर्न। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत वीरवार को रक्षा, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा विशेषकर नाभिकीय ऊर्जा, साइबर सुरक्षा, शिक्षा, कौशल विकास, खनन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा सांस्कृतिक विरासत सहित विभिन्न क्षेत्रों में 18 महत्वपूर्ण समझौतों और पहलों को अपनाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ सार्थक वार्ता की। वार्ता के नतीजों के तहत अब आस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियन की सप्लाई होगी। आस्ट्रेलिया तीन प्राचीन कलाकृतियां भारत को लौटाएगा। रक्षा क्षेत्र में सहयोग में दोनों देशों ने कई नए विषयों को शामिल किया है। दोनों नेताओं ने वार्ता के दौरान भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हुई मजबूत प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में बताया, 'हमने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते यानी सीईसीए पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है।' प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में दोनों देशों की वैश्विक मुद्दों पर राय भी सामने रखी। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया मानते हैं कि आतंकवाद केवल किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई साझा और संकल्प अटूट है। उन्होंने कहा कि हमारा यह भी मानना है कि विश्व के अनेक भागों में चल रहे तनावों और युद्धों का समाधान बातचीत और कूटनीति से ही संभव है। पूरे हिंद्ध-प्रशांत क्षेत्र में दोनों देश मिलकर शांति, स्थिरता, नौवहन की स्वतंत्रता और नियम आधारित व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया-कनाडा-भारत प्रौद्योगिकी एवं नवाचार साझेदारी के तहत सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की गई।

'ग्रो मोर, अचीव मोर' के मंत्र के साथ विकसित भारत की ओर बढ़ रहा देशः पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी का भारत 'ग्रो मोर, अचीव मोर' के मंत्र के साथ विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत अब चंद्रयान की सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि गगनयान मिशन और अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लक्ष्य पर भी काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और जल्द ही विश्व की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है।

भारत में 500 मिलियन डॉलर निवेश करेगा ऑस्ट्रेलियनसुपर

एजेंसी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरवार को भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) में ऑस्ट्रेलियनसुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के अतिरिक्त निवेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह निवेश भारत की आर्थिक प्रगति व सुधारों पर वैश्विक निवेशकों के बढ़ते भरोसे का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक्स' पर जारी एक पोस्ट में कहा कि ऑस्ट्रेलियनसुपर का नया निवेश भारत की विकास यात्रा में दुनिया के विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि ये यह भारत की तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था में मौजूद विशाल निवेश अवसरों का भी प्रमाण है। इस निवेश की घोषणा मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलिया-भारत वार्षिक लीडर्स समिट के दौरान की गई।

हाई कोर्ट ने क्रिकेटर अभिषेक के खिलाफ आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने का दिया निर्देश

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ज्योति सिंह की बेंच ने इस मामले के प्रतिवादियों को उनके सोशल मीडिया हैंडल के जरिये नोटिस जारी करने का आदेश दिया। अभिषेक शर्मा ने अपने व्यक्तित्व के अधिकारों के संरक्षण की मांग करते हुए कहा था कि उनके बारे में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) निर्मित कंटेंट बिना उनकी अनुमति के अपलोड किए गए हैं। सात जुलाई को सुनवाई के दौरान मेटा की ओर से वकील वरुण पाठक ने कहा था कि 8 यूआरएल यानि वेबलिंक हैं, जिनमें से 2 का एक्सेस नहीं हो पा रहा है। एक यूआरएल पैपराजी किस्म का फोटो है और उससे व्यक्तित्व के अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं होता है। तब अभिषक शर्मा की ओर से पेश वकील ने कहा था कि वो एआई निर्मित फोटो है। तब कोर्ट ने कहा था कि मानहानि और व्यक्तित्व के अधिकारों में एक पतली रेखा का फर्क है। मानहानि वाले मामलों में भी व्यक्तित्व के अधिकारों का हनन होता है, तब पाठक ने कहा कि अगर किसी ने कुछ कहा जो झूठ और अस्वीकार्य है तो वो दूसरी श्रेणी में आएगा।

मानसून ने पूरे देश को किया कवर, 1 दिन की देरी से पहुंचा

◆ महाराष्ट्र के रायगढ़ में बारिश के बाद तीन हजार एलपीजी सिलेंडर नदी में बहे

एजेंसी, भोपाल/जयपुर/पटना। मानसून ने वीरवार को पूरे देश को कवर कर लिया है। आमतौर पर यह 8 जुलाई को देश का पूरा हिस्सा कवर कर लेता है, लेकिन इस बार एक दिन लेट है।

मानसून के कारण सभी राज्यों में बारिश का दौर जारी है। यूपी में वीरवार सुबह से नोएडा, मथुरा, मेरठ, बुलंदशहर समेत 50 शहरों में तेज बारिश हो रही है। नोएडा में सड़कों पर एक से दो फुट तक पानी भर गया। वहीं, गाजियाबाद में 10 फीट सड़क धंस गई। इसमें कार और बाइक समा गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नालूपानी और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। वहीं, टिहरी में बुधवार को दुकानों के पास लैंडस्लाइड में एक मकान गिर गया। आसपास के दो से तीन मकान कभी भी गिर सकते हैं। उधर, राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ में बुधवार रात बारिश से एक मकान ढह गया। मलबे में से पति-पत्नी समेत लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहीं, महाराष्ट्र के रायगढ़ में बारिश के बाद 3 हजार एलपीजी सिलेंडर पातालगंगा नदी में बह गए। केरल के वायनाड में भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। वीरवार को राहत और बचाव अभियान के दौरान तीन और शव बरामद किए गए। अधिकारियों के मुताबिक, अब भी 2 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। हादसा 7 जुलाई को अनक्कम्पोयिल-मेप्पाडी सुरंग परियोजना के निर्माण स्थल पर हुआ था। यह परियोजना वायनाड और कोझिकोड जिलों को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लगातार बारिश के बीच एक बार फिर लैंडस्लाइड हुई। स्थानीय स्यानाचट्टी के पास यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिर गए। घटना का वीडियो सामने आया है।

ऋण-जमा अनुपात सुधारने को लेकर सीएम ने बैंकर्स को दिए कड़े निर्देश

पात्र लोगों को समयबद्ध ऋण उपलब्ध कराएं बैंकः धामी

एजेंसी, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में ऋण-जमा (सीडी) अनुपात बढ़ाने के लिए कम प्रदर्शन वाले जिलों में नियमित शिविर आयोजित करने और पात्र लोगों को समयबद्ध तरीके से ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने वीरवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 97वीं बैठक में बैंकिंग सेवाओं, ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन व विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य के आर्थिक विकास में बैंकिंग क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बैंकों से किसानों, युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों और आम लोगों तक ऋण की पहुंच आसान बनाने को कहा। मुख्यमंत्री ने बागेश्वर, पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ व टिहरी जिलों में कम ऋण-जमा अनुपात पर चिंता व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन, लीड बैंक और संबंधित विभागों के समन्वय से नियमित शिविर लगाने तथा पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य का ऋण-जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदन में कोई कमी हो तो उसे तकनीकी आधार पर निरस्त करने के बजाय संबंधित व्यक्ति का मार्गदर्शन कर कमियां दूर कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में वार्षिक ऋण योजना के तहत लगभग 96 प्रतिशत और एमएसएमई क्षेत्र में 111 प्रतिशत उपलब्धि राज्य की आर्थिक प्रगति का संकेत है। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-2.0, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, होम-स्टे योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

एडीबी ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.60 फीसदी किया

एजेंसी, नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के बाद अब एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा कीमतों में संभावित बढ़ोतरी के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर का अनुमान 6.90 प्रतिशत से घटाकर 6.60 फीसदी कर दिया है। एडीबी ने वीरवार को जारी एशियाई विकास परिदृश्य (एडीओ) जुलाई 2026 रिपोर्ट में कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए घटाकर 6.6 फीसदी किया गया है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2027-28 के लिए इसे 7.3 फीसदी पर बरकरार रखा गया है।

नई औद्योगिक नीति से हिमाचल में बढ़ेगा निवेश युवाओं को मिलेगा रोजगार : मुख्यमंत्री सुक्खू

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार नई औद्योगिक नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई नीति से राज्य में निवेश आकर्षित करने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने व उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को अधिक आसान बनाने में मदद मिलेगी।

शिमला में उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति तैयार करने से पहले सभी हितधारकों से चर्चा की जा रही है। उनका कहना था कि सरकार ऐसी नीति तैयार कर रही है, जो उद्योगों के अनुकूल हो। उन्होंने कहा कि निवेशकों को सुविधा देने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली को भी और मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों की स्थापना और संचालन से जुड़ी नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान इस दिशा में कई नीतिगत फैसले और कानूनी सुधार किए जा चुके हैं। बैठक में ऊना में बन रहे बल्क ड्रग पार्क और धर्मशाला में निर्माणाधीन यूनिटी मॉल की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दोनों परियोजनाओं का काम तेज करने के निर्देश दिए। बल्क ड्रग पार्क में देश की प्रतिष्ठित कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। 2,071 करोड़ की इस परियोजना से प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। परियोजना के लिए करीब 800 बीघा भूमि समतल की जा चुकी है और साइट विकास का काम तेजी से चल रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के प्रमुख कलपुर्जों पर मूल सीमा शुल्क माफ किया

एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्र ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, वियरेबल्स (स्मार्टवॉच, फिटनेस बैंड) और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान से बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) हटा दी है। यह छूट 31 मार्च, 2029 तक लागू रहेगी, जो गुरुवार से प्रभावी हो गई है। वित्त मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले इन तीन प्रमुख कलपुर्जों के विनिर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) छूट लागू करने के लिए तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने देश में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता कम करने के लिए डिस्प्ले असेंबली, लिथियम-आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) माफ कर दिया है।

ईरान के परमाणु ठिकानों के पास अमेरिकी हमला

जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी सैनिक अड्डों पर किया अटैक

एजेंसी, वॉशिंगटन। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु बिजली फैसिलिटी के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया है। अल जजीरा के मुताबिक यह हमला दोपहर करीब 12 बजे हुआ।

वहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने पिछले 2 दिनों में ईरान के 170 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, हमलों में एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन और मिसाइल भंडार, सैन्य स्पीड बोट और होर्मुज स्ट्रेट के पास तटीय इलाकों में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाब में ईरान ने बताया कि उसने कतर, कुवैत और बहरीन में अमेरिका के सैनिक अड्डों पर ड्रोन हमले किए हैं। ईरानी सेना के मुताबिक, हमलों में कुवैत के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, कतर के अर्ली वॉर्निंग सैटेलाइट एंटीना और बहरीन में अमेरिकी सेना के फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया।

ईरान के सिरिक में अमेरिकी हमले, 3 की मौत

ईरान की न्यूज एजेंसी आईएसएनए के मुताबिक, अमेरिका ने सिरिक शहर में हमला किया। स्थानीय अधिकारियों के हवाले से एजेंसी ने बताया कि इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं।

अमेरिकी हमलों से होर्मुज स्ट्रेट सामान्य करना मुश्किल

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि अमेरिकी सैन्य हमलों से होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री आवाजाही को पूरी तरह सामान्य करना भी मुश्किल हो जाएगा। अल जजीरा के मुताबिक, आईआरजीसी ने बयान में कहा कि युद्ध से पहले के मुकाबले होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही अभी करीब 50% तक बहाल हुई है। मौजूदा रुकावट के लिए उसने अमेरिका की दखलअंदाजी और मनमानी को जिम्मेदार ठहराया।

अमेरिका में भारतीय इंजीनियर ने पत्नी की हत्या की

एजेंसी, वॉशिंगटन डीसी/हैदराबाद। अमेरिका में एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का आरोप है कि उसने पत्नी का गला घोंटकर हत्या की। अगले दिन उसके शव की फोटो भारत में रहने वाली गर्लफ्रेंड को भेजी। करीब 9 महीने तक चली जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल वह हिरासत में है। उसे जमानत के लिए 50 लाख डॉलर यानी करीब 47 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। दोषी साबित होने पर उसे उम्रकैद की सजा हो सकती है। आरोपी की पहचान 30 साल के अविनाश नार्ने के रूप में हुई है। वह तेलंगाना का रहने वाला है। वह अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसकी शादी 5 जून 2025 को 27 साल की राजिता सब्बिनेनी से हुई थी।

राममंदिर चढ़ावा चोरीः आरोपियों के घर से मिले नोटों के बंडल, रिश्तेदारों के 30 बैंक अकाउंट फ्रीज

◆ चंदे की रकम ब्याज पर बांटी, शेयर मार्केट में लगाई

एजेंसी, अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी अनुकल्प मिश्रा को पुलिस वीरवार सुबह 9 बजे उसके घर लेकर गई। वहां करीब 20 मिनट तक तलाशी ली। घरवालों से भी पूछताछ की।

इससे पहले, बुधवार को पुलिस लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडेय को भी उनके घरों पर लेकर गई थी। इनके भी घरों की तलाशी ली थी। पुलिस ने आरोपियों के रिश्तेदारों के 30 बैंक खाते फ्रीज किए हैं। इन खातों में आय की तुलना में अधिक लेन-देन मिलने की बात सामने आई है। वहीं, तीनों के घरों की तलाशी के दौरान पुलिस ने नोटों के बंडल और सोने के जेवर (कान की बालियां, लॉकेट) बरामद किए। साथ ही एक कार भी मिली। हालांकि, पुलिस ने अभी इसका खुलासा नहीं किया कि कितना कैश और सामान किसके घर से बरामद हुआ है? पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अनुकल्प ने पूछताछ में बताया- मैं और अविनाश शुक्ला चोरी के पैसों को शेयर मार्केट में लगाते थे। लोगों को ब्याज पर देते थे। पैसों को करीबियों और रिश्तेदारों को पैसे देते थे। फिर उनसे अपने खातों में पैसे ट्रांसफर करवाते थे। इधर, सपा प्रमुख अखिलेश ने लखनऊ में कहा- हमारे धर्म में चढ़ावे की चोरी महापाप है। इन्होंने महापाप किया है। भाजपा में भगदड़ शुरू भी हो गई है। बहुत सारे लोग मुझसे अभी से संपर्क करने लगे हैं। स्ङ्घ सिर्फ लीपापोती कर रही है। सुनने में तो आया है कि स्ङ्घ पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, एक सदस्य पर 420 का मुकदमा है।

बैठक — पुरानी दिल्ली को संरक्षित और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करेगा आईवीपीएन

विरासत भी बचेगी, आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगीः सीएम रेखा

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने पुरानी दिल्ली के संरक्षण व पुनर्विकास के उद्देश्य से गठित शाहजहानाबाद रिडेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नाम बदलकर अब इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम (आईवीपीएन) कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि निगम के माध्यम से पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित करते हुए उसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बनाने की व्यापक और पहल प्रारंभ हो चुकी है। इसी क्रम में इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम की चेयरपर्सन व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में निगम की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित की गई। बैठक में शहरी

विकास मंत्री एवं निगम के उपाध्यक्ष आशीष सूद, प्रबंध निदेशक संदीप कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

बैठक में पुरानी दिल्ली के समग्र पुनर्विकास, विरासत संरक्षण, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और पर्यटन को बढ़ावा देने से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में ऐतिहासिक चांदनी चौक के पुनर्विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजार का डिजाइन इस प्रकार विकसित किया जाए, जिससे उसकी ऐतिहासिक पहचान, पारंपरिक स्वरूप और सांस्कृतिक गरिमा स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन लाखों लोगों की आवाजाही को देखते हुए क्षेत्र में आधुनिक एवं उपयोगी सार्वजनिक शौचालय (टॉयलेट ब्लॉक) विकसित किए जाएं और नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जाए। मुख्यमंत्री का कहना था कि जब से चांदनी चौक का विकास हुआ है, तभी से यहां बाजार विकसित हुआ था, इसलिए इस बाजार का गौरव वापस लौटाने में यहां के बाजार, व्यापारियों व दुकानदारों का भी ध्यान रखना होगा।

विरासत संरक्षण के साथ व्यापारियों के हितों का भी रखा जाएगा पूरा ध्यान

मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक टाउन हॉल के पुनर्विकास की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इसका एक प्रमुख प्रवेश एवं निकास चांदनी चौक की ओर से भी विकसित किया जाए, ताकि यह ऐतिहासिक इमारत एक प्रमुख विरासत एवं पर्यटन केंद्र के रूप में उभर सके। बैठक में स्थानीय व्यापारियों व दुकानदारों के हितों का भी पूरा ध्यान रखने पर बल दिया गया, ताकि विरासत संरक्षण और व्यापारिक गतिविधियों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।

सीएम योगी ने चित्रकूट के प्रमुख संतों के साथ लगाई कामदगिरि पर्वत की पंचकोसी परिक्रमा

एजेंसी, चित्रकूट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चित्रकूट जनपद प्रवास के दूसरे दिन वीरवार को प्रभु श्रीराम की तपोभूमि एवं धर्मनगरी चित्रकूट में विधि-विधानपूर्वक पूजन-अर्चन कर भगवान श्री कामतानाथ के दर्शन किए।

पावन कामदगिरि परिक्रमा कर प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति एवं जनकल्याण की मंगलकामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरहा हनुमान मंदिर से अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हुए रघुवर किशोर मंदिर के दर्शन किए तथा श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ भगवान श्री कामतानाथ की पावन परिक्रमा की। परिक्रमा के दौरान राम मोहल्ला में संत मदन गोपाल दास जी ने पूजन-अर्चन कराया। प्रथम मुखारविंद पर पुजारी भरत शरण दास महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य विधिवत पूजा संपन्न कराई। भरत मिलाप मंदिर में महंत राम मनोहर दास जी ने भगवान भरत के चरण चिन्हों का पूजन एवं आरती कराई। बरहा हनुमान मंदिर में मंदिर के पुजारी विजय तिवारी महाराज द्वारा श्री हनुमान जी का विधिवत पूजन-अर्चन एवं आरती कराई गई।कामदगिरि महाआरती स्थल पर आचार्य विपिन विराट ने मुख्यमंत्री के करकमलों से भगवान श्री कामतानाथ की महाआरती एवं पूजन संपन्न कराया। इस अवसर पर आचार्य विपिन विराट ने मुख्यमंत्री को कामदगिरि का चित्र एवं रामनामी अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। वहीं कामदगिरि क्षेत्र के सभासद अरुण कुमार त्रिपाठी 'जुगल' ने भगवान श्री कामतानाथ का चित्र एवं अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया।

गुमशुदा महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा को लेकर शिमला प्रशासन अलर्ट

मानव तस्करी रोकने के लिए मजबूत होगी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, डीसी ने दिए दिशा-निर्देश

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जिला स्तरीय मानव तस्करी निरोधक इकाई की बैठक उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में वीरवार को आयोजित की गई।

बैठक में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जी. गणेशा बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में जारी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों के अनुरूप गुमशुदा व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा और शीघ्र खोज सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है। डीसी अनुपम कश्यप ने कहा कि दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के लापता होने की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा बिना किसी अनावश्यक विलंब के तत्काल प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की जानी चाहिए तथा मामले की गंभीरता से जांच प्रारंभ की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्देशों में कहा है कि गुमशुदगी के मामलों में प्रारंभिक जांच के नाम पर देरी नहीं की जा सकती। प्रत्येक शिकायत को संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ लिया जाए, ताकि लापता व्यक्ति का शीघ्र पता लगाया जा सके और मानव तस्करी अथवा अन्य आपराधिक गतिविधियों की आशंका को समय रहते रोका जा सके।

कोर्ट ने तस्करी निरोधक इकाइयों (एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट) को सुदृढ़ करने, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने तथा आधुनिक तकनीक के माध्यम से खोज अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने पर भी बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के यह दिशा-निर्देश महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने, गुमशुदगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा मानव तस्करी जैसी गंभीर चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। इन निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन से आम नागरिकों का कानून-व्यवस्था एवं पुलिस तंत्र पर विश्वास और अधिक मजबूत होगा तथा गुमशुदा व्यक्तियों की शीघ्र बरामदगी में उल्लेखनीय सहायता मिलेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी ममता पॉल, नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अंजली चौहान सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

न्यू शिमला में यातायात व्यवस्था सुधारने के निर्देश

न्यू शिमला क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए चल रही खुदाई से उत्पन्न यातायात अव्यवस्था और जनसुविधाओं पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों और एजेंसियों की बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त अनुपम कश्यप ने की। उपायुक्त ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आम जनता, विद्यार्थियों और कार्यालय जाने वाले लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सड़क बहाली का कार्य कर दिया गया है। उन्होंने नगर निगम, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, एचआरटीसी और संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। न्यू शिमला मार्ग पर यातायात दबाव को देखते हुए छोटे आकार की बसों के संचालन और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश भी दिए गए।

मानसून को लेकर शिमला प्रशासन अलर्ट

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक उपायुक्त एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मानसून सीजन के दौरान आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए विभागों की तैयारियों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन मानसून के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी रखने और मौसम विभाग की चेतावनियों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, बिजली बोर्ड, पुलिस, स्वास्थ्य, नगर निगम, अग्निशमन और अन्य विभागों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध रखने को कहा। अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने और आपात स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बाल आश्रमों में बनेगी पोषण वाटिका

जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति और मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की समीक्षा बैठक वीरवार को उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, पात्र बच्चों और युवाओं को समयबद्ध लाभ उपलब्ध करवाने तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि जिले के सभी बाल देखभाल संस्थानों में पोषण वाटिका विकसित की जाए। इसके लिए कृषि विभाग के आत्मा प्रोजेक्ट का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पोषण वाटिका के माध्यम से बच्चों को कृषि की जानकारी मिलने के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने अधिकारियों को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत पात्र बच्चों और युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, स्वरोजगार, उच्च शिक्षा और विवाह सहायता सहित सभी सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

शिमला की 412 पंचायतें जुड़ेंगी हाई-स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी संशोधित भारतनेट परियोजना के तहत शिमला जिले की सभी 12 विकास खंडों की 412 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) आधारित हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इस संबंध में उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें परियोजना की प्रगति और कार्य योजना की समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने बताया कि परियोजना के तहत शिमला जिले में कुल 3,691 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का प्रस्ताव है। इसके पूरा होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में तेज, सुरक्षित और निर्बाध इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगी। इससे ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल बैंकिंग और सरकारी सेवाओं की पहुंच को और मजबूत किया जा सकेगा। परियोजना में बसंतपुर, मशोबरा, छौहारा, रामपुर, रोहड़ू, कुपवी, ननखड़ी, नारकंडा, टुटू, जुब्बल-कोटखाई और ठियोग सहित सभी 12 विकास खंड शामिल हैं। बैठक में बताया गया कि बसंतपुर ब्लॉक में 40 किलोमीटर ओएफसी बिछाई जा चुकी है और 10 पंचायतों को जोड़ा गया है। मशोबरा ब्लॉक में 299 किलोमीटर केबल बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है तथा 28 पंचायतें नेटवर्क से जुड़ चुकी हैं। छौहारा, रामपुर और रोहड़ू ब्लॉकों में कार्यादेश जारी किए गए हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में सर्वेक्षण और प्रारंभिक कार्य जारी हैं। डीसी ने कहा कि भारतनेट परियोजना से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार होगा और ग्रामीण नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। बैठक में बीएसएनएल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सामाजिक सेवा और छात्र हित के संकल्प के साथ एबीवीपी ने मनाया स्थापना दिवस

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) द्वारा वीरवार को राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के सभागार में जिला स्तरीय राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस एवं परिषद के 78वें स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, प्राध्यापकों, परिषद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में उमेश दत्त उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता सुनील मनोचा ने की। वक्ताओं ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना, संगठन के कार्यों और राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों की भूमिका पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने युवाओं से समाज सेवा और राष्ट्रहित के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। पंजाबी नृत्य, गद्दी नृत्य और मधुर गीतों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर एबीवीपी द्वारा सामाजिक दायित्व और मानव सेवा के उद्देश्य से रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया।

शिविर में विद्यार्थियों, प्राध्यापकों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय युवाओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। जिला कांगड़ा स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान वत्सल राज (ग्रीन फील्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नगरोटा), द्वितीय स्थान आरुषि शर्मा (पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, धर्मशाला) और तृतीय स्थान सुकृति जरियाल (डीएवी पब्लिक स्कूल, नरवाना) ने हासिल किया। विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए गए।

सशक्त विद्यार्थी ही सशक्त भारत का कर सकते हैं निर्माण: आयुष चौधरी

जिला संयोजक आयुष चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि एबीवीपी ज्ञान, शील और एकता के आदर्शों के साथ छात्र हित, समाज हित और राष्ट्रहित में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सशक्त विद्यार्थी ही सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया गया।

मंडी कॉलेज में एबीवीपी ने मनाया स्थापना दिवस

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी इकाई ने राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस एवं परिषद के 78वें स्थापना दिवस के अवसर पर महाविद्यालय परिसर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान पर्चा वितरण, मिष्ठान वितरण और विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में एसएफएस राष्ट्रीय संयोजक कु. शिल्पा उपस्थित रहीं। इकाई अध्यक्ष कर्ण धामी ने कहा कि एबीवीपी छात्र हित, समाज हित और राष्ट्रहित के लिए निरंतर कार्य करने वाला संगठन है, जो विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रभक्ति और सेवा भाव का विकास करता है। कु. शिल्पा ने परिषद की 78 वर्षों की यात्रा और राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल की दूरदर्शी सोच ने हमीरपुर को बनाया शिक्षा, रोजगार और विकास का सशक्त केंद्र

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के विकास के साथ-साथ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भी ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, जिन्होंने क्षेत्र के युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास, सरकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार तथा आधारभूत विकास के नए अवसर सृजित किए।

इनमें इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (आईएचएम), हमीरपुर की स्थापना, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (एचपीएसएसएसबी), हमीरपुर की स्थापना तथा 66 मेगावाट धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। प्रो. प्रेम कुमार धूमल के प्रयासों से स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (आईएचएम), हमीरपुर आज देश व प्रदेश के अग्रणी होटल प्रबंधन संस्थानों में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। संस्थान की स्थापना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के युवाओं को होटल प्रबंधन, पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में विश्वस्तरीय प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार

के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना था, जिसमें यह संस्थान निरंतर सफल सिद्ध हो रहा है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2026-27 में भी संस्थान ने उत्कृष्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड कायम रखा है। इस वर्ष 92 में से 82 अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों ने कैंपस प्लेसमेंट प्रक्रिया में भाग लिया और सभी 82 विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से रोजगार के प्रस्ताव प्राप्त हुए। संस्थान के कार्यकारी प्रधानाचार्य के अनुसार, स्थापना के लगभग 15 वर्षों में आईएचएम हमीरपुर से तीन वर्षीय बी.एससी. डिग्री पाठ्यक्रम के लगभग 950 विद्यार्थी, क्राफ्ट कोर्स (फूड प्रोडक्शन) के लगभग 441 विद्यार्थी तथा डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस के लगभग 263 विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। संस्थान के पूर्व विद्यार्थी आज देश-विदेश के प्रतिष्ठित होटल, पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी उद्योग में अपनी सेवाएं देकर हमीरपुर का ही नहीं बल्कि प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रो. प्रेम कुमार धूमल के प्रथम मुख्यमंत्री कार्यकाल में वर्ष 1998 में हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (एचपीएसएसएसबी), हमीरपुर की स्थापना भी एक ऐतिहासिक निर्णय था। इस संस्थान की स्थापना से प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया का एक समर्पित एवं सुलभ मंच प्राप्त हुआ। अपनी स्थापना के बाद से इस बोर्ड के माध्यम से प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों ने विभिन्न विभागों की भर्ती परीक्षाओं में भाग लिया तथा हजारों युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार प्राप्त हुआ। इस निर्णय ने हमीरपुर को प्रदेश के प्रमुख भर्ती एवं रोजगार केंद्र के रूप में नई पहचान दिलाई। प्रो. प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में 66 मेगावाट धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना को भी महत्वपूर्ण गति मिली। वर्ष 2011 में परियोजना को राज्य सरकार से तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद इसकी विभिन्न वैधानिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया गया।

भाजपा को दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले आत्ममंथन करना चाहिए: हरिकृष्ण

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जिला शिमला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष हरिकृष्ण हिमराल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टी भगवान राम के नाम पर राजनीति करती है और लोगों के दान से जुड़े मामलों में सवालों के घेरे में रही है, उसे दूसरों पर आरोप लगाने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के परिवार पर बयान देने से पहले अपने राजनीतिक कद का ध्यान रखना चाहिए। हिमराल ने कहा कि प्रदेश की जनता भली-भांति जानती है कि कौन बाहरी है और कौन प्रदेश का निवासी। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखते हैं और भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल पर की गई उनकी टिप्पणी सही है। हिमराल ने भाजपा नेताओं को अपने संगठन और मुद्दों पर ध्यान देने की सलाह दी।

एनआईटी हमीरपुर में एनसीसी एयर विंग प्रशिक्षण शिविर में कैडेट्स को मिला मार्गदर्शन

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) हमीरपुर परिसर में आयोजित एनसीसी एयर विंग के दस दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर (एटीसी-223) में वीरवार को सेना और पुलिस अधिकारियों ने कैडेट्स के साथ संवाद कर उन्हें अनुशासन, मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 1 एचपी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी, कुल्लू द्वारा आयोजित शिविर में थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल श्रीधर राजन ने कैडेट्स को सेना में अधिकारी और सैनिक के रूप में भर्ती के विभिन्न अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने अनुशासन, ईमानदारी और नेतृत्व क्षमता को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। हमीरपुर के एसपी बलवीर सिंह ने नशे के दुष्प्रभाव, यातायात नियमों और साइबर अपराधों से बचाव के बारे में जागरूक किया। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवनशैली अपनाने की अपील की। सूबेदार मेजर संजय कुमार सिंह ने अग्निवीर भर्ती से जुड़ी जानकारी साझा की। कैंप कमांडेंट विंग कमांडर कुणाल शर्मा ने अधिकारियों का स्वागत किया और शिविर की गतिविधियों की जानकारी दी। इस दौरान समाज सेवा के तहत आयोजित रक्तदान शिविर में 31 अधिकारियों और कैडेट्स ने रक्तदान किया।

नुक्कड़ नाटक व गीत-संगीत से ग्रामीणों को दी सरकारी योजनाओं की जानकारी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला शिमला में विशेष प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिला की अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम पंचायत देलठ, कमियाना और चलौंठी में लोगों को योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया।

सूचना व जन संपर्क विभाग के अनुमोदित सांस्कृतिक दल 'द बिगिनर्स' और त्रिमूर्ति रंग मंच ने नुक्कड़ नाटक एवं गीत-संगीत के माध्यम से लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान पात्र लाभार्थियों को आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। सांस्कृतिक दलों ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 50 हजार रुपए से कम है, उन्हें अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत सिलाई मशीन, बढ़ई और लोहार कार्य के लिए औजार उपलब्ध करवाए जाते हैं। वहीं, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत पात्र परिवारों को मकान निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा बीपीएल और दो लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को पीजीडीसीए/डीटीपी का एक वर्ष का निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है। अंतरजातीय विवाह पुरस्कार योजना के तहत भी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इस अवसर पर ग्राम पंचायत देलठ के प्रधान उमा दत्त, कमियाना के प्रधान विक्रम सिंह सहित स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।

गॉर्टन कैसल में स्वास्थ्य परामर्श शिविर, 200 कर्मचारियों ने लिया लाभ

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। कर्मचारियों के स्वास्थ्य व कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गॉर्टन कैसल बिल्डिंग परिसर शिमला में स्वास्थ्य परामर्श एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) सुशील ठाकुर ने किया। उन्होंने कर्मचारियों से नियमित स्वास्थ्य जांच करवाने और निवारक स्वास्थ्य देखभाल को जीवनशैली का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। शिविर का आयोजन डॉ. लोकेंदर पाल शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, डीडीयू अस्पताल शिमला के सहयोग से विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की टीम द्वारा किया गया। इस दौरान करीब 200 कर्मचारियों ने स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श सेवाओं का लाभ उठाया। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने कर्मचारियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, बीमारियों से बचाव के उपायों और समय पर चिकित्सा सलाह लेने के महत्व की जानकारी दी। यह पहल भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग की कर्मचारियों के स्वास्थ्य संरक्षण और कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

गोबिंदसागर जलाशय में 7.04 लाख कार्प मत्स्य बीज का संचयन

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। मत्स्य विभाग, हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश के प्रमुख गोबिंदसागर जलाशय में मत्स्य संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से जून और जुलाई 2026 के दौरान 7,04,645 गुणवत्तायुक्त कार्प मत्स्य बीज का सफलतापूर्वक संचयन किया है।

विभागीय मत्स्य बीज फार्मों में तैयार 100 मिलीमीटर से अधिक आकार के इन मत्स्य बीजों का संचयन जलाशय के विभिन्न क्षेत्रों में किया गया। अभियान के तहत 18 जून को विभागीय मत्स्य बीज फार्म नालागढ़ से तैयार 1,50,000 हंगेरियन स्ट्रेन और 1,46,288 कॉमन कार्प मत्स्य बीज का जिला ऊना के दोबड़घाट क्षेत्र में संचयन किया गया। इसके बाद 4 जुलाई को मत्स्य बीज फार्म दयोली (घाघस) से तैयार 2,02,860 कॉमन कार्प मत्स्य बीज का गोविंदसागर जलाशय के मंडी भराड़ी क्षेत्र में तथा 7 जुलाई को मत्स्य बीज फार्म अलसू, जिला मंडी से तैयार 2,05,497 अमूर कार्प मत्स्य बीज का नकराणा क्षेत्र में संचयन किया गया। निदेशक व प्रभारधारी मत्स्य, हिमाचल प्रदेश विवेक चंदेल (भा.प्र.से.) ने बताया कि विभाग जलाशयों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज का नियमित संचयन कर रहा है।

उन्होंने कहा कि 100 मिलीमीटर से अधिक आकार के मत्स्य बीज के जीवित रहने की संभावना अधिक होती है, जिससे जलाशयों में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने और जैव विविधता संरक्षण में सहायता मिलती है। उन्होंने बताया कि मत्स्य सहकारी सभाओं ने भी स्थानीय प्रजातियों के मत्स्य बीज के संचयन पर जोर दिया है, ताकि प्राकृतिक मत्स्य संसाधनों का संरक्षण बेहतर तरीके से किया जा सके। सहायक निदेशक मत्स्य बिलासपुर पंकज ठाकुर ने बताया कि विभागीय मत्स्य बीज फार्म दयोली (घाघस) में गुणवत्तायुक्त कार्प मत्स्य बीज उपलब्ध है, जिसे मत्स्य किसान एक रुपये प्रति बीज की दर से प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने किसानों से मानसून के दौरान तालाबों और बायोफ्लॉक इकाइयों में मत्स्य बीज संचयन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दयोली फार्म में भारतीय मेजर कार्प प्रजातियों का प्रजनन कार्य भी शुरू हो चुका है और शीघ्र ही इनका बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। विभाग का लक्ष्य प्रदेश के जलाशयों में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के साथ मत्स्य किसानों और मछुआरों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।

कुपवी में विकास कार्यों को गति देने पर जोर, विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण) में उप सचिव तथा आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम की केंद्रीय प्रभारी अधिकारी आईएएस कृतिका कुल्हारी ने शिमला जिले के आकांक्षी विकासखंड कुपवी का दौरा कर विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की।

इस अवसर पर आयोजित बैठक में जिला विकास अधिकारी शिमला, खंड विकास अधिकारी कुपवी तथा विभिन्न विभागों के जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के तहत निर्धारित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) की विभागवार प्रगति, उपलब्धियों, चुनौतियों और आगामी कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई। कृतिका कुल्हारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, वहां सुधार के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने नियमित निगरानी, प्रभावी योजना निर्माण और समयबद्ध लक्ष्य प्राप्ति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, आधारभूत संरचना, वित्तीय समावेशन और आजीविका जैसे क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने विभागों को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, नवाचारों को अपनाने और परिणाम आधारित कार्यशैली अपनाने का आह्वान किया। बैठक में विभिन्न विभागों ने अपने कार्यों, उपलब्धियों, चुनौतियों और आगामी योजनाओं का प्रस्तुतीकरण दिया। अधिकारियों ने योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं और उनके समाधान पर भी चर्चा की। केंद्रीय प्रभारी अधिकारी ने कहा कि सभी विभागों के संयुक्त प्रयासों से ही कुपवी विकासखंड को विकास के नए मानकों तक पहुंचाया जा सकता है और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सकता है।

प्रशिक्षण वर्ग सिद्धार्थन ने दिया कार्यकर्ता विकास का मंत्र, संजय टंडन ने समझाई भाजपा की कार्यपद्धति

समर्पित व संस्कारित कार्यकर्ता ही भाजपा की सबसे बड़ी पूंजी

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। भारतीय जनता पार्टी जिला हमीरपुर के चल रहे जिला प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे दिन विभिन्न विषयों पर आयोजित बौद्धिक एवं संगठनात्मक सत्रों में प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, हिमाचल प्रदेश के भाजपा सह-प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा तथा प्रांत संघचालक वीर सिंह रांगड़ा ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया।

सभी वक्ताओं ने संगठन, विचारधारा, कार्य विस्तार, कार्यकर्ता निर्माण तथा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखते हुए कार्यकर्ताओं को प्रभावी जनसंपर्क, वैचारिक स्पष्टता एवं संगठनात्मक कार्यशैली का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे दिन का प्रथम सत्र प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ने 'कार्यकर्ता विकास, संभव एवं दायित्व बोध' विषय पर लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी उसका समर्पित और संस्कारित कार्यकर्ता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से

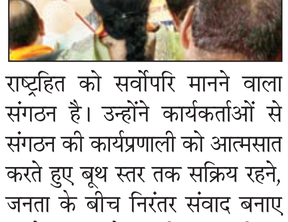

अपने व्यक्तित्व, व्यवहार, संगठनात्मक कौशल तथा जनसेवा के भाव का निरंतर विकास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने दायित्वों का पूर्ण बोध होना चाहिए तथा संगठन द्वारा दिए गए प्रत्येक उत्तरदायित्व का निष्ठा, अनुशासन और समर्पण के साथ निर्वहन करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता का सतत विकास ही संगठन के निरंतर विस्तार और सफलता का आधार है। भाजपा के हिमाचल प्रदेश सह-प्रभारी संजय टंडन ने अपने संबोधन में भाजपा की कार्यपद्धति पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण, अनुशासन और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानने वाला संगठन है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन की कार्यप्रणाली को आत्मसात करते हुए बूथ स्तर तक सक्रिय रहने, जनता के बीच निरंतर संवाद बनाए रखने तथा प्रत्येक दायित्व का निष्ठा और जवाबदेही के साथ निर्वहन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सफलता का आधार उसके प्रशिक्षित, अनुशासित और समर्पित कार्यकर्ता हैं। प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने अपने सत्र में भाजपा के कार्य विस्तार एवं संगठन सुदृढ़ीकरण के विभिन्न आयामों पर चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ने, बूथों को मजबूत बनाने तथा समाज के प्रत्येक वर्ग तक पार्टी की नीतियों और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर भी विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार विकास, रोजगार, वित्तीय प्रबंधन और जनहित से जुड़े अनेक मोर्चों पर अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से तथ्यों के आधार पर जनता के बीच जाकर सरकार की नाकामियों को प्रभावी ढंग से रखने का आग्रह किया। प्रांत संघ चालक वीर सिंह रांगड़ा ने अपने उद्बोधन में भाजपा के विचार परिवार की अवधारणा पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सामाजिक समरसता और सेवा का भाव भारतीय विचार परंपरा की मूल शक्ति है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे संगठन के वैचारिक आधार को गहराई से समझें तथा अपने आचरण, व्यवहार और जनसेवा के माध्यम से इन मूल्यों को समाज में स्थापित करें। उन्होंने कहा कि वैचारिक रूप से सशक्त कार्यकर्ता ही संगठन को स्थायी मजबूती प्रदान करते हैं।

कोल बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान में तेजी लाने के निर्देश

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राज्य स्तरीय कोल बांध विस्थापित व पुनर्वास सलाहकार समिति की समीक्षा बैठक वीरवार को बचत भवन, बिलासपुर में मंडलायुक्त मंडी आरके परुथी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कोल बांध प्रभावित परिवारों से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा कर संबंधित विभागों को समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

मंडलायुक्त ने कहा कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के निर्देशानुसार आयोजित इस बैठक का उद्देश्य प्रभावित परिवारों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों को पात्र परिवारों को प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा पुनर्वास क्षेत्रों में पेयजल, सड़क और सीवरेज से जुड़े लंबित कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे करने के निर्देश दिए। डीपीएफ जमथल में बसाए गए परिवारों के स्थायी पते से संबंधित मुद्दे पर तहसीलदार सदर और खंड विकास अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में एनटीपीसी द्वारा प्रभावित परिवारों को दिए गए रोजगार की समीक्षा भी की गई। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 440 प्रभावितों को रोजगार दिया जा चुका है।

मंडलायुक्त ने भविष्य में उन परिवारों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए, जिनके किसी सदस्य को अभी तक रोजगार नहीं मिला है। हरनोड़ा क्षेत्र में खेल मैदान के विकास और सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने पर भी चर्चा हुई। वहीं, कृषि भूमि तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि 59 हेक्टेयर में से 42 हेक्टेयर क्षेत्र में परीक्षण सफल रहा है और जल्द ही पूरे क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में उपायुक्त राहुल कुमार, एनटीपीसी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

यूपीसीएल को 1320 मेगावाट बिजली खरीद की मिली मंजूरी

25 साल के लिए बिजली खरीद को हरी झंडी

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही बिजली की मांग को देखते हुए उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) को 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीदने की मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के इस फैसले से राज्य की दीर्घकालिक बिजली जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। पिछले लगभग दो वर्षों से लंबित इस योजना को मंजूरी मिलने के बाद यूपीसीएल अब 25 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किसी बिजली उत्पादक कंपनी से बिजली खरीद सकेगा। यह कंपनी केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को आवंटित कोयला लिंकेज का उपयोग कर बिजली का उत्पादन करेगी। इस व्यवस्था के तहत राज्य को वित्तीय वर्ष 2030-31 से बिजली की आपूर्ति शुरू होने की संभावना है।

◆ **कोयला आधारित बिजली खरीद का रास्ता साफ**

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष एम.एल. प्रसाद, सदस्य (विधि) अनुराग शर्मा और सदस्य (तकनीकी) प्रभात किशोर डिमरी की पीठ ने इस संबंध में अंतिम आदेश जारी किया। आयोग ने बढ़ती बिजली मांग और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिसोर्स एडिक्वेसी स्टडी में भी यह संकेत दिया गया था कि यदि समय रहते उत्पादन क्षमता या दीर्घकालिक बिजली खरीद की व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले वर्षों में उत्तराखंड को बिजली की गंभीर कमी का सामना करना पड़ सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बिजली की कमी वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 13 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2035-36 तक बढ़कर करीब 30 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।

स्वास्थ्य विज्ञान में संयुक्त शोध करेंगे एम्स और पतंजलि

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को एक मंच पर लाने की दिशा में एक अभिनव पहल हुई है। पतंजलि अनुसंधान संस्थान, पतंजलि विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ऋषिकेश के बीच क्लिनिकल रिसर्च और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौते के तहत तीनों संस्थान मिलकर क्लिनिकल स्टडीज़, वैज्ञानिक अनुसंधान, अकादमिक सहयोग और स्वास्थ्य विज्ञान में नवाचार पर काम करेंगे। साथ ही शोधार्थियों, वैज्ञानिकों और चिकित्सकों का आपसी आदान-प्रदान भी किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा की संयुक्त क्षमताओं का उपयोग कर रोगियों के

◆ **भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान को मिला साझा मंच**

लिए साक्ष्य-आधारित उपचार विकसित करना है

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद गुरुवार को पतंजलि योगपीठ के महासचिव आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि यह साझेदारी दोनों संस्थानों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यह भारत में एक ऐसे समन्वित स्वास्थ्य मॉडल को सशक्त बनाएगी जिसमें पारंपरिक भारतीय चिकित्सा ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियां एक-दूसरे की पूरक बनकर कार्य करेंगी।

न्यूज ब्रीफ

हरिद्वार में हत्या के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। नगर कोतवाली क्षेत्र में 28 जून को गंगा तट की झाड़ियों में मिले अज्ञात महिला के शव के सनसनीखेज हत्याकांड का हरिद्वार पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस और बदमाशों के बीच बुधवार की देर रात हुई मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। पुलिस के अनुसार, रोड़ीबेलवाला चौकी क्षेत्र के आस्था पथ के समीप करीब 30 वर्षीय अज्ञात महिला का शव झाड़ियों में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत गला घोंटने और मुंह दबाकर दम घुटने से होने की पुष्टि हुई। शरीर पर संघर्ष और चोटों के कई निशान मिलने के बाद नगर कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई।

पुलिस ने नदी-नालों के किनारे रहने वालों को किया अलर्ट, सुरक्षित स्थानों पर भेजा

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। राजधानी देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए दून पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रमेंद्र सिंह डोबाल के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमें संवेदनशील स्थानों पर लगातार गश्त कर रही हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, बारिश की स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। रात से ही पुलिस टीमें नदी-नालों के किनारे और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को लाउड हेलर के माध्यम से सतर्क कर रही हैं। लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए लोगों से नदी-नालों के पास न जाने की अपील की जा रही है। पुलिस नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर भेज रही है, ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो।

यूकेपीएससी परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव अभ्यर्थियों को मिलेगा दोहरा मौका

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों का नया आपत्ति मॉड्यूल लागू कर दिया है। इसके तहत आयोग परीक्षा कराने के बाद दो बार आपत्तियों का निस्तारण करेगा। इसके बाद ही परिणाम जारी करेगा। यह मॉड्यूल तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आयोग से अनुमोदन के बाद नवीन ऑनलाइन प्रश्नपत्र ऑब्जेक्शन मॉड्यूल लागू किया गया है। इसके तहत पहले चरण में परीक्षा संपन्न होने के बाद परीक्षा के ए-सीरीज के प्रश्नपत्र को आयोग वेबसाइट पर जारी करेगा। अभ्यर्थी सात दिन के भीतर इससे संबंधित प्रश्नों, विकल्पों की संरचना पर निशुल्क आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

मानसून की दस्तक के साथ सुस्त पड़ी गंगोत्री-यमुनोत्री यात्रा

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। मानसून सीजन की शुरुआत के साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा की रफ्तार धीमी पड़ गई है। पीक सीजन में जहां दोनों धामों में प्रतिदिन 15 से 20 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे थे वहीं अब यात्रियों की संख्या घटकर महज एक से डेढ़ हजार प्रतिदिन रह गई है। वर्तमान में दोनों धामों की यात्रा लगभग न के बराबर चल रही है। इस वर्ष चारधाम यात्रा का शुभारंभ 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हुआ था। शुरुआती दौर में दोनों धामों में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी। हालांकि जून से यात्रियों की संख्या में लगातार गिरावट आने लगी। पीक सीजन में प्रतिदिन 15 से 20 हजार श्रद्धालुओं के मुकाबले जून में यह आंकड़ा घटकर पांच से सात हजार प्रतिदिन रह गया।

मुख्यमंत्री की खेल योजनाओं के तहत पिथौरागढ़ में 500 खिलाड़ियों का होगा चयन

भारतेंदु संवाददाता, पिथौरागढ़। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम के प्रभावी संचालन को लेकर मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों योजनाओं के तहत कुल 500 खिलाड़ियों के चयन और ट्रायल कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया। जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप बिष्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 8 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 300 खिलाड़ियों (150 बालक एवं 150 बालिकाएं) का चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को प्रतिमाह 1,500 रुपये की खेल छात्रवृत्ति मिलेगी। वर्ष 2022-23 से संचालित इस योजना से अब तक 1,198 खिलाड़ी लाभान्वित हो चुके हैं।

राजकीय आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 25 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन की तिथि

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में वर्ष 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा के तहत विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक छात्र-छात्राएं 25 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुमाऊं मंडल के 37 आईटीआई में इस वर्ष भी दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (ड्यूल ट्रेनिंग सिस्टम) के तहत प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। राजकीय आईटीआई बेतालघाट में कार्यरत कुमाऊं मंडल की प्रवेश समिति के उप नोडल अधिकारी राजेंद्र पांडे ने बताया कि एक वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रशिक्षार्थियों को छह माह चयनित कंपनी में तथा द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रशिक्षार्थियों को एक वर्ष संस्थान और एक वर्ष कंपनी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि में कंपनी नियमानुसार मानदेय भी देगी।

स्वामी सत्व मुनि बने श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण उत्तर पंगत के नए श्रीमहंत

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। तमिलनाडु के कांचीपुरम में आयोजित धार्मिक समारोह में श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण की उत्तर पंगत के नए श्रीमहंत की विधिवत ताजपोशी संपन्न हुई। सर्वसम्मति से पंजाब के स्वामी सत्व मुनि को उत्तर पंगत का श्रीमहंत मनोनीत किया गया। समारोह की अध्यक्षता कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य स्वामी विजेन्द्र सरस्वती ने की। उन्होंने नवनियुक्त श्रीमहंत स्वामी सत्व मुनि को आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की। हरिद्वार स्थित बड़ा उदासीन अखाड़ा द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस अवसर पर देशभर से संत-समाज, विभिन्न अखाड़ों के प्रमुख संत एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांचीपुरम पहुंचे।

देहरादून में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट, बंद रहेंगे स्कूल

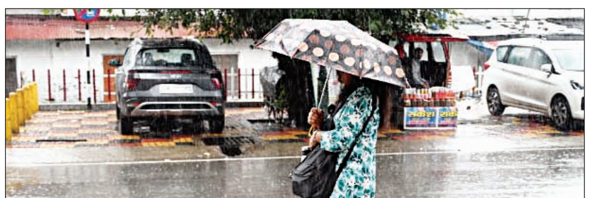

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। भारत मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के आधार पर 10 जुलाई 2026 (शुक्रवार) के लिए नैनीताल जनपद में भारी से बहुत भारी वर्षा, आकाशीय बिजली तथा तीव्र वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। संभावित भू-स्खलन, नदियों-नालों में तेज जलप्रवाह और अन्य आपदा संबंधी जोखिमों को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन जनपद के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिवसीय अवकाश घोषित किया है।

जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ललित मोहन रयाल द्वारा जारी आदेश

◆ **नैनीताल में आज सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी रहेंगे बंद**

में कहा गया है कि मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर 10 जुलाई को जनपद के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी विद्यालय (कक्षा 1 से 12 तक संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थान) तथा सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे।

मुख्य शिक्षाधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

आश्रमों की भागीदारी के बिना भव्य कुंभ संभव नहीं: एबीएसएपी

कुंभ तैयारियों में आश्रमों की भागीदारी की मांग हुई तेज

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। अखिल भारतीय संत आश्रम परिषद ने कुंभ-2027 की तैयारियों में आश्रमधारी संतों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए मेला प्रशासन से शीघ्र संवाद और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग की है।

प्रेस क्लब में गुरूवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानन्द गिरी महाराज और राष्ट्रीय महामंत्री राम विशाल दास महाराज ने कहा कि 19 जून को कुंभ मेलाधिकारी को आश्रमों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक न तो कोई औपचारिक जवाब मिला और न ही परिषद को किसी बैठक या परामर्श के

◆ **मेला प्रशासन से संतों ने मांगा संवाद**

लिए बुलाया गया।

उन्होंने कहा कि कुंभ केवल प्रशासनिक आयोजन नहीं, बल्कि सनातन धर्म की जीवंत आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है। इसकी सफलता के लिए अखाड़ों के साथ-साथ आश्रमों, मठों और स्वतंत्र संत परंपराओं को भी समान सम्मान और सहभागिता मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि हरिद्वार के हजारों आश्रम ही कुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं को आवास, भोजन, चिकित्सा, सत्संग और आध्यात्मिक मार्गदर्शन जैसी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, मेला प्रशासन को उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिए।

परिषद ने मेला प्रशासन से अपील की कि वह किसी के प्रभाव में आने के बजाय सभी संत परंपराओं को साथ लेकर कुंभ की तैयारियां करे। परिषद पदाधिकारियों ने कहा कि अखाड़ा परिषद से जुड़े आंतरिक विवादों के कारण संत समाज की छवि प्रभावित हुई है और ऐसे समय में टकराव नहीं, बल्कि समन्वय और संवाद की आवश्यकता है।

उन्होंने कहाकि मेला प्रशासन अखाड़ों के चार-छह गैंगधारियों के चंगुल से निकले। यदि ऐसा नहीं होता है तो बिना संतों के मेला संभव नहीं है। कहाकि अखाड़ा परिषद के सेंटिंग-गेटिंग वाले कभी भी मेला प्रशासन को धोखा दे सकते हैं। मेला प्रशासन इनके बहकावे में न आए।

70 विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति पर मंथन करेगा यूकेडी नेतृत्व

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण एवं निर्णायक बैठक 11 जुलाई 2026 को वृंदावन गार्डन, कारगी चौक, देहरादून में केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुकरेती की अध्यक्षता में आयोजित होगी। बैठक में प्रदेशभर से केंद्रीय पदाधिकारी, संरक्षक मंडल, जिला एवं महानगर अध्यक्ष तथा संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी भाग लेंगे।

केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल आगामी विधानसभा चुनाव प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर पूरी ताकत, पूरे आत्मविश्वास और जीत के संकल्प के साथ लड़ेगा। पार्टी अब केवल चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं कर रही, बल्कि उत्तराखंड की राजनीति में एक मजबूत क्षेत्रीय विकल्प के रूप में उभरने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा रही है।

उन्होंने बताया कि लगभग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3 से 4 संभावित प्रत्याशी पिछले कई महीनों से सक्रिय रूप से जनसंपर्क और चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कार्यकारिणी की बैठक में सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों की राजनीतिक स्थिति, संगठन की मजबूती, संभावित प्रत्याशियों की

◆ **11 जुलाई को देहरादून में यूकेडी की निर्णायक बैठक**

तैयारी तथा चुनावी रणनीति पर विस्तार से मंथन कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।

श्री कुकरेती ने स्पष्ट कहा कि पार्टी में अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा। उत्तराखंड क्रांति दल एक अनुशासित संगठन है और संगठन की गरिमा से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। जो भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता पार्टी के संविधान, अनुशासन और सामूहिक निर्णयों की अवहेलना करेगा, उसके विरुद्ध संगठनात्मक कार्रवाई करने से पार्टी पीछे नहीं हटेगी। संगठन सर्वोपरि है और सभी को उसी भावना से कार्य करना होगा।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आज बेरोज़गारी, पलायन, भ्रष्टाचार, भू-कानून, मूल निवास, संसाधनों की लूट और युवाओं के भविष्य जैसे गंभीर संकटों से जूझ रहा है। राष्ट्रीय दलों ने वर्षों तक प्रदेश की जनता को केवल आश्वासन दिए हैं, जबकि उत्तराखंड क्रांति दल इन मूल मुद्दों को लेकर जनता के बीच मजबूती से जाएगा और एक सशक्त क्षेत्रीय विकल्प प्रस्तुत करेगा।

उत्तराखंड के विद्यालयों में विकास कार्यों को मिलेगी गति

समग्र शिक्षा के तहत निर्माण कार्यों को शीघ्र करें पूर्ण : डॉ. धन सिंह रावत

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। सूबे में समग्र शिक्षा के तहत संचालित विभिन्न निर्माण कार्य समयबद्ध पूर्ण हो इसके लिये विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। योजना के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय वर्षों के अधूरे पड़े कार्यों को ससमय पूरा करने के साथ ही नये निर्माण कार्यों को भी निश्चित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने को कहा गया है। इसके अलावा समग्र शिक्षा व पीएम-श्री विद्यालयों में स्थापित होने वाले विभिन्न वर्चुअल क्लासेज के कार्यों में भी तेजी लाने को कहा गया है। निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी करने वाली कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिये गये है।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज विद्यालयी शिक्षा

◆ **निर्माण कार्यों की साप्ताहिक रिपोर्ट मांगी गई**

महानिदेशालय स्थित सभागार में समग्र शिक्षा परियोजना की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने समग्र शिक्षा के अन्तर्गत निर्माण कार्यों में हो रही लेटलतीफी पर नाराजगी जताते हुये कहा कि परियोजना के अंतर्गत विगत वित्तीय वर्षों में स्वीकृत निर्माण कार्य अभी तक अधूरे पड़े हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये।

डॉ. रावत ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर 7803 निर्माण कार्य स्वीकृत हुये हैं जिसमें से 5735 निर्माण कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं जबकि 1068 निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं।

दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे पर मलबा आने से यातायात ठप

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। भारी बारिश के चलते

◆ **चमोली में देवाल-लोहाजंग मार्ग भी मलबे से बाधित**

कई स्थानों पर भूस्खलन और जलभराव की स्थिति सामने आ रही है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में आज और कल भारी से अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली चमकने और तेज बारिश के दौर को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है।

लगातार बारिश के कारण दिल्ली-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया है। कालसी क्षेत्र में जुड्डो झरने के समीप पहाड़ी से मलबा मिट्टी और बड़े पत्थर गिरने के कारण सड़क बंद हो गई। बृहस्पतिवार सुबह करीब चार बजे मलबा आने से मार्ग पूरी तरह बाधित हुआ था। इसके बाद विभागीय कर्मचारियों ने जेसीबी मशीन की मदद से मलबा हटाकर सुबह करीब छह बजे यातायात बहाल कर दिया था लेकिन बारिश जारी रहने के कारण दोबारा मलबा और पत्थर गिरने लगे जिससे मार्ग फिर से बंद हो गया।

सड़क खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग की टीम और जेसीबी मशीन मौके पर तैनात हैं। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही बारिश कम होगी और पहाड़ी से मलबा गिरना बंद होगा वैसे ही मार्ग को दोबारा खोलने का काम शुरू कर दिया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल आवाजाही पर रोक लगाई गई है।

सुरक्षा बच्चों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को दिए सख्त निर्देश

आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे पर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते आवारा कुत्तों के खतरे और उनसे बच्चों सहित आम लोगों की सुरक्षा से जुड़े मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव सहित कई विभागों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी अदालत के सामने प्रस्तुत करें।

मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई की। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों से जुड़ा है

जिसमें देशभर में आवारा कुत्तों के कारण बढ़ रही घटनाओं और बच्चों को होने वाले नुकसान को गंभीरता से लेते हुए राज्यों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी राज्य प्रशासन से जवाब तलब किया है।

हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव संबंधित विभागों के सचिव भारत सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं कि वे आगामी सात अगस्त 2026 तक अपने अनुपालन हलफनामे अदालत में दाखिल करें। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित विभागों को यह बताना होगा कि आवारा कुत्तों की समस्या को नियंत्रित करने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अब तक क्या कदम उठाए हैं।

अदालत ने इस बात पर चिंता जताई कि आवारा कुत्तों के हमलों से बच्चों और कमजोर वर्ग के लोगों को सबसे अधिक खतरा रहता है। कई स्थानों पर कुत्तों के झुंड सड़कों और सार्वजनिक क्षेत्रों में घूमते रहते हैं जिससे दुर्घटनाओं और हमलों की आशंका बनी रहती है। हाईकोर्ट ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसके लिए प्रभावी व्यवस्था बनाना जरूरी है।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित विभागों से यह भी अपेक्षा की है कि वे केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहें बल्कि जमीन पर प्रभावी कदम उठाएं। आवारा कुत्तों की पहचान उनके नियंत्रण नसबंदी और सुरक्षित प्रबंधन जैसी व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन को ठोस योजना तैयार करनी होगी।

ऊखीमठ के स्कूलों और अस्पताल में अग्नि सुरक्षा निरीक्षण संपन्न

भारतेंदु संवाददाता, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जिले के कस्बा ऊखीमठ में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से शैक्षणिक संस्थानों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का विस्तृत निरीक्षण किया गया। यह अभियान पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड, देहरादून द्वारा जारी निर्देशों तथा पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग के आदेश के अनुपालन में चलाया गया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी गणनाथ सिंह बिष्ट के नेतृत्व में अग्निशमन विभाग की टीम ने विभिन्न संस्थानों का दौरा कर वहां उपलब्ध अग्नि सुरक्षा संसाधनों और व्यवस्थाओं का बारीकी से परीक्षण किया।

निरीक्षण का उद्देश्य संभावित अग्निकांड की स्थिति में संस्थानों की तैयारियों का आकलन करना तथा आवश्यक सुधार संबंधी सुझाव देना था।

◆ **आपातकालीन निकास मार्गों का किया निरीक्षण**

निरीक्षण के दौरान टीम ने भवनों में लगाए गए अग्निशमन यंत्रों, अग्नि सुरक्षा उपकरणों, आपातकालीन निकास मार्गों और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि सभी उपकरण सही स्थिति में कार्य कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रभावी उपयोग किया जा सकता है।

साथ ही यह भी देखा गया कि आपातकालीन निकास मार्ग पूरी तरह खुले और अवरोध मुक्त हों ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जिन स्थानों पर सुधार की आवश्यकता महसूस हुई, वहां संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

चन्नी खेमे की बैठक से पंजाब कांग्रेस में हलचल

संगठनात्मक फेरबदल के बाद समर्थक नेताओं संग मंथन, भूपेश बघेल से मुलाकात और आगामी रणनीति पर रही चर्चा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब कांग्रेस में हाल ही में हुए संगठनात्मक फेरबदल के बाद पार्टी के भीतर जारी राजनीतिक हलचल और गुटबाजी के बीच गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने समर्थक वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक कर आगामी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की। यह बैठक वरिष्ठ कांग्रेस नेता राणा गुरजीत सिंह के आवास पर हुई, जिसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा, परगट सिंह, भारत भूषण आशु समेत चन्नी खेमे के कई प्रभावशाली नेता शामिल हुए। करीब कई घंटों तक चली इस बैठक को पंजाब कांग्रेस की मौजूदा परिस्थितियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार बैठक में पंजाब कांग्रेस की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, संगठन में हाल ही में किए गए बदलाव, नेताओं को नई जिम्मेदारियों तथा भविष्य की रणनीति को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में मौजूद नेताओं ने पार्टी के भीतर चल रहे घटनाक्रम, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और संगठन को मजबूत बनाने के उपायों पर अपने-अपने विचार रखे। हालांकि बैठक समाप्त होने के बाद किसी भी नेता ने आधिकारिक तौर पर मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे चन्नी खेमे की शक्ति प्रदर्शन और आगे की रणनीति तय करने वाली अहम बैठक माना जा रहा है।

बैठक के दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई कि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल से आज या कल मुलाकात करेंगे या नहीं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में संगठनात्मक फेरबदल, पार्टी के भीतर उठ रहे असंतोष और भविष्य की राजनीतिक दिशा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि मुलाकात के समय को लेकर अंतिम निर्णय बैठक के दौरान ही लिया जाना था।

बैठक में शामिल वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां प्रत्येक नेता को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने संकेत दिए कि पार्टी के भीतर मतभेदों को संवाद के माध्यम से दूर किया जा सकता है और संगठन की मजबूती ही सभी नेताओं की प्राथमिकता है। दूसरी ओर, पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल भी लगातार पार्टी नेताओं और संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने पंजाब कांग्रेस भवन में यूथ कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक कर आगामी चुनावों, संगठनात्मक गतिविधियों और युवा कार्यकर्ताओं की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा जिला अध्यक्षों, कार्यकारी अध्यक्षों, वरिष्ठ नेताओं और अन्य संगठनात्मक पदाधिकारियों के साथ भी उनका लगातार संवाद जारी है।

पिछले कई दिनों से चंडीगढ़ में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। पार्टी नेतृत्व का प्रयास है कि संगठन में चल रहे असंतोष और गुटबाजी को समाप्त कर सभी नेताओं को एक मंच पर लाया जाए। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर फीडबैक लिया जा रहा है और नेताओं की राय के आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चरणजीत सिंह चन्नी की अपने समर्थक नेताओं के साथ हुई यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब पंजाब कांग्रेस नेतृत्व संगठन को एकजुट करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार करने में जुटा है। ऐसे में इस बैठक के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में चन्नी और भूपेश बघेल की संभावित मुलाकात, संगठन में संभावित बदलाव और पार्टी नेतृत्व के अगले कदमों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

डीए विवाद में पीएसपीसीएल एमडी से हाई कोर्ट ने मांगा हलफनामा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

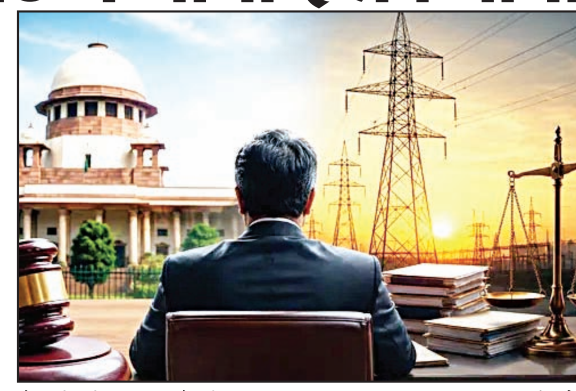

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) से जुड़े मामले में पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के प्रबंध निदेशक को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट करने को कहा है कि पीएसपीसीएल अपने कर्मचारियों को डीए देने के मामले में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है या केवल पंजाब सरकार के आदेशों को लागू करता रहा है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में यह तथ्य सामने आना जरूरी है कि डीए और डीआर भुगतान को लेकर निगम की अब तक क्या नीति रही है। अदालत ने कहा कि यदि पीएसपीसीएल अपने स्तर पर फैसले लेता रहा है तो स्थिति अलग होगी, लेकिन यदि वह राज्य सरकार के निर्णयों का पालन करता आया है तो मामले की दिशा अलग हो सकती है।

यह मामला पीएसपीसीएल कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को डीए व डीआर के भुगतान से जुड़ा है। निगम और अन्य अपीलकर्ताओं ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान पीएसपीसीएल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मूल याचिका में निगम को पक्षकार नहीं बनाया गया था। उन्होंने कहा कि पीएसपीसीएल एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है, जिसके अपने सेवा नियम हैं, इसलिए बिना सुनवाई के कोई फैसला नहीं किया जा सकता।

न्यूज ब्रीफ

मोहाली समेत पंजाब में कॉलोनी नियमों में बदलाव

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने मोहाली समेत पूरे प्रदेश में कॉलोनियों के विकास और भवन निर्माण की मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। हाउसिंग एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना के अनुसार अब कॉलोनाइजर और डेवलपर चेंज ऑफ लैंड यूज (सीएलयू), लेआउट प्लान और कॉलोनाइजर लाइसेंस के लिए एकीकृत आवेदन कर सकेंगे। नई व्यवस्था में 21 मीटर तक ऊंची इमारतों के नक्शे थर्ड पार्टी प्रमाणन के आधार पर मंजूर किए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया में तेजी आएगी। सरकार ने अलग-अलग मंजूरियों के लिए समय सीमा भी तय कर दी है। सीएलयू आवेदन का निपटारा 23 कार्य दिवस, लेआउट प्लान और कॉलोनाइजर लाइसेंस 30 कार्य दिवस में जारी करना होगा। सीएलयू की वैधता दो वर्ष निर्धारित की गई है। सरकार का दावा है कि नए नियमों से निर्माण परियोजनाओं में तेजी आएगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। मोहाली में बढ़ती आवासीय परियोजनाओं को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

जलभराव समस्या पर मेयर ने मांगा जवाब

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। बारिश के दौरान शहर में जलभराव की समस्या को लेकर नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मेयर सरबजीत सिंह समाना ने कहा है कि जल निकासी व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों और फील्ड स्टाफ की जिम्मेदारी तय की जाएगी। जिन क्षेत्रों में पानी भरने की शिकायतें मिली हैं, वहां समीक्षा कर लापरवाही के कारणों का पता लगाया जाएगा। मेयर ने कहा कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की कोताही सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उनका उद्देश्य केवल बारिश के समय पानी निकालना नहीं, बल्कि ऐसी स्थायी व्यवस्था तैयार करना है जिससे भविष्य में शहरवासियों को जलभराव की परेशानी न झेलनी पड़े। गौरतलब है कि मेयर बनने के बाद सरबजीत सिंह समाना ने शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा कर मानसून से पहले नालों, रोड गलियों और स्टॉर्म वाटर ड्रेनों की सफाई के निर्देश दिए थे। अब हालिया बारिश के बाद इन तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।

फिल्म सतलुज मामला पहुंचा हाई कोर्ट

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित फिल्म 'सतलुज' को ओटीटी मंच से हटाए जाने का मामला अब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है। फिल्म को दोबारा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता शरवण सिंह ने संविधान के अनुच्छेद-226 के तहत याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी), पंजाब सरकार, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड और जी5 को पक्षकार बनाया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म को बिना किसी सार्वजनिक वैधानिक या न्यायिक आदेश के हटाया गया, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिकों के सूचना प्राप्त करने के अधिकार का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से मांग की है कि फिल्म को पूरे देश में जी5 पर तत्काल बहाल करने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही हटाने के कारणों से जुड़े किसी भी सरकारी या न्यायिक आदेश को सार्वजनिक करने की मांग भी की गई है।

पीरमुछल्ला में पार्क, लाइब्रेरी निर्माण लटका वर्षों से इंतजार कर रहे हजारों निवासी

भारतेन्दु संवाददाता, जीरकपुर।

पीरमुछल्ला में नगर परिषद की ओर से प्रस्तावित म्यूनिसिपल पार्क और सार्वजनिक लाइब्रेरी की परियोजना करीब छह वर्ष बाद भी शुरू नहीं हो सकी है। वर्षों पहले तैयार की गई योजना अब तक फाइलों में ही सीमित है, जिससे क्षेत्रवासियों में नाराजगी बढ़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बढ़ती आबादी के बावजूद पार्क, लाइब्रेरी और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव है। पढ़ाई, सैर और मनोरंजन के लिए उन्हें पंचकूला, चंडीगढ़ और मोहाली जाना पड़ता है।

वर्ष 2021 में प्रशासन ने करीब नौ एकड़ सरकारी भूमि पर मल्टीलेवल स्पोर्ट्स स्टेडियम, आधुनिक लाइब्रेरी और अन्य सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था, लेकिन प्रशासनिक और राजनीतिक बदलावों के कारण योजना आगे नहीं बढ़ सकी। बाद में चिह्नित भूमि को स्ट्रीट वेंडिंग जोन में बदलने का प्रस्ताव भी आया, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी परविंदर सिंह भट्टी ने बताया कि यह प्रस्ताव फिलहाल लंबित है।

छह साल से अधूरी परियोजना

पीरमुछल्ला में नगर परिषद की ओर से प्रस्तावित म्यूनिसिपल पार्क और सार्वजनिक लाइब्रेरी की परियोजना करीब छह वर्ष बाद भी शुरू नहीं हो सकी है। वर्षों पहले तैयार की गई योजना अब तक फाइलों में ही सीमित है, जिससे क्षेत्रवासियों में नाराजगी बढ़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बढ़ती आबादी के बावजूद पार्क, लाइब्रेरी और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव है। पढ़ाई, सैर और मनोरंजन के लिए उन्हें पंचकूला, चंडीगढ़ और मोहाली जाना पड़ता है। वर्ष 2021 में प्रशासन ने करीब नौ एकड़ सरकारी भूमि पर मल्टीलेवल स्पोर्ट्स स्टेडियम, आधुनिक लाइब्रेरी और अन्य सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था।

मोहाली में चंडीगढ़ की तर्ज पर साइकिल ट्रैक बनाने की उठी मांग

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली

शहर में सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल यातायात व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) सेक्टर-67 ने महत्वपूर्ण पहल की है। एसोसिएशन ने मोहाली की सेक्टर डिवाइडिंग सड़कों पर चंडीगढ़ की तर्ज पर अलग साइकिल ट्रैक विकसित करने की मांग उठाई है। इस संबंध में एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब सरकार के प्रधान सचिव तथा मोहाली नगर निगम के मेयर को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की है।

आरडब्ल्यूए के प्रधान नरेंद्र सिंह कसाना ने बताया कि मोहाली का विकास सुनियोजित तरीके से किया गया है और गमाडा के मास्टर प्लान में भी सेक्टर डिवाइडिंग सड़कों के किनारे करीब आठ फुट चौड़े साइकिल ट्रैक का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद वर्षों बीत जाने के बाद भी इस योजना को धरातल पर लागू नहीं किया गया। परिणामस्वरूप साइकिल चालकों को मजबूरन मुख्य सड़क पर ही वाहनों के साथ चलना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है।

उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी और यातायात के दबाव को देखते हुए अब अलग साइकिल ट्रैक की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। यदि साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराया जाए तो अधिक लोग दैनिक आवागमन के लिए साइकिल का उपयोग करेंगे। इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होगी, यातायात का दबाव घटेगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी।

एसोसिएशन ने अपने ज्ञापन में विशेष रूप से कुंभड़ा चौक से फेज-11 तक सेक्टर डिवाइडिंग सड़क पर प्राथमिकता के आधार पर साइकिल ट्रैक विकसित करने की मांग की है। साथ ही शहर की अन्य प्रमुख सेक्टर डिवाइडिंग सड़कों पर भी चरणबद्ध तरीके से साइकिल ट्रैक बनाने का सुझाव दिया गया है, ताकि पूरे शहर में सुरक्षित और व्यवस्थित साइकिल नेटवर्क विकसित हो सके।

वीआईपी मूवमेंट से चंडीगढ़-जीरकपुर मार्ग बंद, बारिश में फंसे सैकड़ों लोग

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

सिटी ब्यूटीफुल के नाम से पहचाने जाने वाले चंडीगढ़ में यातायात व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। वीरवार को वीआईपी मूवमेंट के चलते जीरकपुर से चंडीगढ़ में प्रवेश करने वाली मुख्य सड़क को काफी समय तक बंद रखा गया, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बीच सड़क बंद होने से हालात और ज्यादा खराब हो गए। सैकड़ों वाहन चालक कई घंटों तक जाम में फंसे रहे और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी देरी हुई।

यह मार्ग चंडीगढ़ में प्रवेश करने वाले सबसे व्यस्त रास्तों में से एक है। रोजाना हजारों लोग नौकरी, व्यापार और अन्य जरूरी कामों के लिए जीरकपुर से चंडीगढ़ आते-जाते हैं। सुबह और शाम के व्यस्त समय में इस सड़क पर पहले ही वाहनों का दबाव अधिक रहता है और कई बार लंबा जाम लग जाता है। ऐसे में वीआईपी मूवमेंट के दौरान अचानक मार्ग बंद किए जाने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई।

वीरवार को मौसम भी खराब था और कई इलाकों में तेज बारिश हो रही थी। सड़क बंद होने के कारण बड़ी संख्या में वाहन चालक बीच रास्ते में फंस गए। कई लोग अपने वाहनों में बैठे रहे, जबकि कुछ यात्रियों को बारिश में भीगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ी। लंबे समय तक जाम में फंसे रहने के कारण लोगों में नाराजगी बढ़ती गई।

वाहन चालकों का कहना था कि वीआईपी मूवमेंट के लिए आम जनता की परेशानियों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। लोगों ने सवाल उठाया कि सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है, लेकिन इसके लिए वैकल्पिक इंतजाम भी किए जाने चाहिए ताकि आम लोगों को घंटों तक परेशानी का सामना न करना पड़े।

जाम में फंसे कई लोगों ने अपनी नाराजगी जताने के लिए लगातार वाहनों के हॉर्न बजाए। लोगों का कहना था कि हर बार वीआईपी आवाजाही के दौरान आम नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ती है। एक तरफ प्रशासन शहर को व्यवस्थित और आधुनिक बनाने के दावे करता है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं यातायात प्रबंधन की कमियों को उजागर करती हैं।

स्थानीय निवासियों ने बताया कि जीरकपुर-चंडीगढ़ मार्ग पर पहले से ही यातायात का भारी दबाव रहता है। इस रास्ते पर रोजाना हजारों वाहन चलते हैं। ऐसे में अगर बिना पर्याप्त सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था के सड़क बंद कर दी जाती है तो लोगों की मुश्किलें बढ़ना स्वाभाविक है। लोगों ने मांग की कि भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचने के लिए प्रशासन को पहले से बेहतर योजना तैयार करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की।

फेज-8बी की बदहाल सड़कों से उद्योगपति और कर्मचारी परेशान

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली।

औद्योगिक क्षेत्र फेज-8बी की बदहाल सड़कें मानसून की पहली बारिश के बाद और अधिक जर्जर हो गई हैं। जगह-जगह बने गहरे गड्ढों में पानी भर जाने से रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले हजारों कर्मचारी, आईटी प्रोफेशनल, उद्योगपति, कारोबारी और भारी वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय उद्योगपतियों ने नगर निगम से क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है।

◆ अधूरी सड़क और गहरे गड्ढों से रोजाना हजारों लोग हो रहे परेशान

औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण फेज-8बी में प्रतिदिन बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहन, ट्रक और मालवाहक गाड़ियां आती-जाती हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र की एक प्रमुख सड़क का निर्माण कार्य लंबे समय से अधूरा पड़ा हुआ है। निर्माण स्थल पर लगाए गए बैरिकेड और फैली मिट्टी बारिश के कारण दलदल में बदल गई है। इससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और कई स्थानों पर लंबा जाम भी लग जाता है।

जीरकपुर में अवैध निर्माण पर नगर परिषद ने कीं 27 दुकानें सील

भारतेन्दु संवाददाता, जीरकपुर

जीरकपुर नगर परिषद ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव किशनपुरा स्थित रहमत होम्स सोसाइटी में बनाई गई 27 अवैध दुकानों को सील कर दिया। नगर परिषद की बिल्डिंग ब्रांच की टीम ने बुधवार को मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में सभी दुकानों को लाल रंग की सीलिंग टेप लगाकर अपने कब्जे में ले लिया। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि किसी ने सील तोड़ने या दुकानों को खोलने का प्रयास किया तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार रहमत होम्स सोसाइटी के लिए स्वीकृत भवन नक्शे में भूतल पर पार्किंग और उसके ऊपर आवासीय फ्लैट बनाने की अनुमति दी गई थी। लेकिन जांच में सामने आया कि बिल्डर ने स्वीकृत नक्शे का उल्लंघन करते हुए पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान पर व्यावसायिक दुकानों का निर्माण कर लिया। इससे न केवल भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन हुआ, बल्कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए पार्किंग की सुविधा भी प्रभावित हुई।

नगर परिषद को इस संबंध में शिकायतें मिलने के बाद बिल्डिंग ब्रांच ने मौके का निरीक्षण किया। जांच में निर्माण को पूरी तरह अवैध पाए जाने पर बिल्डर को कई बार नोटिस जारी किए गए। नोटिसों में स्पष्ट रूप से अवैध निर्माण हटाने और स्वीकृत नक्शे के अनुसार भवन को बहाल करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि बिल्डर ने न तो अवैध दुकानों को हटाया और न ही नोटिसों का संतोषजनक जवाब दिया।

इसके बाद नगर परिषद ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए बुधवार को सभी 27 दुकानों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने दुकानों के बाहर लाल रंग की सीलिंग टेप लगाई और उन्हें प्रशासनिक कब्जे में ले लिया। मौके पर पर्याप्त प्रशासनिक अमला तैनात रहा ताकि कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की जा सके।

नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी परविंदर सिंह भट्टी ने बताया कि रहमत होम्स के निर्माणकर्ता ने स्वीकृत नक्शे के विपरीत जाकर दुकानों का निर्माण किया, जो पूरी तरह अवैध है।

हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल पदोन्नति पर हटाई रोक

हाई कोर्ट के फैसले से पंजाब के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपलों की पदोन्नति प्रक्रिया हो सकेगी दोबारा शुरू

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपलों की पदोन्नति पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है। अदालत के इस फैसले के बाद अब प्रिंसिपल पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले के अंतिम निर्णय तक होने वाली सभी पदोन्नतियां न्यायालय के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी।

जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस अमरिंदर सिंह ग्रेवाल की खंडपीठ ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई छह माह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाओं में यह सवाल उठाया गया है कि क्या सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल और अन्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्त या पदोन्नति के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास होना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि प्रिंसिपल और अन्य प्रशासनिक पद शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा हैं, इसलिए इन पदों पर नियुक्त के लिए भी वही पात्रता मानदंड लागू होने चाहिए, जो शिक्षकों के लिए निर्धारित हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों के संचालन और शैक्षणिक व्यवस्था में प्रिंसिपल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

वहीं, पंजाब सरकार ने अदालत में दलील दी कि प्रिंसिपल और अन्य प्रशासनिक पद मूल रूप से अध्यापन से जुड़े नहीं बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारियों वाले पद हैं। सरकार ने कहा कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में प्रिंसिपल को कक्षा में पढ़ाना भी पड़े, तब भी पद का मूल स्वरूप प्रशासनिक ही रहता है।

राज्य सरकार ने यह भी कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत टीईटी की अनिवार्यता पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए है। सरकार ने इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का भी हवाला दिया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने माना कि यह मामला विस्तृत विचार की मांग करता है। अदालत ने 18 दिसंबर 2025 को जारी अंतरिम आदेश को समाप्त कर दिया, जिसके कारण प्रिंसिपलों की पदोन्नति प्रक्रिया रुकी हुई थी।

कोर्ट ने कहा कि नियमित प्रिंसिपल नहीं होने से स्कूलों के प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए पदोन्नति प्रक्रिया को जारी रखना जरूरी है। हालांकि अंतिम फैसला आने तक सभी पदोन्नतियां अदालत के निर्णय के अधीन रहेंगी।

पदोन्नति विवाद पर राहत

हाई कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपलों की पदोन्नति प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सकेगी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति पर लगी अंतरिम रोक हटाई जा रही है, लेकिन अंतिम निर्णय आने तक सभी नियुक्तियां न्यायालय के आदेश के अधीन होंगी। मामले में याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल और अन्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य की जानी चाहिए। उनका कहना था कि स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था में प्रिंसिपल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसलिए शिक्षकों जैसी पात्रता जरूरी होनी चाहिए। वहीं, पंजाब सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि प्रिंसिपल पद मुख्य रूप से प्रशासनिक जिम्मेदारी वाला होता है। सरकार के अनुसार, टीईटी की अनिवार्यता केवल पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों पर लागू होती है।

बारिश के बीच स्कूल तैयारियों में देरी पर शिक्षकों का रोष

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना

पंजाब में मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने के बाद स्कूलों में बरसात से बचाव और सुरक्षा इंतजामों को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देशों पर सवाल खड़े हो गए हैं। अध्यापक संगठनों ने विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए आरोपलगाया है कि जिन तैयारियों को मार्च और अप्रैल महीने में पूरा किया जाना चाहिए था, उनके लिए अब बारिश के मौसम में गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं और रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं।

अध्यापकों का कहना है कि मानसून शुरू होने के बाद स्कूलों में छतों की सफाई, पानी की टंकियों की देखभाल, भवनों की मरम्मत और अन्य जरूरी काम करवाना मुश्किल हो गया है। उनका आरोप है कि विभाग ने समय रहते बजट और संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए और अब अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए स्कूल प्रबंधन पर जवाबदेही डाली जा रही है।

दरअसल, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को बरसात के मौसम में स्कूल भवनों और विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें स्कूलों की छतों और पानी की पाइपों की सफाई, पानी की टंकियों को साफ रखने, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों में दरारों की मरम्मत करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा स्कूल परिसरों में जलभराव रोकने, बिजली के उपकरणों की जांच करने, खराब और लटकती तारों को ठीक करवाने तथा मच्छरों से बचाव के लिए फॉगिंग करवाने को कहा गया है।

अध्यापकों का तर्क है कि ये सभी कार्य गर्मी के महीनों में आसानी से पूरे किए जा सकते थे। मार्च और अप्रैल में मौसम साफ होने के कारण छतों की सफाई, भवनों की मरम्मत और पानी की टंकियों की देखभाल जैसे काम सुरक्षित तरीके से हो सकते थे। लेकिन अब जब लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में छतों पर चढ़कर काम करवाना जोखिम भरा है।

शिक्षकों ने आरोप लगाया कि विभाग के अधिकारी जमीनी हालात से दूर बैठकर केवल कागजी कार्रवाई पूरी करने में लगे हैं। उनका कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा प्रबंध नहीं किए गए और बारिश के कारण किसी स्कूल में कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग और सरकार की होगी।

अध्यापकों ने यह भी सवाल उठाया कि केवल रिपोर्ट तैयार करने और जानकारी मांगने से स्कूलों की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

देर से जागा विभाग

शिक्षा विभाग के निर्देशों के बाद अब जिला स्तर पर स्कूलों से सुरक्षा इंतजामों की रिपोर्ट मांगी जा रही है। अधिकारियों को व्यवस्थाओं की निगरानी कर कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी होगी।

एक साल से विशेषज्ञ विहीन है लुधियाना सिविल अस्पताल

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना। महानगर के सबसे बड़े सरकारी सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिले के सिविल अस्पताल में पिछले करीब एक वर्ष से नियमित फोरेंसिक मेडिसिन विशेषज्ञों के दोनों पद खाली पड़े हैं। इसके कारण हत्या, आत्महत्या और संदिग्ध मौतों के मामलों में होने वाले पोस्टमार्टम और अदालतों से जुड़े मेडिको-लीगल मामलों की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

◆विशेषज्ञों की भारी कमी

मामले की गंभीरता को देखते हुए यह मुद्दा अब पंजाब मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। आयोग में मामला पहुंचने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल तेज हो गई है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि पंजाब के बड़े और संवेदनशील जिले में इतने लंबे समय तक फोरेंसिक विशेषज्ञों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई।

जानकारी के अनुसार, जिला सिविल अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में पुलिस से जुड़े मामले आते हैं। हत्या, दुर्घटना, आत्महत्या और संदिग्ध मौतों के मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विशेषज्ञ राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। विशेषज्ञों की कमी के कारण अस्पताल को दूसरे संस्थानों की बाहरी डॉक्टरों की सहायता लेनी पड़ रही है। वहीं, दूसरी ओर शहर के कई निजी चिकित्सा संस्थानों में फोरेंसिक विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। डीएमसीएच में चार, सीएमसीएच में तीन और ईएसआई मॉडल अस्पताल में एक फोरेंसिक विशेषज्ञ कार्यरत हैं। इसके बावजूद सरकारी अस्पताल में नियमित विशेषज्ञ नहीं होने से व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार, फोरेंसिक विशेषज्ञ डॉ. चरणकमल को दोराहा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। इसके साथ ही वह चंडीगढ़ में मेडिको-लीगल सेवाओं से जुड़ी जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं।

ब्यास नदी के बढ़ते जलस्तर से किसान चिंतित

भारतेन्दु संवाददाता, टांडा

किसानों ने बाढ़ खतरे को देखते हुए बांध मजबूत करने की मांग की

ब्यास नदी के बढ़ते जलस्तर और लगातार हो रही बारिश के बीच टांडा क्षेत्र के किसानों की चिंता बढ़ गई है। ब्यास मंड में स्थित गांव रड़ा के पास नदी किनारे पहले हुए कटाव से जमीन और बांधों को भारी नुकसान पहुंचा था। अब मानसून के दौरान संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए किसानों ने प्रशासन से नदी किनारे बने बांधों की तत्काल मरम्मत और मजबूती की मांग उठाई है।

किसानों का कहना है कि पिछले दिनों हुई बारिश के कारण नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यदि क्षतिग्रस्त तटबंधों की समय रहते मरम्मत नहीं की गई तो ब्यास नदी का पानी खेतों और गांवों में घुस सकता है। इससे किसानों की फसलों और संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचने की आशंका है।

किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि ब्यास नदी और आसपास के प्रभावित इलाकों का जल्द निरीक्षण करवाया जाए। इसके अलावा जहां-जहां बांध कमजोर हो चुके हैं, वहां तुरंत मरम्मत कार्य शुरू किया जाए। उनका कहना है कि केवल कागजी कार्रवाई से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का जायजा लेना जरूरी है।

किसानों ने बताया कि पिछले साल आई बाढ़ के दौरान ब्यास नदी के दोनों किनारों पर बने कई बांध टूट गए थे। इसके चलते बड़ी मात्रा में पानी खेतों में भर गया था और सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि प्रभावित हुई थी। कई किसानों की तैयार फसलें बर्बाद हो गई थीं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था।

किसानों का कहना है कि पिछले अनुभव को देखते हुए इस बार प्रशासन को पहले से तैयारियां करनी चाहिए। उन्होंने पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से अपील की है कि ब्यास नदी के किनारे बने बांधों को मजबूत करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं।

फाजिल्का में नियम तोड़ने वालों पर ट्रैफिक पुलिस सख्त

भारतेन्दु संवाददाता, फाजिल्का

जिले में ट्रैफिक पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। पुलिस की ओर से शहर के विभिन्न स्थानों पर नाके लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है और नियम तोड़ने वालों के चालान किए जा रहे हैं। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस किसी भी तरह की सिफारिश को नजरअंदाज कर रही है।

जानकारी के अनुसार, लाल बत्ती चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने एक बुलेट मोटरसाइकिल को रोककर जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी और उसका साइलेंसर भी बदला हुआ था। पुलिस ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए चालक का 7 हजार रुपये का चालान काट दिया और उसे रसीद सौंप दी।

ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा नियमों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

ट्रैफिक पुलिस एएसआई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि शहर में कई बुलेट मोटरसाइकिल चालकों द्वारा साइलेंसर में बदलाव कर तेज आवाज और पटाखे जैसी आवाज निकालने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इससे आम लोगों को परेशानी होती है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ता है।

ग्रुप-डी परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थियों का भंडाफोड़

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना

पंजाब में सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में सेंध लगाने वाले एक शातिर गिरोह का खुलासा हुआ है। ग्रुप-डी सरकारी पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में असली उम्मीदवारों की जगह फर्जी परीक्षार्थियों को बैठाकर परीक्षा दिलाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने दो उम्मीदवारों के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश रचने की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, यह मामला लुधियाना के एक परीक्षा केंद्र से जुड़ा है, जहां पंजाब सरकार की ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान दो उम्मीदवारों ने खुद परीक्षा देने के बजाय अपनी जगह अन्य व्यक्तियों को बैठा दिया। इन फर्जी परीक्षार्थियों ने सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश किया और प्रश्न पत्र हल करने लगे। मामले का खुलासा परीक्षा समाप्त होने के बाद दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया के दौरान हुआ। परीक्षा बोर्ड और संबंधित अधिकारियों ने जब उम्मीदवारों के हस्ताक्षर, फोटो और अन्य रिकॉर्ड का मिलान किया तो कई गड़बड़ियां सामने आईं। जांच में पाया गया कि परीक्षा देने वाले व्यक्तियों के चेहरे आवेदन करने वाले वास्तविक उम्मीदवारों से मेल नहीं खा रहे थे।

इसके बाद परीक्षा केंद्र की ओर से मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई। दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। स्कूल के प्रिंसिपल नरेश कुमार की ओर से दी गई लिखित शिकायत के आधार पर थाना दरेसी पुलिस ने उम्मीदवार बिजेंदर और अंकुश के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, यह पूरा मामला सरकारी भर्ती प्रक्रिया में धोखाधड़ी से जुड़ा है। आरोप है कि दोनों उम्मीदवारों ने परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए अपनी जगह फर्जी व्यक्तियों को बैठाया। इसके पीछे आर्थिक लेनदेन की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस गिरोह में कितने लोग शामिल हैं और क्या इससे पहले भी ऐसी किसी परीक्षा में इस तरह की धांधली की गई है।

अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर पहचान जांच, बायोमेट्रिक सत्यापन और दस्तावेजों की जांच जैसी प्रक्रियाओं को मजबूत किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सके।

राजा वड़िंग बोले, हाईकमान का हर फैसला मुझे मंजूर है

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब कांग्रेस में चल रहे अंदरूनी विवाद के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है, वह उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ने या राजनीति छोड़कर खेती करने के लिए भी कहेंगे तो वह उसके लिए तैयार हैं।

राजा वड़िंग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा दिया है। उन्होंने स्वीकार किया कि उनमें कई कमियां हो सकती हैं और पंजाब कांग्रेस में उनसे अधिक योग्य नेता भी मौजूद हैं, लेकिन जब पार्टी नेतृत्व ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है तो वह पूरी निष्ठा के साथ अपना दायित्व निभाएंगे।

उन्होंने कहा कि वह पहले भी पंजाब कांग्रेस की वरिष्ठ नेतृत्व की सलाह और निर्देशों के अनुसार काम करते रहे हैं और आगे भी सभी नेताओं को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। राजा वड़िंग ने कहा कि परिवार में कई बार मतभेद और बहस हो सकती है, लेकिन यदि कोई नेता उनसे व्यक्तिगत रूप से नाराज है तो वह उसे मनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पंजाब की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के लोग मौजूदा सरकार से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब पर बढ़ते कर्ज और कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर जनता चिंतित है।

न्यूज ब्रीफ

पटियाला में परिवार के चार सदस्यों ने निगला जहरीला पदार्थ, दो की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, पटियाला। पंजाब के पटियाला शहर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के चार सदस्यों ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ निगल लिया। इस घटना में परिवार के दो सदस्यों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार, ऑफिसर कॉलोनी निवासी विकास बातिश, उनकी पत्नी तमन्ना बातिश, बेटी खुशी बातिश और बेटे कनव बातिश ने बुधवार रात जहरीला पदार्थ निगल लिया। तबीयत बिगड़ने पर चारों को राजिंदरा अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान विकास और उनकी बेटी खुशी की मौत हो गई। वहीं, पत्नी तमन्ना और बेटा कनव गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। डीएसपी सिटी-1 संजीव सिंगला ने बताया कि शुरुआती जांच में घरेलू लेन-देन विवाद की बात सामने आई है। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाया है और मामले की जांच जारी है। परिजनों व आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।

लुधियाना में थार चालक की गुंडागर्दी

भारतेन्दु संवाददाता,लुधियाना। शहर के हैबोवाल इलाके में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक थार चालक ने आवारा कुत्तों को खाना खिला रहे एनिमल लवर पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और एक कुत्ते को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शिकायतकर्ता परमजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि वह रोजाना गली के आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं। घटना के समय रात करीब 10:30 बजे वह कुत्तों को खाना खिला रहे थे, तभी तेज रफ्तार थार वहां पहुंची। आरोप है कि चालक रविंदर सिंह ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए कुत्ते को कुचल दिया। परमजीत और लोगों ने जब चालक को रोकने की कोशिश की तो आरोप है कि उसने पिस्तौल निकालकर जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। थाना हैबोवाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

न्यूजीलैंड भेजने का झांसा देकर की 3 .57 लाख की ठगी

भारतेन्दु संवाददाता, अमृतसर

विदेश भेजने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने के आरोप में थाना रणजीत एवेन्यू पुलिस ने ट्रैवल एजेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने जर्मन इमीग्रेशन से जुड़े ट्रैवल एजेंट संदीप सिंह चौहान और मुस्कान के खिलाफ शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि दोनों ने एक युवक को न्यूजीलैंड भेजने का भरोसा दिलाकर उसके परिवार से 3.57 लाख रुपये ले लिए, लेकिन न तो उसे विदेश भेजा गया और न ही पैसे वापस किए गए।

पुलिस को दी शिकायत में अमृतसर निवासी चरणजीत सिंह ने बताया कि वह अपने बेटे को विदेश भेजना चाहते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात आरोपियों से हुई। आरोपियों ने खुद को इमीग्रेशन और विदेश भेजने की प्रक्रिया से जुड़ा एजेंट बताते हुए उनके बेटे को न्यूजीलैंड भेजने का दावा किया। उन्होंने वीजा लगवाने, दस्तावेज तैयार करवाने और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने का भरोसा दिया।

चरणजीत सिंह ने बताया कि आरोपियों की बातों पर विश्वास करते हुए उन्होंने अलग-अलग समय में कुल 3.57 लाख रुपये दे दिए। पैसे लेने के बाद आरोपियों ने कुछ समय तक प्रक्रिया चलने और जल्द विदेश भेजने का आश्वासन दिया, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

पीड़ित के अनुसार, जब उन्होंने अपने बेटे को विदेश भेजने या पैसे वापस करने के लिए कहा तो आरोपियों ने टालमटोल शुरू कर दी। कई बार संपर्क करने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। इसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की।

लंबे इंतजार के बाद नंगल क्षेत्र के लोगों की मांग पूरी, अब ट्रेन सुविधा होगी आसान

नंगल डैम स्टेशन पर रुकेगी वंदे भारत एक्सप्रेस

भारतेन्दु संवाददाता, नंगल

वंदे भारत ठहराव से यात्रियों को मिलेगा बड़ा लाभ

नंगल क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। नई दिल्ली-अंब अंदौरा वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव अब नंगल डैम रेलवे स्टेशन पर भी किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष डॉ. सुभाष शर्मा को पत्र भेजकर मंजूरी की जानकारी दी है।

डॉ. सुभाष शर्मा ने बताया कि नंगल क्षेत्र के लोगों की यह लंबे समय से प्रमुख मांग थी कि वंदे भारत एक्सप्रेस को नंगल डैम रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए ठहराव दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन पहले नंगल डैम स्टेशन पर पानी भरने के लिए रुकती थी, लेकिन यात्रियों के चढ़ने और उतरने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

उन्होंने बताया कि नंगल डैम रेलवे स्टेशन का क्षेत्रीय महत्व काफी अधिक है। यहां देश के प्रमुख भाखड़ा बांध, एनएफएल कारखाना और कई औद्योगिक एवं धार्मिक स्थल मौजूद हैं। इसके बावजूद स्थानीय लोगों को वंदे भारत ट्रेन की सुविधा लेने के लिए ऊना या श्री आनंदपुर साहिब जाना पड़ता था, जिससे उन्हें अतिरिक्त परेशानी और समय का सामना करना पड़ता था।

डॉ. सुभाष शर्मा ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को केंद्रीय रेल मंत्री के समक्ष उठाया था और लोगों की मांग को देखते हुए नंगल डैम स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव करने की अपील की थी। उन्होंने बताया कि रेल मंत्रालय ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए गाड़ी संख्या 22447/22448 नई दिल्ली-अंब अंदौरा वंदे भारत एक्सप्रेस के नंगल डैम रेलवे स्टेशन पर ठहराव की मंजूरी दे दी है।

उन्होंने कहा कि जल्द ही यह ट्रेन नंगल डैम स्टेशन पर यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। इससे क्षेत्र के लोगों को दिल्ली और हिमाचल की ओर यात्रा करने में काफी सुविधा मिलेगी। व्यापारियों, विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और धार्मिक यात्रियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। इलाके के लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने से नंगल और आसपास के क्षेत्रों का संपर्क बेहतर होगा। वंदे भारत जैसी तेज रफ्तार ट्रेन का ठहराव मिलने से क्षेत्र के विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

तरनतारन में एसआई नशा तस्करी में गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़।

पंजाब पुलिस ने अपने ही विभाग के एक सब इंस्पेक्टर को नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। मामला सीमावर्ती जिले तरनतारन का है, जहां तैनात एसआई साहिब सिंह के पास से करीब 300 ग्राम हेरोइन और कथित ड्रग मनी बरामद होने का दावा किया गया है। पुलिस के अनुसार, सीआईए स्टाफ को सूचना मिली थी कि एसआई साहिब सिंह कथित तौर पर अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हुए नशा तस्करी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल है। सूचना के आधार पर एसपी (इन्वेस्टिगेशन) रिपुतापन सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।

पुलिस टीम ने जांच के बाद कार्रवाई करते हुए तरनतारन जिले के गांव मजूपुर निवासी साहिब सिंह से जुड़े झबाल क्षेत्र के एक अहाते में छापेमारी की। यहां से हेरोइन और ड्रग मनी बरामद होने की बात कही गई है। पुलिस ने एसआई साहिब सिंह को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है।

हेरोइन तस्करी आरोप में पुलिस मुंशी पर कार्रवाई

भारतेन्दु संवाददाता, फाजिल्का

पंजाब के सीमावर्ती जिला फाजिल्का में पुलिस विभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। जलालाबाद क्षेत्र की पुलिस चौकी घुबाया में तैनात एक मुंशी को हेरोइन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस अधिकारियों ने चौकी प्रभारी और मुंशी दोनों को निलंबित कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई श्री मुक्तसर साहिब पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान की गई। पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध कार को रोककर उसमें सवार लोगों की जांच की। तलाशी लेने पर कार से 280 ग्राम हेरोइन और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद हुई।

पुलिस जांच में सामने आया कि कार में मौजूद लोगों में जलालाबाद क्षेत्र की पुलिस चौकी घुबाया का मुंशी जोगिंदर सिंह भी शामिल था। नशा तस्करी मामले में संलिप्तता पाए जाने के बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।

डीएसपी जलालाबाद गुरसेवक सिंह बराड़ ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान चौकी घुबाया के प्रभारी गुरनाम सिंह की भूमिका पर भी सवाल उठे। पुलिस ने लापरवाही और संदिग्ध भूमिका को देखते हुए चौकी प्रभारी गुरनाम सिंह को भी मामले में नामजद कर लिया है।

अंतर्कलह भाजपा नेता ने कांग्रेस नेतृत्व की कार्यशैली पर उठाए गंभीर सवाल

पंजाब कांग्रेस विवाद पर तरुण चुघ का हमला

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब कांग्रेस में चल रहे अंदरूनी विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने कांग्रेस हाईकमान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी अपने नेताओं और संगठन को संभालने में सक्षम नहीं है, वह पंजाब को कैसे संभाल सकती है।

तरुण चुघ ने कांग्रेस नेतृत्व पर परिवारवाद और केंद्रीकृत कार्यशैली का आरोप लगाते हुए कहा कि गांधी-नेहरू परिवार की नीतियों के कारण पंजाब को लंबे समय से नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पंजाब को अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला बनाकर रखा है और राज्य की भावनाओं की अनदेखी की है।

भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस के अंदर चल रहा विवाद यह दिखाता है कि पार्टी में नेताओं की आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली नेतृत्व पंजाब कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के बजाय अपनी इच्छा थोप रहा है।

तरुण चुघ ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में पंजाब से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सही निर्णय नहीं लिए गए। उन्होंने पानी के मुद्दे, चंडीगढ़ से जुड़े मामलों, 1984 के सिख विरोधी दंगों और राज्य के विकास से जुड़े विषयों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा पंजाब के हितों के खिलाफ काम किया है। भाजपा नेता ने कहा कि वर्तमान समय में भी कांग्रेस में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव की शिकायतें सामने आ रही हैं, खासकर अनुसूचित जाति समाज से जुड़े कार्यकर्ताओं के मुद्दों पर पार्टी की भूमिका सवालों के घेरे में है।

तरुण चुघ ने कहा कि पंजाब कांग्रेस में चल रहे विवाद से यह स्पष्ट हो गया है कि पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर असंतोष है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हाईकमान अपने नेताओं की समस्याओं का समाधान करने में विफल साबित हो रहा है।

गौरतलब है कि पंजाब कांग्रेस में पिछले कुछ समय से संगठन और नेतृत्व को लेकर खींचतान चल रही है। कई नेताओं ने पार्टी के फैसलों और कार्यप्रणाली को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। हालांकि कांग्रेस की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि पार्टी में सभी मुद्दों को बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाएगा।

नए गैस कनेक्शन का रास्ता साफ

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना

पंजाब भर में पिछले कई महीनों से बंद पड़ी घरेलू गैस सेवाएं अब दोबारा शुरू होने जा रही हैं। गैस कंपनियों ने नए घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने, उपभोक्ताओं के नाम ट्रांसफर करने और डबल बॉटल कनेक्शन (डीबीसी) जैसी सेवाओं के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया है। इससे लंबे समय से परेशान उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

जानकारी के अनुसार, पिछले करीब चार महीने से गैस कंपनियों ने नए कनेक्शन जारी करने और पहले से चल रहे गैस कनेक्शन की कॉपी पर नाम ट्रांसफर करने की प्रक्रिया रोक रखी थी। इसके कारण कई परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। खासकर ऐसे मामलों में अधिक दिक्कत आई, जहां परिवार के मुखिया या माता-पिता के निधन के बाद गैस कनेक्शन बच्चों के नाम पर ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था।

गैस कनेक्शन ट्रांसफर नहीं होने के कारण कई परिवारों को सिलेंडर सप्लाई लेने में भी मुश्किलें आ रही थीं। वहीं, नए शादीशुदा जोड़ों को भी नया गैस कनेक्शन लेने और अतिरिक्त सिलेंडर कनेक्शन हासिल करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

अब गैस एजेंसियों ने उपभोक्ताओं से आवेदन और जरूरी दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उपभोक्ता अपने संबंधित गैस एजेंसी कार्यालय में जाकर नए कनेक्शन, नाम ट्रांसफर और अन्य सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।

लुधियाना एलपीजी गैस फेडरेशन के प्रधान मनजीत सिंह ने बताया कि सभी गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद कनेक्शन ट्रांसफर करवाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे।

उन्होंने बताया कि डबल बॉटल कनेक्शन योजना के तहत दूसरा सिलेंडर जारी करने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी तरह शुरू हो जाएगी। इससे उन उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा, जिन्हें लंबे समय से अतिरिक्त सिलेंडर की जरूरत थी।

उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अपनी संबंधित गैस एजेंसी में पहुंचकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करें।

ईमानदार शासन और जागरूक नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत आधारशिला हैं

भारत आज विश्व की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। देश तकनीक, आधारभूत ढांचे, शिक्षा, डिजिटल सेवाओं, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में लगातार प्रगति कर रहा है। सरकार का लक्ष्य विकसित भारत का निर्माण है, अर्थात ऐसा भारत जो आर्थिक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली हो लेकिन इस सपने को साकार करने की राह में यदि कोई सबसे बड़ी बाधा है, तो वह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि यह समाज, व्यवस्था और लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने वाली गंभीर समस्या है।

भ्रष्टाचार का अर्थ है अपने पद, अधिकार या शक्ति का अनुचित लाभ लेकर निजी स्वार्थ की पूर्ति करना। रिश्वतखोरी, भाई-भतीजावाद, घोटाले, सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी, फर्जी बिल, अवैध कमीशन, पद का दुरुपयोग आदि इसके प्रमुख रूप हैं। यह समस्या केवल सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग रूपों में दिखाई देती है।

यदि किसी राष्ट्र को विकसित बनना है तो उसकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए लेकिन भ्रष्टाचार विकास की गति को बाधित करता है। सरकार द्वारा सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, बिजली, रोजगार या कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो धन आवंटित किया जाता है, उसका एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। परिणामस्वरूप योजनाएं कागजों में सफल दिखाई देती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता। इससे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होता है और विकास की प्रि, या कमजोर पड़ जाती है।

शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का असर और भी गंभीर होता है। यदि स्कूलों, अस्पतालों या सार्वजनिक सेवाओं में गुणवत्ता के बजाय पैसे और सिफारिश का महत्व बढ़ जाए, तो समाज की बुनियाद कमजोर हो जाती है। एक विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं अनिवार्य हैं, लेकिन भ्रष्टाचार इन दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करता है।

भ्रष्टाचार निवेश और व्यापारिक माहौल को भी नुकसान पहुंचाता है। जब किसी देश में पारदर्शिता की कमी होती है और काम करवाने के लिए रिश्वत या अनुचित प्रभाव की जरूरत पड़ती है, तो निवेशकों का विश्वास कम होता है। उद्योगों की वृद्धि प्रभावित होती है और रोजगार के अवसर घटते हैं। इससे आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार सामाजिक असमानता को भी बढ़ाता है। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम है या प्रभावशाली है, वह कई बार व्यवस्था का अनुचित लाभ उठा लेता है, जबकि गरीब और सामान्य नागरिक अपने अधिकारों से वंचित रह जाता है। इससे समाज में अन्याय, असंतोष और व्यवस्था के प्रति अविश्वास बढ़ता है। लोकतंत्र की असली ताकत समान अवसर और न्याय में निहित होती है, लेकिन भ्रष्टाचार इस भावना को कमजोर कर देता है।

हालांकि भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सेवाएं, ई-गवर्नेंस, पारदर्शी निविदा प्रणाली, आधार आधारित सेवाएं, जनधन खाते और शिकायत निवारण तंत्र जैसे प्रयासों से कई क्षेत्रों में सुधार देखने को मिला है। तकनीक ने मानवीय हस्तक्षेप को कम कर पारदर्शिता बढ़ाने में मदद की है। फिर भी केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं; समाज की भागीदारी भी आवश्यक है।

केशव शर्मा 'रसिक'
कोटला, घुमारवीं, बिलासपुर

विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार होगा जब भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। इसके लिए, पारदर्शी प्रशासन, मजबूत जवाबदेही, नैतिक शिक्षा और जागरूक नागरिकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध सामूहिक प्रयास ही सुशासन को मजबूत करेंगे और देश को तेज, समावेशी तथा सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाएंगे।

आज आवश्यकता केवल कठोर कानून बनाने की नहीं बल्कि ऐसी सामाजिक चेतना विकसित करने की है जिसमें ईमानदारी को सम्मान और भ्रष्टाचार को सामाजिक अस्वीकार्यता मिले। परिवार विद्यालय और समाज को मिलकर नई पीढ़ी में नैतिक मूल्यों पारदर्शिता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करनी होगी। प्रत्येक नागरिक यदि अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी ईमानदारी से पालन करे तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस दिखाए, तो व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन संभव है। विकसित भारत का सपना केवल आर्थिक प्रगति से पूरा नहीं होगा बल्कि सुशासन जवाबदेही और स्वच्छ प्रशासन से ही साकार होगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत ही आत्मनिर्भर समृद्ध और विश्व में अग्रणी भारत की मजबूत नींव बन सकता है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

क्या भारतीय राजनीति में अब केवल सत्ता ही तय करती है नेताओं की वफादारी ?

पारिवारिक और सामाजिक जीवन में जहां वफादारी सबसे बड़ी पूंजी होती है, वहीं क्या सियासत की दुनिया में वफादारी सबसे सस्ती चीज होती है? आज यह सवाल हर तरफ पूछा जा रहा है। क्या जब तक सत्ता का 'सूरज' चमकता रहता है, दरबार में भीड़ लगी रहती है लेकिन जैसे ही सूरज 'अस्ताचल' होने लगता है, सियासी 'महफिल' में सन्नाटा छा जाता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त ठीक यही हो रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बाद तृणमूल कांग्रेस की बगावत ने पार्टी को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया है। दिल्ली से कोलकाता तक पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मनमानी के खिलाफ पार्टी के 20 लोकसभा सांसदों और 58 से अधिक विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। वैसे यह महज एक पार्टी का संकट नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र के उस गहरे घाव को उजागर करता है, जिसे मौकापरस्ती का नासूर कहते हैं। प. बंगाल में भाजपा ने 45.43 प्रतिशत वोट पाकर सत्ता पर कब्जा किया और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर 7.16 प्रतिशत गिर गया। विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम में ममता बनर्जी की पार्टी को मात्र 80 सीटें मिलीं। ममता बनर्जी के 35 में से 22 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा, यानी करीब 63 प्रतिशत मंत्री चुनाव हार गए। खुद ममता बनर्जी भी अपने पुराने गढ़ भवानीपुर में हार गईं। 15 साल की सत्ता का यह अंत था, लेकिन असली तमाशा इसके बाद शुरू हुआ।

पिछले 14 दिन में ही पांच बड़े नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और अपनी राज्यसभा सीट भी छोड़ दी है। जिस सुखेंदु शेखर राय को ममता का सबसे भरोसेमंद सिपाही माना जाता था, उन्होंने जाते-जाते भाजपा को तारीफ में पत्र लिखा। 14 बागी सांसद भाजपा के राष्ट्रीय रणनीतिकार और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर लंच के लिए जुटे, जहां प. बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। यह लंच महज खाने का नहीं, सियासी पाला बदलने का आयोजन था। बागियों की फेहरिस्त लंबी है।

काकोली घोष दस्तीदार, जगदीश चंद्र बसुनिया, खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान, पार्थ भौमिक, बापी हलदार, सायोनी घोष, माला रॉय, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, जून मालिया, अरूप च, वर्ती और शत्रुघ्न सिन्हा समेत 19 सांसदों के नाम बागी सूची में हैं। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने खुलकर कहा कि भारी भ्रष्टाचार की वजह से पार्टी की हार हुई है। उन्होंने संकेत दिए कि वे एनडीए का समर्थन करेंगी और अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए मौजूदा सरकार के साथ काम करेंगी। टीएमसी में उठी बगावत कोई अपवाद नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की पुरानी प्रवृत्ति का नया अध्याय है। कांग्रेस से लेकर तृणमूल और अन्य दलों तक, सत्ता और पद की राजनीति ने वैचारिक प्रतिबद्धता को अक्सर पीछे छोड़ दिया है। दल-बदल करने वाले अधिकांश नेताओं के फैसलों के पीछे विचारधारा से अधिक राजनीतिक अवसर और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं दिखाई देती हैं।

संजय सक्सेना
राजनीतिक विश्लेषक

विडंबना यह है कि जो नेता कल तक किसी दल और उसके नेतृत्व की प्रशंसा करते थे, वही आज दूसरी पार्टी में जाकर उसके विरोधी बन जाते हैं। एंटी-डिफेक्शन कानून भी इस प्रवृत्ति को पूरी तरह रोक नहीं पाया है। राजनीतिक दलों ने कानून की सीमाओं के भीतर रहकर भी रास्ते निकाल लिए हैं।

बंगाल की मौजूदा स्थिति केवल तृणमूल कांग्रेस की चुनौती नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति का व्यापक सच है। यह घटनाक्रम बताता है कि केवल सत्ता के आधार पर खड़े संगठन लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकते।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

बिखरना विनाश का पथ है तो सिमटना निर्माण का।
-कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर

संपादकीय

भारत-इंडोनेशिया संबंधों का स्वर्णिम दौर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा केवल एक सामान्य राजनयिक कार्यक्रम नहीं थी बल्कि यह भारत की बदलती वैश्विक भूमिका और बढ़ती रणनीतिक क्षमता का स्पष्ट संकेत है। वर्तमान समय में जब विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र वैश्विक राजनीति, व्यापार और सुरक्षा का प्रमुख केंद्र बन चुका है, तब भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत होती साझेदारी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस यात्रा के दौरान रक्षा, व्यापार, तकनीक, शिक्षा, कृषि, संस्कृति और समुद्री सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुए समझौते दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा देने वाले साबित हो सकते हैं। लगभग 20 महत्वपूर्ण समझौतों और पहलों पर सहमति बनना इस बात का प्रमाण है कि दोनों देश अब अपने संबंधों को केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव तक सीमित नहीं रखना चाहते बल्कि उन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलना चाहते हैं। भारत और इंडोनेशिया के संबंध सदियों पुराने हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक संबंधों का इतिहास काफी पुराना रहा है। रामायण और महाभारत जैसी भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का प्रभाव इंडोनेशिया के सामाजिक जीवन में भी दिखाई देता है। लेकिन आज के दौर में दोनों देशों के रिश्तों का महत्व केवल सांस्कृतिक जुड़ाव तक सीमित नहीं है। दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री शक्तियां हैं और वैश्विक आपूर्ति शृंखला, ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार में इनकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को नई मजबूती प्रदान की है।

इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रक्षा क्षेत्र में हुआ सहयोग रहा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए हुआ समझौता भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और बढ़ती निर्यात क्षमता का बड़ा उदाहरण है। भारत लंबे समय तक रक्षा उपकरणों का प्रमुख आयातक देश रहा है, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। स्वदेशी तकनीक और अनुसंधान के आधार पर भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्रह्मोस जैसी अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली में अन्य देशों की रुचि भारत की तकनीकी क्षमता और सामरिक विश्वसनीयता को दर्शाती है। इंडोनेशिया द्वारा इस मिसाइल प्रणाली को अपनाने का निर्णय दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे का प्रतीक है। रक्षा सहयोग केवल हथियारों की खरीद तक सीमित नहीं है बल्कि यह दोनों देशों के बीच सामरिक समझ और सुरक्षा साझेदारी को भी मजबूत करता है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बदलते सुरक्षा समीकरणों के बीच भारत और इंडोनेशिया का सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। दोनों देश समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और रक्षा प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा सकते हैं। इससे न केवल दोनों देशों की सुरक्षा क्षमताएं मजबूत होंगी बल्कि क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी।

समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते भी इस यात्रा की बड़ी उपलब्धियों में शामिल हैं। हिंद महासागर और मलक्का जलडमरूमध्य विश्व व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में गिने जाते हैं। दुनिया की बड़ी मात्रा में ऊर्जा और व्यापारिक वस्तुओं का परिवहन इन्हीं समुद्री मार्गों से होता है। ऐसे में इन क्षेत्रों की सुरक्षा और स्थिरता वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है। इंडोनेशिया के सबंग बंदरगाह के विकास में सहयोग तथा भारत के सूचना समन्वय केंद्र में इंडोनेशिया के संपर्क अधिकारी की नियुक्ति समुद्री निगरानी और सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करेगी। इससे समुद्री अपराधों, अवैध गतिविधियों और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में दोनों देशों को बेहतर सहयोग मिलेगा। आर्थिक क्षेत्र में भी यह यात्रा महत्वपूर्ण रही। वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव के बीच महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ धातुओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक वाहन, हरित ऊर्जा और आधुनिक तकनीक के विकास के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। भारत और इंडोनेशिया के बीच इस क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों को वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद करेगा। इसी प्रकार स्टील उत्पादन के क्षेत्र में सेल और क्राकाटाउ स्टील के बीच सहयोग औद्योगिक साझेदारी का नया उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह सहयोग दोनों देशों के उद्योगों को नई संभावनाएं प्रदान कर सकता है और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि कर सकता है।

डिजिटल क्षेत्र में सहयोग भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता को दर्शाता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान और डिजिटल सार्वजनिक ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यूपीआई जैसी प्रणाली ने देश में वित्तीय लेनदेन को आसान और तेज बनाया है। इंडोनेशिया के साथ डिजिटल भुगतान प्रणाली को जोड़ने की पहल दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई दे सकती है। इसके अलावा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जैसी अवधारणाओं पर आधारित सहयोग डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने में सहायक होगा। यह भारत की डिजिटल नवाचार क्षमता को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का अवसर भी है। शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में सहयोग भी इस साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आईआईएम बेंगलुरु का इंडोनेशिया में विदेशी परिसर स्थापित करना भारतीय शिक्षा की वैश्विक पहचान को मजबूत करने वाला कदम है। इससे दोनों देशों के छात्रों और शिक्षाविदों को नए अवसर मिलेंगे। उच्च शिक्षा, शोध और प्रबंधन प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच ज्ञान आधारित साझेदारी को मजबूत करेगा। शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं बल्कि देशों के बीच दीर्घकालिक संबंधों की नींव भी होती है।

-शिवांश धाकड़

गंगा को निर्मल बनाने की दिशा में गंगा प्रहरी अभियान समाज के साझा प्रयासों का मजबूत आधार

गंगा केवल एक नदी नहीं है बल्कि यह भारत की संस्कृति सभ्यता और पारिस्थितिकी का आधार है। हिमालय की गोद से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने वाली गंगा करोड़ों लोगों की आस्था आजीविका और जीवन का प्रमुख स्रोत है। भारतीय परंपरा में गंगा को मां का दर्जा दिया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गंगा का धरती पर अवतरण मानव कल्याण और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए हुआ था। सदियों से यह नदी भारतीय जनमानस की आस्था और जीवन दर्शन का अभिन्न हिस्सा रही है।

डॉ. रुचि बड़ोला, डीन
भारतीय वन्यजीव संस्थान
पीआई, गंगा एवं जैव विविधता संरक्षण परियोजना

उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा करते हुए विभिन्न राज्यों से होकर गुजरती है। यह नदी गांवों शहरों और कस्बों को जल उपलब्ध कराने के साथ ही कृषि और उद्योगों के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गंगा बेसिन देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में शामिल है। गंगा का जल लाखों किसानों के खेतों तक पहुंचता है और देश की खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है। इसके किनारे बसे कई ऐतिहासिक और धार्मिक नगर भारतीय सभ्यता के विकास के साक्षी रहे हैं। गंगा नदी का महत्व केवल सामाजिक और आर्थिक नहीं है बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगा बेसिन जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है। यहां कई दुर्लभ जलीय और स्थलीय जीव पाए जाते हैं। गंगा डॉल्फिन इस नदी की सबसे प्रमुख प्रजातियों में शामिल है। इसके अलावा घड़ियाल कछुओं की विभिन्न प्रजातियां मगरमच्छ और अनेक प्रकार के पक्षी गंगा के पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध बनाते हैं। इन जीवों की मौजूदगी नदी के स्वस्थ पर्यावरण का संकेत मानी जाती है।

हालांकि पिछले कुछ दशकों में औद्योगिक प्रदूषण बढ़ती आबादी कचरा प्रबंधन की कमी और मानव गतिविधियों के कारण गंगा की स्वच्छता और जैव विविधता पर गंभीर खतरे मंडराने लगे हैं। कई स्थानों पर नालों का गंदा पानी नदी में पहुंच रहा है। नदी किनारे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से भी जल गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।

इसके कारण कई जलीय प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट पैदा हो गया है।

गंगा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस अभियान का उद्देश्य गंगा को स्वच्छ निर्मल और अविरल बनाना है। इसके अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण घाटों की सफाई नदी किनारों के संरक्षण और जैव विविधता बचाने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। गंगा डॉल्फिन सहित अन्य संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

गंगा संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं है बल्कि इसमें समाज की भागीदारी भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का समूह तैयार किया है जिन्हें गंगा प्रहरी नाम दिया गया है। गंगा प्रहरी गंगा संरक्षण में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

गंगा प्रहरियों का मुख्य उद्देश्य नदी को अविरल और निर्मल बनाए रखने के साथ जलजीवों का संरक्षण करना है। ये प्रहरी नदी की गुणवत्ता पर नजर रखते हैं और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को रोकने में सहयोग करते हैं। अवैध शिकार और नदी में कचरा डालने जैसी गतिविधियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी संकट में फंसे जलीय जीवों की सुरक्षा वन विभाग और बचाव केंद्रों तक पहुंचाने का काम भी गंगा प्रहरी करते हैं।

गंगा प्रहरी केवल संरक्षण कार्यों तक सीमित नहीं हैं बल्कि वे घाटों की सफाई वृक्षारोपण अभियान और जनजागरूकता कार्यक्रमों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। वे स्थानीय लोगों को गंगा की महत्ता और स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हैं। उनके प्रयासों से नदी संरक्षण को एक सामाजिक आंदोलन का स्वरूप मिल रहा है।

भारतीय वन्यजीव संस्थान और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा किनारे रहने वाले समुदायों की आजीविका मजबूत करने के लिए भी कई पहल की हैं। इसके तहत जलज मॉडल तैयार किया गया है जिसके माध्यम से गंगा प्रहरियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि स्थानीय लोग नदी संरक्षण के साथ आर्थिक रूप से भी मजबूत बन सकें।

(ये लेखिका के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

परिश्रम की मिसाल हैं नीतू चंद्रा

नीतू चंद्रा

नीतू चंद्रा का जन्म 10 जुलाई 1984 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पटना में प्राप्त की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली का रुख किया। बचपन से ही उन्हें खेल और कला दोनों में गहरी रुचि थी। यही कारण है कि उन्होंने अभिनय के साथ-साथ खेल के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं। नीतू चंद्रा अंतरराष्ट्रीय स्तर की ताइक्वांडो खिलाड़ी रही हैं और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिचय दिया है। खेलों में उनकी अनुशासनप्रियता और मेहनत ने उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाया तथा यही गुण उनके अभिनय जीवन में भी दिखाई देते हैं।

नीतू चंद्रा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 2005 में प्रदर्शित हिंदी फिल्म गरम मसाला से की। इसके बाद उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में विविध प्रकार की भूमिकाएं निभाकर अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने केवल हिंदी सिनेमा तक ही स्वयं को सीमित नहीं रखा बल्कि तमिल तेलुगु कन्नड़ और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया।

कविता

हरे पत्ते

सुभाष चंद कश्यप, टीजीटी (हिंदी)
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, लड़ा, जिला चंबा

हरे-हरे ये प्यारे पत्ते, लगते जैसे सपने सच्चे।
डाली-डाली झूम रहे हैं, धरती के ये सुंदर बच्चे।
सुबह-सुबह जब ओस नहाए, मोती जैसी चमक दिखाएं।
मंद पवन के संग लहराकर, मन में नई उमंग जगाएं।
धूप सुनहरी जब मुस्काए, इन पर रंग अनोखे छाए।
हरियाली का संदेशा लेकर, जीवन की खुशियां बरसाए।
पक्षी इनकी छांव में गाएं, राहगीरों को सुख पहुंचाएं।
शुद्ध हवा का उपहार देकर, सबका जीवन महकाएं।
हरे पत्ते कहते हमसे, पेड़ों का सम्मान करो।
धरती मां की हरियाली को, मिलकर और महान करो।
आओ हम सब वृक्ष लगाएं, हर आंगन हरियाली लाएं।
हरे पत्तों की मुस्कानों से, सुंदर अपना देश बनाएं।

मेहनत से आत्मनिर्भर भारत को नई दिशा दे रहे मत्स्य किसान

हर वर्ष 10 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस देश के लाखों मत्स्य किसानों और मत्स्य पालन से जुड़े लोगों के योगदान को सम्मान देने के लिए समर्पित है। भारत कृषि प्रधान देश है और यहां खेती के साथ-साथ पशुपालन तथा मत्स्य पालन भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार हैं। आज मत्स्य पालन केवल पारंपरिक आजीविका का साधन नहीं रह गया है बल्कि यह रोजगार सृजन आय वृद्धि पोषण सुरक्षा और निर्यात बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन चुका है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का उद्देश्य मत्स्य पालन के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना नई तकनीकों को बढ़ावा देना तथा मत्स्य किसानों को आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से जोड़ना है।

डॉ. प्रियंका सौरभ
स्वतंत्र टिप्पणीकार

राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का विशेष महत्व वर्ष 1957 की उस ऐतिहासिक उपलब्धि से जुड़ा है जब भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रमुख भारतीय कार्प मछलियों का कृत्रिम प्रजनन सफलतापूर्वक कराया था। इस उपलब्धि ने देश में मत्स्य उत्पादन की दिशा बदल दी। इससे पहले मछली उत्पादन पूरी तरह प्राकृतिक प्रजनन पर निर्भर था जिसके कारण उत्पादन सीमित रहता था। कृत्रिम प्रजनन तकनीक के सफल विकास के बाद बड़ी संख्या में गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज तैयार किए जाने लगे जिससे मत्स्य पालन को नई गति मिली। इसी उपलब्धि की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है।

भारत विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादक देशों में शामिल है। देश में समुद्री और मीठे पानी दोनों प्रकार के मत्स्य संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। लंबा समुद्री तट विशाल नदियां झीलें जलाशय तालाब और कृत्रिम जल स्रोत मत्स्य पालन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत का मत्स्य उत्पादन लगातार बढ़ा है और देश वैश्विक स्तर पर मत्स्य उत्पादन तथा जलीय कृषि के क्षेत्र में अग्रणी देशों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। इससे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है।

मत्स्य पालन का महत्व केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि पोषण सुरक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मछली उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन ओमेगा तीन फैटी एसिड विटामिन और कई आवश्यक खनिजों का समृद्ध स्रोत है। संतुलित आहार में मछली का विशेष स्थान माना जाता है। बच्चों महिलाओं और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए भी मछली उपयोगी खाद्य पदार्थ है। इसलिए मत्स्य उत्पादन बढ़ाने का सीधा संबंध देश की पोषण सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। सीमांत और छोटे किसान खेती के साथ तालाबों में मछली पालन करके अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। कई राज्यों में धान की खेती के साथ मत्स्य पालन की मिश्रित पद्धति भी अपनाई जा रही है जिससे भूमि और जल संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो रहा है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह भी मत्स्य पालन से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल रही है।

सरकार भी मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। आधुनिक मत्स्य पालन को बढ़ावा देने वाले जलाशयों के विकास गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज उपलब्ध कराने मत्स्य किसानों को प्रशिक्षण देने तथा आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का उद्देश्य

मत्स्य उत्पादन बढ़ाना मत्स्य अवसंरचना का विकास करना निर्यात को प्रोत्साहित करना और मत्स्य किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। इसके माध्यम से मत्स्य पालन को संगठित और तकनीक आधारित व्यवसाय बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

आज आधुनिक तकनीकों के उपयोग से मत्स्य पालन पहले की तुलना में अधिक लाभकारी बन गया है। बेहतर गुणवत्ता वाले मत्स्य बीज संतुलित आहार जल गुणवत्ता प्रबंधन रोग नियंत्रण और वैज्ञानिक पालन पद्धतियों ने उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। बायोफ्लॉक प्रणाली पुनर्चक्रण आधारित जलीय कृषि प्रणाली और पिंजरा मत्स्य पालन जैसी आधुनिक तकनीकों ने सीमित संसाधनों में भी अधिक उत्पादन संभव बनाया है। डिजिटल तकनीकों की मदद से मत्स्य किसान मौसम बाजार और उत्पादन संबंधी जानकारी भी आसानी से प्राप्त कर रहे हैं।

भारत के कई राज्यों में मत्स्य पालन आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल ओडिशा गुजरात केरल तमिलनाडु असम बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर मत्स्य उत्पादन किया जाता है। इन राज्यों ने वैज्ञानिक मत्स्य पालन अपनाकर उत्पादन और आय दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि की है। पहाड़ी राज्यों में भी ट्राउट जैसी ठंडे पानी की मछलियों का पालन तेजी से बढ़ रहा है जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।

मत्स्य क्षेत्र देश के निर्यात में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारतीय समुद्री उत्पादों की विश्व के अनेक देशों में मांग है। झींगा सहित कई समुद्री उत्पाद विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्रसंस्करण और कोल्ड चेन व्यवस्था को मजबूत बनाकर भारत अपने मत्स्य निर्यात को और अधिक बढ़ा सकता है। इससे किसानों की आय के साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलता है।

हालांकि मत्स्य क्षेत्र के सामने कई चुनौतियां भी मौजूद हैं। जल प्रदूषण जलवायु परिवर्तन अत्यधिक मत्स्य दोहन रोगों का प्रकोप और प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण उत्पादन को प्रभावित करते हैं।

(ये लेखिका के निजी विचार हैं)

'भारतेन्दु शिखर

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

सांसद राजीव राय का नाम देश के 25 उत्कृष्ट सांसदों में शामिल

एजेंसी, मऊ

उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से सांसद राजीव राय को देश के 25 उत्कृष्ट लोकसभा सांसदों की सूची में स्थान मिला है। प्रतिष्ठित पत्रिका फेम इंडिया और सर्वे एजेंसी एशिया पोस्ट की ओर से कराए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण में उन्हें यह उपलब्धि हासिल हुई है। सर्वेक्षण की अंतिम सूची 8 जुलाई 2026 को जारी की गई, जिसमें देशभर के सांसदों का विभिन्न मानकों पर मूल्यांकन किया गया।

सर्वेक्षण में सांसदों के संसदीय प्रदर्शन, सदन में सक्रिय भागीदारी, जनहित के मुद्दों को उठाने की क्षमता, क्षेत्रीय विकास कार्यों, जनता से संवाद, सांसद निधि के उपयोग, सार्वजनिक छवि, नवाचार और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता जैसे पहलुओं को आधार बनाया गया।

फेम इंडिया और एशिया पोस्ट की ओर से बताया गया कि यह सर्वेक्षण कई चरणों में वैज्ञानिक और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत पूरा किया गया। शुरुआती चरण में करीब 100 सांसदों का चयन किया गया था। इसके बाद आम जनता की राय, विशेषज्ञों के विश्लेषण और विभिन्न मानकों के आधार पर अंतिम 25 उत्कृष्ट सांसदों का चयन किया गया।

राजीव राय को उनके जनसंपर्क, क्षेत्रीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाने और प्रभावी संसदीय भूमिका निभाने के लिए इस सूची में शामिल किया गया है। उनकी इस उपलब्धि को घोसी संसदीय क्षेत्र और समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सांसद के समर्थकों और क्षेत्र के लोगों ने इस सम्मान पर खुशी जताई है। लोगों का कहना है कि राजीव राय लगातार जनता के मुद्दों को संसद और सार्वजनिक मंचों पर उठाते रहे हैं। उन्होंने घोसी क्षेत्र की समस्याओं, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े विषयों को प्राथमिकता दी है।

अखिलेश यादव की राम मंदिर विवाद में सीडीआर जांच की मांग से गरमाई सियासत

सपा अध्यक्ष ने मंदिर परिसर में कार्यरत लोगों की कॉल डिटेल जांच कराने की मांग करते हुए भाजपा पर साधा निशाना

एजेंसी, लखनऊ

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या स्थित राम मंदिर परिसर में काम करने वाले सभी लोगों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि यदि मंदिर परिसर में कार्यरत लोगों की सीडीआर जांच कराई जाए तो बड़ी संख्या में लोगों के राजनीतिक संबंध सामने आ सकते हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि इनमें से 99.9 प्रतिशत लोगों के संबंध भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पाए जाएंगे।

सपा प्रमुख ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी चुनावी लाभ को धार्मिक मूल्यों से ऊपर रख रही है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब हर घर में चर्चा का विषय बन चुका है। इस मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

अखिलेश यादव ने कहा कि मंदिर परिसर में काम करने वाले सभी लोगों की कॉल डिटेल की जांच होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि जांच होने पर भाजपा के भीतर बड़ा राजनीतिक असर देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी में पहले से ही कई लोग असंतुष्ट हैं और कुछ नेता संपर्क में भी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह राजनीतिक फायदे के लिए अपनी विचारधारा और मुद्दों में बदलाव

करती रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए धर्म और आस्था से ज्यादा राजनीति महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन लोगों को मंदिर से जुड़ी जिम्मेदारियां दी गई थीं, वे अब सामने क्यों नहीं आ रहे हैं।

अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के विवाद पर चिंता जताते हुए कहा कि इस घटना से देश और दुनिया के सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजा जाता है और उनके आदर्शों का सम्मान किया जाना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि भक्तों द्वारा श्रद्धा से दिए गए दान और चढ़ावे के प्रबंधन में गड़बड़ी हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर चढ़ावे की सुरक्षा और पारदर्शिता बेहद जरूरी है, क्योंकि यह करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है।

सपा अध्यक्ष ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल किया कि आरोप लगाए जाने के बावजूद भाजपा सांसद के खिलाफ कोई प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं की गई। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती।

न्यूज ब्रीफ

पौधरोपण अभियान को गति देने के लिए हरित पंचायत बनाने की पहल शुरू

एजेंसी, उरई। जनपद में हरित वातावरण तैयार करने और बड़े स्तर पर पौधरोपण अभियान को गति देने के लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि पौधरोपण केवल सरकारी कार्यक्रम तक सीमित न रहे, बल्कि इसे जनभागीदारी के साथ जनआंदोलन का रूप दिया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि खाली पड़े गौशाला परिसरों में बड़े पैमाने पर पौधरोपण कराया जाए और उन्हें हरित क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि पौधरोपण की तैयारियां समय से पूरी की जाएं और संरक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित कर ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण और 'मेरी पंचायत-हरित पंचायत' अभियान के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक पंचायत अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पौधरोपण का लक्ष्य तय करे और अभियान की नियमित निगरानी की जाए। बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहे।

राहुल गांधी मामले में सुनवाई टली, 24 जुलाई तय

एजेंसी, वाराणसी। अमेरिका के बोस्टन स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान श्रीराम को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल अर्जी पर गुरुवार को होने वाली सुनवाई टल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी और अनुज यादव ने वकालतनामा दाखिल किया और पक्ष रखने के लिए समय मांगा। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 24 जुलाई 2026 तय कर दी। मामले में अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने याचिका दाखिल की थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने 21 अप्रैल 2025 को ब्राउन यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भगवान श्रीराम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। याचिका में धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले निचली अदालत ने अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई थी।

सड़क के भ्रम में तालाब में डूबा तहसील कर्मी

एजेंसी, बिजनौर। जनपद के थाना मंडावर क्षेत्र के गोपालपुर गांव में बारिश के कारण हुए जलभराव ने एक बड़ा हादसा कर दिया। सड़क और तालाब में अंतर न समझ पाने के कारण तहसील का संविदा कर्मी गहरे पानी में चला गया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार बुधवार रात हुई भारी बारिश के बाद गांव की गलियां और सड़कें पानी से भर गई थीं। जलभराव के कारण सड़क और तालाब एक जैसे दिखाई दे रहे थे। गुरुवार सुबह अशोक कुमार (50), पुत्र शेर सिंह, पानी पार करते समय अचानक गहरे तालाब में गिर गए। ग्रामीणों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना मिलने पर बालावाली चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई। तहसीलदार सदर आशीष सक्सेना ने बताया कि खोज अभियान जारी है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है।

रोस्टिंग से सूखी नहरें, धान रोपाई संकट में किसान

एजेंसी, फतेहपुर। फतेहपुर जिले में धान रोपाई के समय नहरों में 15-15 दिन की रोस्टिंग लागू होने से हजारों किसानों की परेशानी बढ़ गई है। सुजानपुर रजबहा समेत कई माइनरों में पानी न आने से खेत तैयार होने के बावजूद किसान रोपाई नहीं कर पा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग ने बिना पूर्व सूचना के पानी बंद कर दिया, जिससे धान की बेड़ सूखने लगी है। किसानों का कहना है कि नहरों की समय पर सफाई भी नहीं हुई, जिसके कारण पानी का प्रवाह पहले से प्रभावित है। भाकियू नेताओं ने चेतावनी दी है कि जल्द पानी नहीं छोड़ा गया तो आंदोलन किया जाएगा। किसानों ने नहर में तत्काल पानी छोड़ने और सफाई कराने की मांग की है। नहर विभाग के अवर अभियंता विकास सिंह ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर रोस्टिंग व्यवस्था के अनुसार जलापूर्ति की जा रही है। किसानों ने कहा कि धान की समय पर रोपाई नहीं होने से उत्पादन प्रभावित होने का खतरा है। उन्होंने प्रशासन से हस्तक्षेप कर सिंचाई व्यवस्था सुचारु कराने और किसानों की समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है।

भदोही में क्रिकेट खेलने के दौरान खूनी विवाद एक छात्र ने दूसरे पर बैट से किया हमला, मौत

एजेंसी, भदोही

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में क्रिकेट खेलते समय हुआ मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि एक किशोर की जान चली गई। देर शाम गांव के बच्चे खेल के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान नो बॉल को लेकर शुरू हुई कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि एक किशोर ने गुस्से में दूसरे किशोर पर बल्ले से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

घटना दुर्गागंज थाना क्षेत्र के भानीपुर गांव स्थित अंबेडकर पार्क की है। जानकारी के अनुसार, गांव के कुछ बच्चे वहां बैट-बॉल खेल रहे थे। खेल के दौरान नो बॉल को लेकर बच्चों के बीच विवाद शुरू हो गया। पहले दोनों पक्षों में बहस हुई और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट की स्थिति बन गई। आरोप है कि गांव के ही 15 वर्षीय किशोर ने गुस्से में बल्ले से आदित्य नामक किशोर के सिर पर वार कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने के बाद आदित्य को परिजन घर ले गए। उन्होंने उसका प्राथमिक उपचार कराया और दवा भी दिलाई, लेकिन रात में अचानक उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बताया जा रहा है कि मृतक आदित्य अपने परिवार का इकलौता बेटा था। उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। बेटे की मौत के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। गांव में भी इस घटना को लेकर शोक का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही दुर्गागंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी किशोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार पूरे मामले की जांच की जा रही है और घटनाक्रम से जुड़े सभी तथ्यों को खंगाला जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

भदोही के भानीपुर गांव में क्रिकेट खेलते समय हुए विवाद ने पूरे गांव को झकझोर दिया। मामूली बात को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। बल्ले से किए गए हमले में घायल आदित्य की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना के बाद गांव में शोक और तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने आरोपी किशोर को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नोएडा कार सवार तीन बदमाशों ने युवक से मोबाइल फोन छीनकर खाते से 1.56 लाख रुपए निकाले

एजेंसी, नोएडा। थाना सेक्टर-113 क्षेत्र के सेक्टर-72 के पास कार सवार तीन बदमाशों ने एक युवक से मोबाइल फोन छीन लिया और उसके बैंक खाते से 1.56 लाख रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को आशंका है कि वारदात को सोशल मीडिया या वेबसाइट के जरिए दोस्ती कर लोगों को जाल में फंसाने वाले गिरोह ने अंजाम दिया है।

जानकारी के अनुसार, पीड़ित नितेश सिंह पुत्र अनिल सिंह मूल रूप से प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और वर्तमान में नोएडा में रहते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह बीती रात सेक्टर-72 के पास खड़े थे। इसी दौरान एक कार में सवार होकर तीन युवक वहां पहुंचे और उनसे बातचीत करने लगे। आरोप है कि बातचीत के दौरान बदमाशों ने उन्हें अपने झांसे में लिया और उनका मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया।

पीड़ित के अनुसार, बदमाशों ने मोबाइल फोन के माध्यम से उनके बैंक खाते से 1.56 लाख रुपये किसी अन्य व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दिए। जब उन्होंने अपना मोबाइल वापस मांगा तो आरोपियों ने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की। इसके बाद बदमाश मोबाइल फोन लेकर कार से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। थाना सेक्टर-113 के प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस आसपास लगे

◆ एक बातचीत ने खाली कर दिया खाता नोएडा में लूट का नया तरीका

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह वारदात ऐसे गिरोह से जुड़ी हो सकती है, जो ऑनलाइन माध्यमों से दोस्ती कर लोगों को अपने जाल में फंसाकर लूटपाट करता है। पुलिस का कहना है कि मामले में अहम सुराग मिले हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की तलाश के लिए अलग-अलग टीमों को लगाया गया है। घटना में इस्तेमाल की गई कार और बदमाशों की पहचान के लिए तकनीकी साक्ष्यों की मदद ली जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

महिलाओं के लिए थाना न्याय की पहली उम्मीद, पुलिस संवेदनशीलता के साथ करे कार्य : विजया रहाटकर

एजेंसी, कानपुर

महिलाओं की सुरक्षा केवल पुलिस विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। हालांकि किसी भी पीड़ित महिला के लिए थाना न्याय की पहली उम्मीद होता है। इसलिए पुलिस को कानून का पालन कराने के साथ-साथ संवेदनशील और मानवीय व्यवहार भी अपनाना चाहिए। यह बात राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने गुरुवार को कानपुर में आयोजित दो दिवसीय 'एडवांस जेंडर सेंसिटिव पुलिसिंग' कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर कही।

कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से सिविल लाइंस स्थित नागेंद्र स्वरूप ऑडिटोरियम में 'शक्ति और सुरक्षा' विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर मुख्य अतिथि रहीं, जबकि उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल और डब्ल्यूसीएसए के आईजी सुभाष चंद्र द्विवेदी ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में 'कंपैशनेट कॉप : शक्ति और सुरक्षा' पुस्तक का विमोचन भी किया गया। कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के 17 जिलों से आए पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

◆ महिला मामलों में पुलिस का व्यवहार तय करेगा भरोसे की नींव : महिला आयोग

इससे पहले इस श्रृंखला की पहली कार्यशाला नौ और 10 जून को गाजियाबाद में आयोजित की गई थी।

विजया रहाटकर ने कहा कि महिला संबंधी मामलों में पुलिस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। कई बार राष्ट्रीय महिला आयोग के पास ऐसी शिकायतें आती हैं, जिनमें महिलाओं को थानों में लंबे समय तक बैठाकर रखने की बात सामने आती है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से अपील की कि ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और पीड़ित महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा कि पति-पत्नी के विवादों में पुलिस को धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए।

'स्कूल चलो' अभियान की रैली को राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव व डीएम ने दिखाई हरी झंडी

एजेंसी, जौनपुर

नए शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए जिले में गुरुवार को स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ जागरूकता रैली के साथ किया गया। अभियान का उद्देश्य जिले के सभी बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना और परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव और जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन ने डायट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया।

रैली में बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र-छात्राएं और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल हुए। विद्यार्थियों ने हाथों में शिक्षा जागरूकता से जुड़े संदेश लिखी तख्तियां लेकर लोगों को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक किया। बच्चों ने 'सब पढ़ें, सब बढ़ें', 'आधी रोटी खाएंगे, स्कूल जरूर जाएंगे' और 'हर बच्चा स्कूल में' जैसे नारों के माध्यम से अभिभावकों से अपने बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराने की अपील की।

जागरूकता रैली में बैंड-बाजा, सजे हुए रथ, घोड़े और शिक्षा प्रेरक गीतों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। रैली डायट परिसर से शुरू होकर चहारसू चौराहा, सद्भावना मोड़, शाही किला, अटाला मस्जिद और कोतवाली चौराहा होते हुए टाउन हॉल मैदान पहुंचकर समाप्त हुई। इस अवसर पर राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि प्रत्येक बच्चे का विद्यालय में नामांकन कराना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विद्यार्थियों से नियमित रूप से स्कूल आने और पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील की।

उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर कुमार ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप अभियान शुरू किया गया है। अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत राज्यमंत्री द्वारा 10 बच्चों का नामांकन भी कराया गया।

उत्तर प्रदेश में लागू होगा वक्फ संशोधन कानून : दानिश अंसारी

एजेंसी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा है कि प्रदेश में भी वक्फ संशोधन कानून लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में वक्फ संशोधन कानून लागू होने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में नियमों, कानूनों और उपनियमों के अनुसार इस कानून को लागू किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों के बेहतर रखरखाव और पारदर्शी व्यवस्था के उद्देश्य से वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 लेकर आई है। इसके माध्यम से कई सकारात्मक बदलाव किए गए हैं, जिनका असर वक्फ बोर्ड के कामकाज में दिखाई देगा। उन्होंने बताया कि नए वक्फ बोर्ड के गठन में पिछड़े पसमांदा मुसलमानों, महिलाओं और समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान दानिश अंसारी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रावधानों के तहत सभी राज्यों में बोर्ड का गठन प्रस्तावित है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता बढ़ाना है। कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले पर उन्होंने कहा कि विपक्ष को देश के विकास से जुड़ी योजनाओं को लेकर सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया।

विकास | नए उपकेंद्र से चार हजार उपभोक्ताओं को मिलेगी बेहतर बिजली आपूर्ति

मऊ में नए उपकेंद्र से सुधरेगी बिजली व्यवस्था

एजेंसी, मऊ

जनपद में बिजली व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने बंधा रोड स्थित प्रस्तावित 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र का विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। करीब 530 लाख रुपये की लागत से बनने वाले इस उपकेंद्र से शहर और आसपास के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण, निर्बाध और बेहतर बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेशभर में विद्युत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। नए उपकेंद्रों का निर्माण कर बिजली वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी और

उपभोक्ता केंद्रित बनाया जा रहा है।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बंधा रोड पर बनने वाले नए 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र की क्षमता 5+5 एमवीए होगी। इसके अंतर्गत चार नए 11 केवी फीडरों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद क्षेत्र के करीब चार हजार बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

उन्होंने बताया कि नए उपकेंद्र से पटन टोला, व्यारी टोला, संस्कृत पाठशाला, हरिकेशपुरा, सदर चौक, मलिक टोला, हट्टी मदारी, औरंगाबाद, हनुमान घाट, ऑफिसर्स कॉलोनी, रेलवे क्वार्टर, गायघाट, खालसा, ख्वाजाजहांपुर और कागजीवनचक सहित कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार आएगा।

मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में बिजली वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीक और मजबूत आधारभूत ढांचे की आवश्यकता है। नए उपकेंद्र के शुरू होने के बाद 11 केवी विद्युत लाइनों की लंबाई कम होगी, जिससे तकनीकी हानियों में कमी आएगी। इसके अलावा ओवरलोडिंग, लो-वोल्टेज और बार-बार होने वाले फॉल्ट जैसी समस्याओं से भी उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति में सुधार होने से घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यापारिक और अन्य संस्थानों को भी लाभ मिलेगा। बेहतर विद्युत व्यवस्था क्षेत्र के विकास को गति देने में सहायक होगी।

ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपकेंद्र का निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और जनता को जल्द से जल्द इस परियोजना का लाभ मिलना चाहिए।

औरैया में सूने मकान का ताला तोड़ लाखों के जेवर-नकदी चोरी

एजेंसी, औरैया

अजीतमल कस्बे के आजाद नगर मोहल्ले में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपये के जेवरात, नकदी और घरेलू सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना का पता उस समय चला, जब इलाज कराकर दिल्ली से लौटे दंपती ने घर का ताला खोला। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, आजाद नगर निवासी अवध बिहारी दुबे अपनी पत्नी उमा दुबे के साथ 15 जून को उपचार के लिए दिल्ली गए थे। उनके घर पर ताला लगा हुआ था। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने मकान के मुख्य दरवाजे और कमरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बुधवार रात करीब 10 बजे जब दंपती घर वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमरों के ताले टूटे हुए हैं और सामान बिखरा पड़ा

◆ इलाज कराकर लौटे दंपती को लगा झटका, घर से लाखों के जेवर चोरी

है। अलमारी का लॉक भी उखड़ा हुआ था। पीड़ित ने बताया कि चोर सोने की अंगूठियां, मंगलसूत्र, झुमकी, पायल, कंधौनी सहित कई कीमती आभूषण चोरी कर ले गए। इसके अलावा करीब 80 हजार रुपये नकद, दो बोरी सरसों, स्टील के बर्तन, मिक्सी मशीन समेत अन्य घरेलू सामान भी गायब मिला।

घटना की जानकारी मिलते ही मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। कोतवाली प्रभारी रमेश सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही चोरी का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने रात्रि गश्त बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है और जल्द खुलासे का दावा किया है।

बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी की फांसी बदलकर 50 साल कैद की गई

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

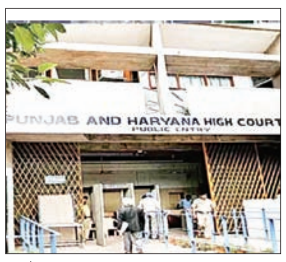

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सात वर्ष की उम्र पूरी होने से महज 17 दिन पहले दुष्कर्म और हत्या की शिकार हुई एक मासूम बच्ची के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी को सुनाई गई फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलते हुए निर्देश दिया कि वह बिना किसी रिमिशन के 50 वर्ष की वास्तविक कैद भुगतेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोषी को इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की समयपूर्व रिहाई या सजा में छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

हाई कोर्ट ने दुष्कर्म, हत्या, अपहरण और साक्ष्य मिटाने के अपराध में दोषी की दोषसिद्धि को पूरी तरह बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि दोषी के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य पर्याप्त और विश्वसनीय हैं, इसलिए उसके अपराध में किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती। हालांकि सजा के स्वरूप में बदलाव करते हुए फांसी के स्थान पर लंबी अवधि के कठोर कारावास का आदेश दिया गया।

फैसले में अदालत ने पुलिस जांच की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर टिप्पणी की। न्यायालय ने जांच के दौरान दस्तावेज गढ़ने के आरोपों, लोक अभियोजक की लापरवाही और ट्रायल कोर्ट की कमियों पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि गंभीर आपराधिक मामलों की जांच और सुनवाई पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और कानूनी मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, ताकि न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बना रहे। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जांच एजेंसियों और अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी है कि वे निष्पक्ष और साक्ष्य आधारित जांच सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करती है।

हरियाणा सरकार ने बदली तबादला व्यवस्था

सरकार ने सभी निगमों को नई ऑनलाइन तबादला नीति अपनाने के निर्देश किए जारी

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी बोर्ड, निगमों और अन्य सरकारी संगठनों में तबादला प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए नई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी-2026 लागू कर दी है। सरकार ने सभी संबंधित संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि वे इस नीति को तत्काल प्रभाव से अपनाएं या फिर इसके अनुरूप अपनी अलग तबादला नीति तैयार करें।

मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र में इस मामले को बेहद जरूरी बताते हुए सभी विभागों और संस्थाओं को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि 25 जून 2026 को अधिसूचित मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी-2026 प्रभावी हो चुकी है। इसके साथ ही वर्ष 2025 की मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया

है। सरकार ने बताया कि इससे पहले कई बोर्ड और निगम अपनी-अपनी अलग तबादला नीतियों के अनुसार कर्मचारियों के स्थानांतरण करते थे। अलग-अलग नियम होने के कारण कई बार प्रक्रिया में असमानता और विवाद की स्थिति पैदा होती थी। इसके अलावा उच्च न्यायालय की टिप्पणियों और सरकार द्वारा किए गए नियमों में बदलाव को देखते हुए अब सभी संस्थाओं को अपनी मौजूदा नीतियों की समीक्षा करने के लिए कहा गया है। नई व्यवस्था के तहत सभी बोर्ड, निगम और सरकारी संगठनों को यह विकल्प दिया गया है कि वे मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी-2026 को पूरी तरह लागू कर सकते हैं। यदि किसी संस्था के लिए प्रशासनिक या कानूनी कारणों से इसे उसी रूप में लागू करना संभव नहीं है, तो वह इसके मूल सिद्धांतों, दिशा-निर्देशों और उद्देश्यों को बनाए रखते हुए अपनी संशोधित नीति तैयार कर सकती है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई नीति का उद्देश्य तबादला प्रक्रिया को तकनीक आधारित, निष्पक्ष और मेरिट के आधार पर संचालित करना है। ऑनलाइन प्रणाली लागू होने से कर्मचारियों को तबादले के लिए अधिक पारदर्शी व्यवस्था मिलेगी और मनमाने तरीके से किए जाने वाले स्थानांतरण पर रोक लगेगी।

मुख्य सचिव के पत्र में सभी संबंधित संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे नई नीति के प्रस्ताव को जल्द से जल्द सक्षम प्राधिकारी या संबंधित बोर्ड के सामने मंजूरी के लिए रखें। मंजूरी मिलने के बाद संस्था को की गई कार्रवाई की जानकारी और स्वीकृत तबादला नीति की प्रति मानव संसाधन विभाग को भी भेजनी होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं है। राज्य के सभी सरकारी संगठन, बोर्ड और निगम अपनी प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार इसे अपना सकते हैं। इससे पूरे प्रदेश में तबादलों की प्रक्रिया में एकरूपता आने की उम्मीद है।

हरियाणा में बारिश का कहर सात जिलों मे बिगड़े हालात

भारतेंन्दु संवाददाता, हिसार। हरियाणा में मानसून की सक्रियता के चलते लगातार तीसरे दिन कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। गुरुवार सुबह प्रदेश के सात जिलों पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, फरीदाबाद, कैथल और पंचकूला में तेज बारिश दर्ज की गई। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद में भारी बारिश का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला। यहां तेज बारिश के कारण खेड़ी पुल का एक हिस्सा धंस गया। हादसे के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पुल पर वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी। इससे वाहन चालकों को परेशानी हुई और कई जगहों पर यातायात प्रभावित रहा। प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही हैं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। लगातार बारिश के चलते बस अड्डे परिसर में घुटनों तक पानी भर गया। यात्रियों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। वहीं, बस अड्डे की छत से पानी टपकने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी हुई। कई लोगों को अपने सामान के साथ जलभराव से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। गुरुग्राम में भी बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में रुक-रुककर बारिश हो रही है। इससे पहले मंगलवार को हुई तेज बारिश के कारण गुरुग्राम में एक राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा धंस गया था, जिससे यातायात प्रभावित हुआ था। प्रशासन की ओर से सड़क और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें छह शहरों करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए पहली बार इस सीजन में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में तेज बारिश और जलभराव की संभावना जताई है। लगातार बारिश के कारण प्रदेश के तापमान में करीब पांच डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। हालांकि कई जिलों में जलभराव और यातायात बाधित होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, जींद, कैथल और कुरुक्षेत्र के कुछ इलाकों में अभी अच्छी बारिश का इंतजार बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है।

न्यूज ब्रीफ

महेंद्रगढ़ रेल यात्रियों को राहत, चेतक और लालगढ़ एक्सप्रेस में बढ़ेंगे कोच

भारतेंन्दु संवाददाता, नारनौल। महेंद्रगढ़ जिले के रेल यात्रियों के लिए राहतभरी खबर है। बढ़ती यात्री संख्या को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने छह जोड़ी रेल सेवाओं में स्थायी रूप से अतिरिक्त डिब्बे जोड़ने का फैसला किया है। इससे नारनौल, अटेली और महेंद्रगढ़ स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि गाड़ी संख्या 22471/22472 लालगढ़-दिल्ली सराय-लालगढ़ एक्सप्रेस में लालगढ़ से 1 अगस्त और दिल्ली सराय से 3 अगस्त से एक थर्ड एसी और एक स्लीपर कोच स्थायी रूप से जोड़ा जाएगा। इससे यात्रियों को अधिक सीटें उपलब्ध होंगी और भीड़ से राहत मिलेगी।

82 प्रतिशत कॉलेज छात्र कर रहे एआई का इस्तेमाल, पढ़ाई में बदलाव

भारतेंन्दु संवाददाता, हिसार। उच्च शिक्षा में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) विद्यार्थियों के सीखने के तरीके में बड़ा बदलाव ला रहा है। हरियाणा के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के 400 स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों पर किए गए अध्ययन में सामने आया कि 82 प्रतिशत छात्र पढ़ाई के लिए जनरेटिव एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अध्ययन के अनुसार, 74 प्रतिशत विद्यार्थियों ने माना कि एआई की मदद से उनके असाइनमेंट और प्रोजेक्ट की गुणवत्ता बेहतर हुई है। वहीं 51 प्रतिशत से अधिक छात्रों ने स्वीकार किया कि एआई के उपयोग से उनकी कार्यक्षमता और आलोचनात्मक सोच में सुधार आया है। यह शोध गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधार्थी अनमोल खुराना ने किया है।

पीएम रैली स्थल के विश्राम गृह में मिले 21 एक्सपायर फायर सिलेंडर

भारतेंन्दु संवाददाता, जींद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित 17 जुलाई जींद दौरे और रैली की तैयारियों के बीच सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिस लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तैयारियों की समीक्षा बैठक की, वहां लगे सभी 21 फायर सिलिंडर एक्सपायर पाए गए। आपात स्थिति में आग से बचाव के लिए लगाए गए उपकरणों की स्थिति ने प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री मौजूद रहे, लेकिन किसी का ध्यान इस गंभीर कमी पर नहीं गया। प्रधानमंत्री दौरे को देखते हुए विश्राम गृह में लगातार अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों की आवाजाही जारी है।

मारपीट में घायल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की इलाज के दौरान मौत

भारतेंन्दु संवाददाता, नारनौल। महेंद्रगढ़ निवासी दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की इलाज के दौरान मौत हो गई। कांस्टेबल करीब तीन सप्ताह पहले हुई मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद उनका अस्पताल में उपचार चल रहा था, लेकिन बुधवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिवार और क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मृतक कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में तैनात थे और महेंद्रगढ़ जिले के रहने वाले थे। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले से जुड़े तथ्यों को जुटाना शुरू कर दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ब्लॉक समिति मेंबर को मारने आया था आरोपी दोस्त समेत गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने ब्लॉक समिति सदस्य की हत्या की साजिश को नाकाम करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी समिति सदस्य को गोली मारने की फिराक में घूम रहा था। मामले में कार्रवाई के दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी को पकड़ लिया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने हत्या की योजना बनाई थी और वारदात को अंजाम देने के लिए इलाके में घूम रहा था। पुलिस ने आरोपी के एक साथी को भी गिरफ्तार किया है, जो साजिश में शामिल बताया जा रहा है। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हत्या की योजना के पीछे क्या कारण था।

एडीसी की छुट्टी से अविश्वास प्रस्ताव की बैठक टली, रतिया चेयरपर्सन की कुर्सी फिर बची

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद

रतिया नगर परिषद की चेयरपर्सन के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली महत्वपूर्ण बैठक एक बार फिर स्थगित हो गई। इस फैसले से चेयरपर्सन को फिलहाल बड़ी राहत मिली है और उनकी कुर्सी एक बार फिर सुरक्षित बच गई। बैठक स्थगित होने का प्रमुख कारण संबंधित एडीसी का अवकाश पर होना बताया गया है।

जानकारी के अनुसार, अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने के लिए प्रशासन की ओर से बैठक निर्धारित की गई थी। लेकिन बैठक से पहले ही एडीसी के छुट्टी पर चले जाने के कारण निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसके चलते प्रशासन ने बैठक को अगली तिथि तक स्थगित करने का निर्णय लिया। सूत्रों के अनुसार, इस बीच नगर परिषद के कुछ पार्षद हिमाचल प्रदेश घूमने गए हुए थे। पार्षदों की अनुपस्थिति

को लेकर भी स्थानीय स्तर पर राजनीतिक चर्चाएं तेज रहीं।

विपक्ष का मानना है कि बैठक टलने से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, जबकि चेयरपर्सन समर्थकों ने इसे प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। नगर परिषद में पिछले कुछ समय से राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज बनी हुई हैं। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों अपने-अपने पक्ष में समर्थन जुटाने में लगे हैं।

बैठक स्थगित होने के बाद अब सभी की नजर प्रशासन द्वारा घोषित की जाने वाली नई तारीख पर टिकी हुई है। स्थानीय राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगली बैठक में सभी पार्षदों की मौजूदगी और मतदान की प्रक्रिया बेहद अहम रहेगी।

777 करोड़ राजस्व के बावजूद बिजली निजीकरण का विरोध तेज

भारतेंन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी को समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने के प्रस्ताव के विरोध में आंदोलन तेज हो गया है। बुधवार को हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) की जनसुनवाई में बिजली कर्मचारी संगठनों, पावर इंजीनियरों, किसान संगठनों और इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर प्रस्ताव का विरोध किया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने जनसुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली है।

अब इस मामले में आयोग के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न संगठनों ने तर्क दिया कि समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने से सरकारी बिजली व्यवस्था प्रभावित होगी और इससे निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह कदम सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली सेवाओं को कमजोर करने की दिशा में उठाया जा रहा है। उनका आरोप है कि निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए मौजूदा व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है, जिससे भविष्य में उपभोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

प्रस्ताव के विरोध में बुधवार को गुरुग्राम और नूंह की सभी बिजली डिवीजनों में कर्मचारियों ने दो घंटे तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और आयोग से इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की। किसान संगठनों और अन्य सामाजिक संगठनों ने भी कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन करते हुए बिजली सेवाओं के निजीकरण का विरोध किया।

जींद से पीएम मोदी करेंगे पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ, विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात

भारतेंन्दु संवाददाता, जींद

हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा है कि 17 जुलाई प्रदेश के विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन साबित होगा। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री करोड़ों रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे।

कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने गुरुवार को जींद के लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा हरियाणा के विकास को नई दिशा देगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम के सामने आयोजित होने वाली विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान वह वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ भी करेंगे। मंत्री ने

बताया कि 17 जुलाई को जींद के साथ-साथ पूरे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक अवसर होगा। प्रधानमंत्री मोदी भिवानी और नारनौल में नवनिर्मित दो बड़े श्रीराम मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में 10 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का शुभारंभ भी किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनने से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे करीब आधा दर्जन रेलवे फाटकों पर लगने वाले जाम की समस्या का समाधान होगा और यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर कई अन्य महत्वपूर्ण सड़क और आधारभूत ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे।

इनमें अंबाला-काला अंब ग्रीनफील्ड फोरलेन कॉरिडोर का विस्तार, दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे के हरियाणा हिस्से का उद्घाटन, जींद-गोहाना राष्ट्रीय राजमार्ग 352ए, हांसी-बरवाला फोरलेन और बीकानेर-सिवानी-सोनीपत सड़क परियोजनाओं का विस्तार शामिल है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में अत्याधुनिक सिख म्यूजियम का शिलान्यास भी किया जाएगा। इन सभी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास जींद में आयोजित जनसभा के माध्यम से वर्चुअल रूप से किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जींद दौरा हरियाणा में विकास और आधुनिक परिवहन व्यवस्था के नए अध्याय की शुरुआत करेगा।

उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन जैसी आधुनिक तकनीक से देश में पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार हरियाणा में सड़क, रेल, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में बड़े स्तर पर विकास कार्य कर रही हैं।

जमानत पर आया युवक बना निशाना, बहादुरगढ़ में सरेआम हत्या

भारतेंन्दु संवाददाता, झज्जर। बहादुरगढ़ में एक युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक कुछ समय पहले एक मर्डर केस में जमानत पर बाहर आया था। वारदात के दौरान बाइक पर सवार होकर आए तीन हमलावरों ने उसे निशाना बनाया और ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोली लगने के बाद भी युवक ने हिम्मत नहीं हारी और करीब 50 मीटर तक भागा, लेकिन गंभीर चोटों के कारण वह ज्यादा देर तक बच नहीं सका। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश या आपसी विवाद की आशंका जताई जा रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान कर ली गई है। मामले में आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस जल्द ही हमलावरों को पकड़ने का दावा कर रही है।

आठ महीने में तीसरा एसएचओ बदला एडिशनल थाना प्रभारी ने संभाला कार्यभार

भारतेंन्दु संवाददाता, सिरसा

सिरसा जिले में पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए शहर थाना के एसएचओ को हटा दिया है। पिछले आठ महीनों के दौरान यह तीसरी बार है, जब थाना प्रभारी को बदला गया है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने लगातार मिल रही शिकायतों और कार्यप्रणाली की समीक्षा के बाद यह कार्रवाई की है। फिलहाल एडिशनल थाना प्रभारी को थाने का प्रभार सौंप दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, एसएचओ के कार्यकाल को लेकर पुलिस अधिकारियों के पास विभिन्न प्रकार की शिकायतें पहुंच रही थीं। इन शिकायतों में आम लोगों के कार्यों में देरी, फरियादियों से व्यवहार और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों के निस्तारण को लेकर सवाल उठाए गए थे। शिकायतों की समीक्षा के बाद एसपी ने तत्काल प्रभाव से एसएचओ को हटाने के आदेश जारी कर दिए। पुलिस विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और लोगों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान उनकी प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से समय-समय पर अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। यदि किसी अधिकारी के खिलाफ लगातार शिकायतें मिलती हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

नए प्रभार के रूप में एडिशनल थाना प्रभारी ने कार्यभार संभाल लिया है। उनसे थाना क्षेत्र में बेहतर पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण और आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जा रही है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि थाने में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की शिकायत को गंभीरता से सुना जाएगा और पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। लगातार हो रहे प्रशासनिक बदलावों को लेकर शहर में चर्चा का माहौल है। लोगों का मानना है कि बार-बार थाना प्रभारी बदलने के बजाय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

पंचकूला में रेहड़ियों को लेकर भाजपा नेता और एसएचओ के बीच थाने में हुई तीखी बहस

भारतेन्दु संवाददाता, पंचकूला

पंचकूला के एक थाने में भाजपा नेता और थाना प्रभारी (एसएचओ) के बीच हुई तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मामला सड़क किनारे लगने वाली रेहड़ियों को लेकर शुरू हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ गई। घटना के दौरान थाने में मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के अनुसार, भाजपा नेता रेहड़ी संचालकों के पक्ष में अपनी बात रखने के लिए थाने पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी एसएचओ से बहस हो गई। वायरल वीडियो में भाजपा नेता यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 'तुम्हारे पैदा होने से पहले से थाने के बाहर रेहड़ियां लग रही हैं'।

इस पर एसएचओ ने जवाब देते हुए कहा कि क्या वे सरकारी जमीन पर कब्जा करवाना चाहते हैं। इसके बाद दोनों के बीच कुछ देर तक तीखी नोकझोंक चलती रही। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बहस के दौरान दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलों पर अड़े रहे। हालांकि मामला हाथापाई तक नहीं पहुंचा और बाद में मौजूद अन्य लोगों ने स्थिति को शांत कराया। वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण हटाना और कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है। वहीं भाजपा नेता का कहना है कि वे केवल लंबे समय से रोजी-रोटी कमा रहे रेहड़ी संचालकों की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रख रहे थे।

फिलहाल इस मामले में किसी पक्ष की ओर से औपचारिक शिकायत दर्ज होने की जानकारी नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रहा है। आने वाले दिनों में मामले की समीक्षा के बाद आवश्यक कदम उठाए जाने की संभावना जताई जा रही है।

सीईटी ग्रुप-डी में 35 हजार से ज्यादा सुधार, सबसे अधिक अभ्यर्थियों ने बदली फोटो

कल रात 11:59 बजे तक आवेदन में सुधार का अवसर, करेक्शन पोर्टल पर लगातार बढ़ रही अभ्यर्थियों की संख्या

भारतेंन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) की ओर से सीईटी ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा के लिए शुरू किया गया करेक्शन पोर्टल सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। आवेदन पत्र में सुधार का मौका मिलने के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपने विवरण अपडेट कर रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए बताया कि बुधवार सुबह 11:15 बजे तक कुल 35,260 अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में विभिन्न प्रकार के संशोधन कर चुके हैं।

आयोग ने अभ्यर्थियों को आवेदन में जरूरी सुधार करने के लिए कल रात 11:59 बजे तक का समय दिया है। इसके बाद करेक्शन विंडो बंद कर दी जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपने आवेदन पत्र की जांच कर लें और यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो समय रहते उसमें सुधार कर लें। जारी आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी फोटोग्राफ में बदलाव किया है। अब तक 10,722 अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र में लगी फोटो को अपडेट किया है। इसके बाद श्रेणी प्रमाणपत्र से जुड़े बदलाव सबसे अधिक किए गए हैं। कुल 2,988 अभ्यर्थियों ने अपना श्रेणी प्रमाणपत्र अपडेट किया है।

इसके अलावा 2,300 अभ्यर्थियों ने अनुबंध-8 (एनेक्सर-8) में संशोधन किया है। वहीं 2,264 अभ्यर्थियों ने श्रेणी प्रमाणपत्र संख्या में सुधार कराया है। प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि में बदलाव करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 2,170 रही, जबकि 2,155 अभ्यर्थियों ने प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकारी के नाम में संशोधन किया है। आयोग की ओर से लगातार अभ्यर्थियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे आवेदन पत्र में दर्ज सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें। भर्ती प्रक्रिया

में आवेदन संबंधी किसी भी गलती के कारण आगे परेशानी न हो, इसके लिए करेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अभ्यर्थी अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण, प्रमाणपत्रों से जुड़ी जानकारी और अन्य आवश्यक रिकॉर्ड में सुधार कर सकते हैं।

सीईटी ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदेश के हजारों युवाओं में उत्साह है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब आयोग की ओर से आगे की भर्ती प्रक्रिया को गति देने की तैयारी की जा रही है। करेक्शन विंडो के माध्यम से अभ्यर्थियों को अंतिम बार अपने आवेदन में सुधार का अवसर दिया गया है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी केवल वही बदलाव करें जिनकी वास्तव में आवश्यकता है और संशोधन करने के बाद आवेदन पत्र को दोबारा जांच लें। अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीईटी ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह सुधार प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा फोटो और प्रमाणपत्र संबंधी जानकारी अपडेट करने से साफ है कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान कई लोगों से छोटी-छोटी त्रुटियां रह गई थीं, जिन्हें अब ठीक किया जा रहा है। आयोग ने बताया कि करेक्शन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदनों की जांच की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने दस्तावेजों और विवरणों को दोबारा पुष्टि कर लें। सीईटी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा को लेकर युवाओं में लगातार उत्साह बना हुआ है और अब आगे की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। आयोग की ओर से अभ्यर्थियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे सुधार के बाद अपने आवेदन पत्र की सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें।

दिल्ली-एनसीआर में बारिश का कहर, जलभराव से जनजीवन बेहाल

बारिश ने रोकी दिल्ली-एनसीआर की रफ्तार, सड़कों पर जलभराव से बढ़ी परेशानी, प्रशासन अलर्ट पर

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में मॉनसूनी बारिश का कहर लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कों पर पानी भरने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है और लोगों को आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। बारिश के कारण जगह-जगह जाम की स्थिति बन रही है। निचले इलाकों में पानी भरने से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन और नगर निकाय की टीमें जलभराव वाले क्षेत्रों से पानी निकालने और हालात सामान्य करने में जुटी हुई हैं। वहीं, नोएडा में भारी बारिश के बीच एक इमारत का हिस्सा गिरने की घटना सामने आई है। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीमें मौके पर पहुंचीं और स्थिति का जायजा लिया। इमारत के हिस्से के गिरने के कारणों की जांच की जा रही है।

मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में आने वाले समय में भी बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर ही यात्रा करने की अपील की है। ट्रैफिक पुलिस ने भी लोगों को जलभराव वाले रास्तों से बचने और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। लगातार बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं जलभराव, ट्रैफिक जाम और इमारतों को नुकसान जैसी समस्याओं ने शहरी व्यवस्था की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। अधिकारियों का कहना है कि आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित विभाग अलर्ट पर हैं।

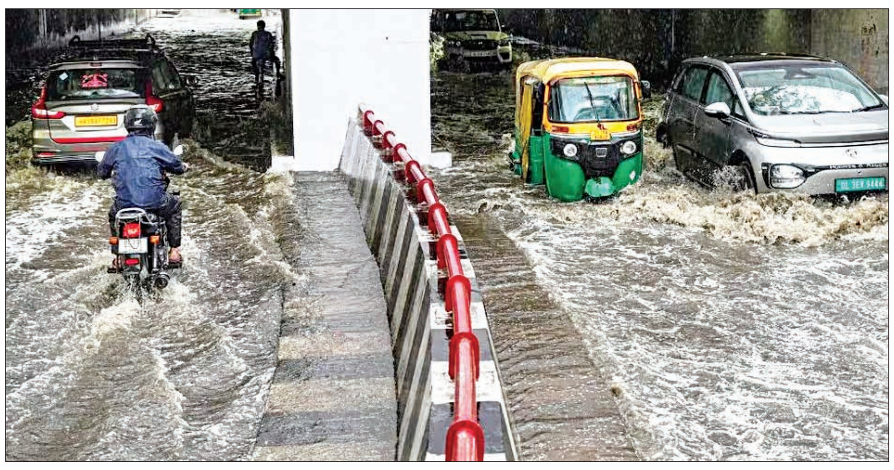

बारिश के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति और जनजीवन भी प्रभावित हुआ है।

कुछ स्थानों पर पेड़ गिरने और सड़कें क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं भी सामने आई हैं। राहत और बचाव टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रही हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे जलभराव वाले स्थानों पर जाने से बचें और मौसम संबंधी अपडेट पर नजर बनाए रखें। अधिकारियों के अनुसार, बारिश रुकने के बाद ही कई क्षेत्रों में स्थिति पूरी तरह सामान्य हो पाएगी। लगातार निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी सक्रिय किए गए हैं। प्रशासन ने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा है।

जलभराव वाले क्षेत्रों में पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा है। पुलिस और आपदा टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित रहने की अपील की गई है।

केजरीवाल ने बताया पेट्रोल का सही रेट,बोले- कीमत 82 रुपए होनी चाहिए

एजेंसी ,नई दिल्ली

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पेट्रोल के दाम कम करने की मांग करते हुए कहा कि मौजूदा कीमतों में काफी कमी की जा सकती है। केजरीवाल ने अपनी गणना का हवाला देते हुए दावा किया कि पेट्रोल की कीमत करीब 82 रुपये प्रति लीटर होनी चाहिए।

केजरीवाल ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में टैक्स और अन्य शुल्कों का बड़ा हिस्सा शामिल होता है, जिसके कारण आम लोगों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह पेट्रोल पर लगाए जाने वाले करों में राहत दे, ताकि आम जनता को महंगाई से राहत मिल सके। आम आदमी पार्टी प्रमुख ने कहा कि

केजरीवाल की पेट्रोल कीमत घटाने की मांग

ईंधन की बढ़ती कीमतों का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ता है। पेट्रोल महंगा होने से न केवल वाहन चालकों का खर्च बढ़ता है, बल्कि परिवहन लागत बढ़ने के कारण रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी असर पड़ता है। उन्होंने सरकार से जनहित में पेट्रोल के दाम घटाने की मांग की। केजरीवाल के इस बयान के बाद पेट्रोल की कीमतों और टैक्स व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र सरकार से ईंधन की कीमतों में कमी लाने के लिए कदम उठाने की मांग की है। वहीं, पेट्रोल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम, मुद्रा विनिमय दर और केंद्र व राज्य सरकारों के टैक्स सहित कई कारकों पर निर्भर करती हैं। सरकार की ओर से इस मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।

गाजीपुर के पास जलभराव से बढ़ी परेशानी, ट्रैफिक पुलिस ने बदला रूट

एजेंसी ,नई दिल्ली

गाजीपुर के पास एनएच-9 पर जलभराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई है। लगातार बारिश के चलते सड़क पर पानी जमा हो गया, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। खासतौर पर गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आने वाले लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले वाहन चालकों से अपील की है कि वे प्रभावित मार्ग का इस्तेमाल करने से बचें और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से यात्रा शुरू करने से पहले मार्ग की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी है। अधिकारियों के अनुसार, जलभराव वाले स्थानों पर यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद रहकर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित कर रही हैं और जरूरत के अनुसार रूट डायवर्जन भी किया जा रहा है।

दिल्ली-एनसीआर में बारिश का अलर्ट, अगले 12 घंटे बेहद अहम

एजेंसी ,नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में लगातार हो रही बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है, लेकिन कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी बढ़ गई है। तेज बारिश के कारण कई सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है।

मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों को बेहद अहम बताया है। इस दौरान दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। विभाग के अनुसार, कुछ इलाकों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। बारिश का सबसे ज्यादा असर निचले इलाकों और उन क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है जहां जलनिकासी की व्यवस्था कमजोर

है। दिल्ली के कई हिस्सों के साथ-साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखें। लगातार बारिश के कारण नगर निकाय और संबंधित विभाग जलभराव वाले क्षेत्रों की निगरानी कर रहे हैं। पंपों की मदद से पानी निकालने और यातायात व्यवस्था सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि आपात स्थिति से निपटने के लिए टीमें तैयार रखी गई हैं।

नोएडा की पॉश सोसायटी में दाखिल होते ही युवक ने ऊपर से कूदकर की खुदकुशी

एजेंसी ,नई दिल्ली

ग्रेटर नोएडा से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ नौकरी का इंटरव्यू देने आए एक युवक ने बहुमंजिला इमारत की 21वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। यह दुखद वाकया ग्रेटर नोएडा की 'पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी' के स्टूडियो अपार्टमेंट में हुआ।

पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, युवक बुधवार की शाम करीब 3:39 बजे अपार्टमेंट में दाखिल हुआ था और इसके ठीक 11 मिनट बाद, यानी करीब 3:50 बजे उसने 21वीं मंजिल से छलांग लगा दी। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सोसाइटी के सुरक्षाकर्मियों और लोगों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को नजदीकी अस्पताल

पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पहचान और जांच में उलझी पुलिस घटनास्थल से पुलिस को युवक का आधार कार्ड मिला है, जिससे उसकी पहचान हो सकी। इसके अलावा पुलिस को उसका मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है, लेकिन फोन पर पैटर्न लॉक लगे होने के कारण पुलिस को उसके परिजनों या दोस्तों के संपर्क नंबर ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। पुलिस फिलहाल मृतक के परिवार से संपर्क साधने की कोशिश में जुटी है ताकि घटना के संबंध में अधिक जानकारी जुटाई जा सके। शुरुआती तफ्तीश के आधार पर पुलिस को आशंका है कि युवक यहाँ किसी कंपनी में नौकरी का इंटरव्यू देने आया था। अंदेशा जताया जा रहा है कि इंटरव्यू में असफल (रिजेक्ट) होने के बाद वह गहरे मानसिक तनाव में आ गया और उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया। हालांकि, अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, इसलिए आत्महत्या की असली वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की हर पहलू से गहनता से जांच कर रही है।

20 दिन के धरने में तिरपाल को लेकर विवाद

एजेंसी, नई दिल्ली

जंतर-मंतर पर पिछले 20 दिनों से चल रहे कांकरोच जनता पार्टी के धरने को लेकर पार्टी नेता अभिजीत दीपके ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि भारी बारिश के बावजूद पुलिस ने धरनास्थल पर तिरपाल लगाने की अनुमति नहीं दी। उनका कहना है कि बारिश के दौरान प्रदर्शनकारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभिजीत दीपके के अनुसार, लगातार बारिश के कारण धरना स्थल पर मौजूद लोगों को परेशानी हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अस्थायी व्यवस्था करने की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने प्रशासन से प्रदर्शनकारियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखने की मांग की है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि धरना आगे भी जारी रहेगा और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई जाती रहेगी। वहीं, पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

न्यूज ब्रीफ

नोएडा चोरी कांडः ताला तोड़कर घर में घुसे चोर, पुलिस जांच में जुटी

एजेंसी नई दिल्ली नोएडा के दादरी इलाके में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है। चोरों ने एक बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपये की नकदी और कीमती गहनों पर हाथ साफ कर दिया। घटना के समय परिवार के लोग किसी काम से बाहर गए हुए थे। वापस लौटने पर घर का सामान बिखरा मिला और चोरी की जानकारी हुई। पीड़ित परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि चोरों की पहचान की जा सके। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चोरों ने घर की सुरक्षा व्यवस्था का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने पहले घर की रेकी की और मौका मिलते ही ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद अलमारी में रखी नकदी और आभूषण लेकर फरार हो गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया है। आसपास के संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे घर को लंबे समय के लिए खाली छोड़ते समय सुरक्षा के उचित इंतजाम करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। मामले की जांच जारी है।

ऑनलाइन प्रक्रिया के नाम पर ठगी, महिला के खाते से निकले 18 लाख रुपये

एजेंसी, नई दिल्ली गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में साइबर अपराधियों ने गैस कनेक्शन के नाम पर एक महिला से करीब 18 लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित महिला कामना जैन को आरोपियों ने मैसेज भेजकर धमकी दी कि अगर जल्द प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो उनका आईजीएल गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा। कनेक्शन कटने के डर से महिला ने मैसेज में दिए गए नंबर पर संपर्क किया। इसके बाद साइबर ठग ने खुद को गैस कंपनी का कर्मचारी बताकर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा। आरोपी ने महिला को अलग-अलग चरणों में पैसे भेजने के लिए मजबूर किया और इस तरह 16 अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए खाते से करीब 18 लाख रुपये निकाल लिए। ठगी का पता चलने के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल की मदद से आरोपी के मोबाइल नंबर, बैंक खातों और ऑनलाइन लेनदेन की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान मैसेज, कॉल या लिंक पर भरोसा न करें। गैस कनेक्शन, बिजली बिल या अन्य सेवाओं के नाम पर आने वाली फर्जी धमकियों से सावधान रहें और किसी भी भुगतान से पहले संबंधित विभाग से आधिकारिक पुष्टि जरूर करें। मामले में आरोपियों की तलाश जारी है।

दिल्ली में पुलिस की सरकारी गाड़ी में लगी भीषण आग,समय रहते बची दो जानें

एजेंसी ,नई दिल्ली

दिल्ली के अलीपुर इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक थाना प्रभारी की सरकारी स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही मिनटों में वाहन धू-धू कर जलने लगा। घटना के समय गाड़ी में थाना प्रभारी और चालक मौजूद थे, लेकिन दोनों ने समय रहते वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, हालांकि सरकारी वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गाड़ी से पहले धुआं निकलता दिखाई दिया, जिसके बाद अचानक आग की लपटें उठने लगीं। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी।

सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक स्कॉर्पियो पूरी तरह जल चुकी थी। आग लगने के दौरान कुछ समय के लिए आसपास के क्षेत्र में यातायात भी प्रभावित रहा और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने इलाके को घेर लिया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी माना जा रहा है, हालांकि पुलिस और संबंधित विभाग सभी संभावित कारणों की जांच कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है, ताकि आग की वास्तविक वजह का पता लगाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के सही कारणों की पुष्टि होगी। पुलिस ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और वाहन के रखरखाव सहित अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। इस घटना के बाद सरकारी वाहनों की नियमित तकनीकी जांच और सुरक्षा मानकों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

दिल्ली में बड़ा छात्र प्रदर्शन,20 जुलाई को संसद मार्च करेगा एनएसयूआई

एजेंसी ,नई दिल्ली

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने संसद मार्च करने का ऐलान किया है। संगठन ने इस मार्च की तारीख भी तय कर दी है। जानकारी के अनुसार, 20 जुलाई को बड़ी संख्या में छात्र और कार्यकर्ता दिल्ली में संसद की ओर मार्च करेंगे।

आरोप है कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों और कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। संगठन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से जवाबदेही तय करने और पद से इस्तीफा देने की मांग की है। नेताओं का कहना है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी जरूरी है। संगठन ने बताया कि संसद मार्च के जरिए वह अपनी मांगों को

एन एस यू आई का संसद मार्च का ऐलान

मजबूती से सरकार तक पहुंचाना चाहता है। इसके लिए देशभर के छात्रों और कार्यकर्ताओं से दिल्ली पहुंचने की अपील की गई है। का दावा है कि यह प्रदर्शन छात्रों की आवाज को उठाने और शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। वहीं, प्रशासन की ओर से इस प्रस्तावित मार्च को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की जा सकती है। दिल्ली में बड़े राजनीतिक और सामाजिक प्रदर्शनों के दौरान यातायात व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की ओर से विशेष इंतजाम किए जाते हैं। नेताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

दिल्ली-एनसीआर में बारिश का डबल असर,राहत भी और आफत भी

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में लगातार हो रही बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही आम लोगों की मुश्किलें भी काफी बढ़ गई हैं। कई इलाकों में भारी जलभराव होने से सड़कें तालाब जैसी नजर आने लगी हैं। बारिश का पानी घरों, दुकानों और निचले इलाकों में भर जाने से लोगों को दैनिक कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई प्रमुख सड़कों पर पानी जमा होने के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। कार्यालय जाने वाले कर्मचारी, स्कूल-कॉलेज के छात्र और अन्य यात्रियों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ रहा है।

लगातार बारिश के कारण कुछ स्थानों पर सड़कें धंसने की घटनाएं भी सामने आई हैं। इससे यातायात प्रभावित हुआ है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। कई जगहों पर पेड़ गिरने से रास्ते अवरुद्ध हो गए, जबकि कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। नगर निकायों और संबंधित विभागों

की टीमें जलनिकासी, पेड़ हटाने और यातायात सुचारु करने के काम में जुटी हुई हैं। मौसम विभाग ने आने वाले समय में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें, जलभराव वाले रास्तों पर सावधानी बरतें और मौसम से जुड़ी आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। लगातार हो रही बारिश ने जहां गर्मी से राहत दिलाई है, वहीं शहर की बुनियादी व्यवस्थाओं की तैयारियों पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नागरिकों को उम्मीद है कि संबंधित एजेंसियां जल्द हालात सामान्य करने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगी।

दिल्ली पुलिस ने बेरोजगार युवाओं को ठगने वाले रैकेट का किया खुलासा

फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर ठगी, आयकर विभाग के नाम पर बड़ा खेल उजागर

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने सरकारी नौकरी के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक बड़े फर्जी भर्ती रैकेट का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह सिविक सेंटर स्थित आयकर विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपये की ठगी कर रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी खुद को प्रभावशाली लोगों से जुड़ा बताकर उम्मीदवारों का विश्वास जीतते थे और उन्हें सरकारी विभागों में नियुक्ति का भरोसा दिलाते थे।

पुलिस के अनुसार, आरोपी सोशल मीडिया, मोबाइल कॉल और व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं तक पहुंचते थे। इसके बाद वे आयकर विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती का दावा करते हुए आवेदन प्रक्रिया, चयन और नियुक्ति पत्र

दिल्ली पुलिस ने फर्जी भर्ती रैकेट का किया भंडाफोड़

दिलाने के नाम पर मोटी रकम वसूलते थे। भरोसा बढ़ाने के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र और अन्य सरकारी दस्तावेज भी तैयार किए जाते थे। कुछ पीड़ितों को कार्यालय बुलाकर औपचारिक प्रक्रिया का दिखावा भी किया जाता था, ताकि उन्हें किसी तरह का संदेह न हो। शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और तकनीकी निगरानी तथा गोपनीय सूचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से नकली दस्तावेज, मोबाइल फोन, लैपटॉप, मुहरें और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया और ठगी की कुल रकम कितनी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सरकारी नौकरी के नाम पर किसी प्रस्ताव पर बिना आधिकारिक पुष्टि के भरोसा न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और गिरोह से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश लगातार जारी है।

ड्रोन और डिजिटल निगरानी से ग्रीनबेल्ट पर रखी जाएगी पैनी नजर

एजेंसी ,नई दिल्ली

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने ग्रीनबेल्ट क्षेत्रों पर बढ़ते अवैध कब्जों को रोकने के लिए नई रणनीति अपनाने का फैसला किया है। इसके तहत प्राधिकरण अब एक निजी कंपनी की सेवाएं लेगा, जो ग्रीनबेल्ट की नियमित निगरानी, सर्वेक्षण और अतिक्रमण की पहचान करने का कार्य करेगी। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करना और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती देना है। अधिकारियों का मानना है कि आधुनिक तकनीक और पेशेवर निगरानी व्यवस्था से अवैध कब्जों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जा सकेगा।

प्राधिकरण के अनुसार, कई शहरों में ग्रीनबेल्ट की जमीन पर समय-समय पर अवैध निर्माण, अस्थायी ढांचे और अन्य प्रकार के अतिक्रमण की शिकायतें मिलती रही हैं। इन मामलों में समय पर कार्रवाई नहीं होने के कारण समस्या लगातार बढ़ती रही है। अब निजी कंपनी नियमित निरीक्षण कर संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार करेगी और संबंधित अधिकारियों को समय पर जानकारी उपलब्ध कराएगी, ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके लिए डिजिटल मैपिंग, ड्रोन सर्वे और अन्य आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जा सकता है। एचएसवीपी का कहना है कि ग्रीनबेल्ट शहरों के पर्यावरण संतुलन, हरियाली और स्वच्छ वातावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन क्षेत्रों में अवैध कब्जे न केवल हरित क्षेत्र को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि शहरी विकास योजनाओं को भी प्रभावित करते हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जेएंडके को गुणवत्ता आधारित पर्यटन मॉडल अपनाना होगा : सीएम

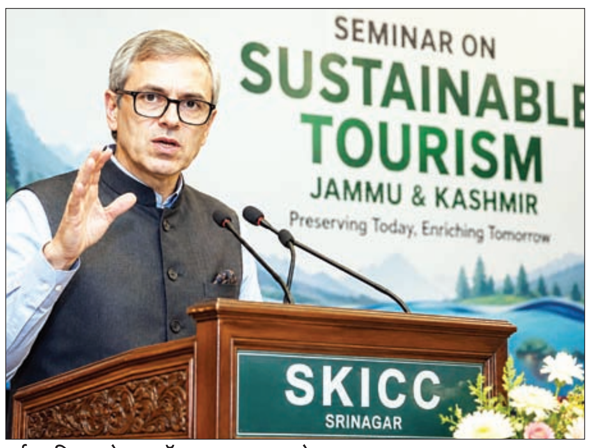

पर्यटन विकास के नए मॉडल पर उमर का जोर।

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर को इस सेक्टर को लंबे समय की सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए धीरे-धीरे 'वॉल्यूम-बेस्ड' (संख्या-आधारित) टूरिज्म मॉडल से 'वैल्यू-बेस्ड' (मूल्य-आधारित) टूरिज्म की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि सस्टेनेबिलिटी के बिना टूरिज्म एक 'बड़ी तबाही' है।

शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सस्टेनेबल टूरिज्म पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए उमर ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश को यह तय करना होगा कि वह 'वॉल्यूम-बेस्ड' डेस्टिनेशन बना रहना चाहता है या

◆सीएम उमर बोले, प्राकृतिक धरोहर बचाएं

'वैल्यू-बेस्ड' टूरिज्म इकॉनमी में बदलना चाहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय तक अशांति के कारण जम्मू-कश्मीर दशकों से 'वॉल्यूम टूरिज्म' पर निर्भर रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि पर्यटकों की संख्या से आगे बढ़कर सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान दिया जाए। पिछले साल हुई सुरक्षा घटना का ज़िक्र करते हुए उमर ने कहा कि इसने कश्मीर के टूरिज्म इकोसिस्टम की कमजोरी को उजागर कर दिया। उन्होंने कहा, 'एक घटना हुई और सब कुछ खत्म हो गया।

पीओके में मारे गए सभी आंदोलनकारी आतंकी : पाकिस्तानी सेना

पीओके में बढ़ते जनआंदोलन के बीच पाकिस्तान ने प्रदर्शनकारियों और नेताओं को बताया आतंकवादी

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में इन दिनों राजनीतिक प्रतिनिधित्व संवैधानिक अधिकारों और स्थानीय लोगों की भागीदारी की मांग को लेकर व्यापक जनआंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन ने पिछले कुछ सप्ताह में तेज रूप ले लिया है और अब यह रावलाकोट मुजफ्फराबाद मीरपुर कोटली बाग हट्टियान बाला सूधनोटी ढेरकोट और डड्याल जैसे अनेक क्षेत्रों तक फैल चुका है। आंदोलनकारी लंबे समय से यह आरोप लगा रहे हैं कि इस्लामाबाद की सरकार पीओके से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले स्थानीय जनता की राय लिए बिना करती है। उनका कहना है कि क्षेत्र के लोगों को न तो पर्याप्त राजनीतिक अधिकार मिल रहे हैं और न ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। इसी मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

रिपोर्टों के अनुसार आंदोलन के दौरान पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों और प्रदर्शनकारियों के बीच कई स्थानों पर टकराव हुआ है। रावलाकोट को इस आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र माना जा रहा है जहां पिछले एक महीने के दौरान कई हिंसक झड़पों की खबरें सामने आई हैं। इन घटनाओं में अनेक लोगों की मौत और कई अन्य के घायल होने के दावे किए गए हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रही संयुक्त अवामी

◆पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघन के लगे गंभीर आरोप

एक्शन कमेटी का कहना है कि प्रदर्शन पूरी तरह राजनीतिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग को लेकर किया जा रहा है लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा बलों द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। संगठन का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोगों को भी बल प्रयोग का सामना करना पड़ रहा है।

आंदोलन के नेताओं का कहना है कि पाकिस्तान सरकार ने पहले संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाया उसके बाद संगठन के कई प्रमुख नेताओं को हिरासत में लिया गया और विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई।

पाकिस्तान में जबरन गायब किए गए लोगों के मुद्दे पर तेज हुआ आंदोलन, न्याय की मांग बुलंद।

सरकारी दावों के बीच प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर उठे सवाल

अब आंदोलन से जुड़े लोगों और मारे गए प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी बताने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान का दावा है कि कुछ संगठन देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियां राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई कर रही हैं। दूसरी ओर आंदोलनकारी इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे अपनी राजनीतिक पहचान लोकतांत्रिक अधिकारों और स्थानीय हितों की लड़ाई बता रहे हैं।

इन घटनाओं के बीच मानवाधिकार को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विभिन्न रिपोर्टों और आंदोलन से जुड़े लोगों के अनुसार कई क्षेत्रों में महिलाओं और युवतियों के साथ दुर्व्यवहार तथा लोगों के लापता होने जैसे आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष पुष्टि होना अभी बाकी है। मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि यदि ऐसे आरोप सामने आते हैं तो उनकी पारदर्शी और निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।

आंदोलन के प्रमुख नेताओं का कहना है कि पीओके के लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उनका आरोप है कि जो लोग राजनीतिक सुधार और स्थानीय अधिकारों की मांग कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान सरकार का कहना है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और किसी भी प्रकार की हिंसा या अशांति फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

यूएपीए केस में डिजिटल साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई हुई तेज

बारामूला में यूएपीए केस को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी, कई जगहों पर की रेड

भारतेंदु संवाददाता, बारामूला। जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) से जुड़े एक मामले की जांच के तहत पुलिस ने कई स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई थाना बारामूला में दर्ज एफआईआर संख्या 43/2026 के संबंध में की गई। पुलिस के अनुसार यह मामला यूएपीए की धारा 13 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3) के तहत दर्ज है। जांच को आगे बढ़ाने और संभावित तकनीकी साक्ष्य एकत्र करने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न इलाकों में समन्वित तरीके से छापेमारी की गई।

पुलिस ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान बारामूला के अलग-अलग क्षेत्रों में स्थित कई आवासों की जांच की गई। इनमें इकबाल कॉलोनी निवासी फराह अशरफ गोजरी, कानली बाग निवासी वसीम अली कर, तौहीद गंज निवासी

बारामूला पुलिस ने कई स्थानों पर की छापेमारी।

तनवीर अहमद मीर उर्फ काका मीर, जो वर्तमान में गुलनार पार्क आजाद गंज में रह रहे हैं, तथा ख्वाजाबाग जेट्टी निवासी वसीम हुसैन मीर के घर शामिल हैं।

तलाशी के दौरान पुलिस ने कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने कब्जे में लिए, जिनमें चार मोबाइल फोन और एक लैपटॉप शामिल है। इन उपकरणों को आगे की फोरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है ताकि डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण कर मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा सके।

पुलिस का कहना है कि पूरा तलाशी अभियान कानून के निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप चलाया गया। कार्रवाई के दौरान कार्यकारी मजिस्ट्रेट तथा स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई ताकि जांच प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे।

लखनपुर में अमरनाथ यात्रियों को मिल रहीं बेहतर सुविधाएं

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर स्थित बाबा अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर में श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी है। जिला प्रशासन द्वारा लखनपुर कॉरिडोर में श्रद्धालुओं के लिए व्यापक और बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

लखनपुर कॉरिडोर केंद्र पर श्रद्धालुओं के लिए आरएफआईडी और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें आगे की यात्रा के लिए रवाना किया जाता है। इस दौरान यात्रियों के ठहराव के लिए विश्रामगृह, कूलर, पंखे, लंगर, शौचालय सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। श्रद्धालुओं ने जिला प्रशासन के इन प्रबंधों की सराहना करते हुए कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। आधार शिविर में श्रद्धालु

लंगर सेवा भी संचालित हो रही है

लखनपुर कॉरिडोर में दो लंगर संचालित किए जा रहे हैं जहां प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के व्यंजन श्रद्धालुओं को परोसे जा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर भेजा जा रहा है। पूरे क्षेत्र में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और वालंटियर भी यात्रियों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। श्रद्धालुओं के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरा लखनपुर बम-बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है।

बाबा बर्फानी के भजन-कीर्तन में लीन नजर आ रहे हैं जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। यात्रियों के लिए शिविर में बड़ी एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है जिस पर बाबा अमरनाथ और जम्मू-कश्मीर के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के दृश्य दिखाए जा रहे हैं।

मौसम विभाग का अलर्ट,कई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। मौसम विभाग ने आज से मौसम में बड़े बदलाव का अनुमान लगाया है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश, आंधी-तूफान, बिजली कड़कना और तेज हवाएं शामिल हैं। विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है क्योंकि आने वाली बारिश से कमज़ोर इलाकों, खासकर पहाड़ी इलाकों और मुख्य हाईवे पर अचानक बाढ़, लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने की संभावना है।

विभाग ने कहा कि कई जगहों पर रुक-रुक कर बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है जिससे मौजूदा गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। हालांकि, मौसम में बदलाव से कमजोर इलाकों में सर्फेस ट्रांसपोर्ट और बाहर की एक्टिविटीज में भी रुकावट आ सकती है।

स्थानीय लोगों, टूरिस्ट और अमरनाथ यात्रा के यात्रियों को अधिकारियों द्वारा जारी मौसम की सलाह मानने और तेज़ बारिश के दौरान बाढ़ की आशंका वाले इलाकों, लैंडस्लाइड ज़ोन और अस्थिर पहाड़ी ढलानों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है।

न्यूज ब्रीफ

सलाल बांध के गेट खुलने से चिनाब नदी में बढ़ा बहाव, नदी किनारे लोगों को सतर्क रहने की सलाह

भारतेंदु संवाददाता, रियासी। रियासी जिले में सलाल बांध के कई स्पिलवे गेट गुरुवार को खोल दिए गए। ऐसा ऊपरी जलग्रहण इलाकों में भारी बारिश के कारण पानी के बहाव में तेजी से हुई बढ़ोतरी के बाद किया गया। अधिकारियों ने बताया कि जलाशय में बढ़ते जलस्तर को नियंत्रित करने और चिनाब नदी में अतिरिक्त पानी के बहाव का सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए ये गेट खोले गए। पानी के बहाव में यह बढ़ोतरी पिछले कुछ दिनों में बांध के कैचमेंट इलाकों में हुई व्यापक बारिश के कारण हुई है जिससे जलाशय का जलस्तर काफी बढ़ गया है।

बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौट रहे गुजरात के तीर्थयात्री की मौत

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। अमरनाथ यात्रा के दौरान बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौट रहे तीर्थयात्री की मौत होने की सूचना मिली है। मृतक तीर्थयात्री की पहचान रमन भाई दानजी भाई पटेल (62) पुत्र दानजी भाई निवासी गुजरात के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रमन भाई बालटाल रूट से पवित्र यात्रा पूरी करके लौटते समय आज सुबह डुमेल में मृत पाए गए। मृतक ने बालटाल रूट से यात्रा शुरू की थी और कल बुधवार को दर्शन पूरे किए थे।

बलविंदर सिंह ने 'सतलुज' फिल्म पर बैन का किया विरोध

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। डीजीपीसी के उपाध्यक्ष एवं आरटीआई कार्यकर्ता बलविंदर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 25 हजार लोगों की मौत के कथित सच पर आधारित 'सतलुज' फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म उसी विषय पर आधारित है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्वीकार किया है। बलविंदर सिंह ने कहा कि किसी भी फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के बजाय लोगों को उसे देखने और अपनी राय बनाने का अधिकार मिलना चाहिए।

आज जम्मू के कंट्री इन में होगा एपीवाई कार्यक्रम

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से 10 जुलाई को जम्मू के कंट्री इन में एपीवाई (अटल पेंशन योजना) कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान पात्र लोगों को मौके पर ही अटल पेंशन योजना में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना है।

हिमकोटी मार्ग पर बैटरी कार सेवा बंद, मलबा हटाने का काम जारी

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। श्री माता वैष्णो देवी भवन जाने वाले हिमकोटी मार्ग पर भूस्खलन (लैंडस्लाइड) होने की वजह से ट्रैक को श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए एहतियातन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। फिलहाल बैटरी कार सेवा रोक दी गई है। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, भूस्खलन के तुरंत बाद ट्रैक पर गिरे मलबे और पत्थरों को हटाने का काम युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया है।

हीरानगर में उपमुख्यमंत्री की जनसभा में हंगामा, एनएलयू की मांग को लेकर नारेबाजी

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। हीरानगर में आयोजित उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी की जनसभा उस समय हंगामे में बदल गई जब जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग को लेकर एक एडवोकेट ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। स्टेटहुड की मांग को लेकर आयोजित इस जनसभा में उपमुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान एडवोकेट केतन कुमार अचानक खड़े हो गए।

ईओडब्ल्यू ने पुलवामा में जब्त नशीले पदार्थ किए नष्ट

भारतेंदु संवाददाता, पुलवामा। कश्मीर क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) ने एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स कश्मीर के साथ मिलकर पुलवामा जिले के आईजीसी लस्सीपोरा स्थित इंसीनरेटर में जब्त किए गए नशीले पदार्थों और अन्य प्रतिबंधित सामग्री का न्यायालय के आदेशों के अनुरूप निस्तारण किया। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए की गई और पूरी प्रक्रिया को कानूनी प्रावधानों के अनुरूप संपन्न कराया गया।

नशीले पदार्थों को ड्रग डिस्पोज़ल कमेटी की निगरानी में वैज्ञानिक तथा पर्यावरण के अनुकूल तरीके से जलाकर नष्ट किया गया ताकि उनका दोबारा दुरुपयोग न हो सके और पर्यावरण पर भी किसी प्रकार का

◆नशे की कमाई पर चला कानून का शिकंजा

प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

नष्ट किए गए प्रतिबंधित पदार्थों में चरस, गांजा और साइकोट्रोपिक गोलियां शामिल थीं। इन सभी पदार्थों को एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स कश्मीर ने विभिन्न अभियानों के दौरान जब्त किया था। मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार अभियान चला रही हैं और ऐसे अभियानों में बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए जाते हैं। जब्त सामग्री का समय पर और विधिसम्मत तरीके से निस्तारण करना भी कानून प्रवर्तन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जिससे इन पदार्थों के दोबारा अवैध नेटवर्क तक पहुंचने की संभावना समाप्त हो जाती है।

हर खतरे से निपटने में सक्षम है भारतीय वायुसेना : एपी सिंह

वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने अग्रिम इलाकों का किया दौरा, ऑपरेशनल क्षमता की समीक्षा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने उत्तरी सेक्टर के अग्रिम सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर वहां तैनात वायुसेना की विभिन्न इकाइयों की ऑपरेशनल तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण मौसम में देश की सुरक्षा में जुटे अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की तथा उनका उत्साह बढ़ाया। यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब उत्तरी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा सशस्त्र बल लगातार अपनी तैयारियों को और बेहतर बनाने में जुटे हैं।

दौरे के दौरान एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने अग्रिम मोर्चों पर तैनात अधिकारियों से मौजूदा सुरक्षा स्थिति परिचालन क्षमता और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विभिन्न सैन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया और सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात जवानों की तैयारियों की समीक्षा की। वायुसेना प्रमुख ने जवानों से सीधे संवाद करते हुए उनके अनुभव सुने और कठिन परिस्थितियों में निभाई जा रही उनकी जिम्मेदारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना का प्रत्येक अधिकारी और जवान देश की संप्रभुता तथा सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर रहा है।

एयर चीफ मार्शल ने कहा कि भारतीय वायुसेना आधुनिक तकनीक अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और उच्च स्तर के प्रशिक्षण के बल पर किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने में पूरी तरह सक्षम है।

जवानों का बढ़ाया हौसला

उन्होंने जवानों से हर समय सतर्क रहने और बदलते सुरक्षा परिदृश्य के अनुरूप अपनी तैयारियों को मजबूत बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय वायुसेना हर परिस्थिति में देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन करती रहेगी। उन्होंने अधिकारियों और जवानों के अनुशासन पेशेवर दक्षता तथा कर्तव्यनिष्ठा की विशेष रूप से प्रशंसा करते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिकों का समर्पण पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

एयर चीफ मार्शल ने जवानों की सराहना

कठिन मौसम ऊंचे पर्वतीय इलाकों और विषम परिस्थितियों में भी उनका मनोबल अटूट बना हुआ है। एयर चीफ मार्शल का यह दौरा न केवल सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है बल्कि इससे सीमाओं पर तैनात जवानों का मनोबल भी मजबूत हुआ है। भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह देश की सीमाओं की रक्षा और किसी भी संभावित चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर समय पूरी तरह तैयार है।

पंजाब में बढ़ रहा एचआईवी संक्रमण, हर महीने जीएमसी जम्मू पहुंच रहे 2500 नमूने

जीएमसी जम्मू की वायरोलॉजी लैब निभा रही अहम भूमिका

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। पंजाब में एचआईवी संक्रमण के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य के कई जिलों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है और सबसे अधिक प्रभावित वर्ग 25 से 30 वर्ष आयु के युवा हैं। संक्रमण की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब के आठ जिलों से हर महीने लगभग 2500 एचआईवी जांच के नमूने राजकीय मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) जम्मू की माइक्रोबायोलॉजी लैब भेजे जा रहे हैं। यहां जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट संबंधित जिलों को भेजी जाती है, जबकि

◆जीएमसी जम्मू की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

मरीजों का उपचार पंजाब में ही किया जाता है।

जीएमसी जम्मू की माइक्रोबायोलॉजी लैब को इसी वर्ष फरवरी में नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) की मान्यता प्राप्त हुई थी। इसके बाद यह जम्मू कश्मीर की पहली एनएबीएल मान्यता प्राप्त वायरोलॉजी लैब बन गई। अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के कारण इसकी जांच क्षमता और विश्वसनीयता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसी

हर महीने हो रही 2500 जांचें

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि पंजाब में एचआईवी संक्रमण बढ़ने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें नशीले पदार्थों का इंजेक्शन के माध्यम से सेवन एक प्रमुख वजह माना जा रहा है। संक्रमित सुइयों का साझा उपयोग संक्रमण के फैलाव को तेज करता है।

वजह से पंजाब के होशियारपुर, पठानकोट, जालंधर, रोपड़, मोगा, बटाला, नवांशहर और कपूरथला जिलों के एचआईवी नमूनों की जांच का दायित्व भी इस लैब को सौंपा गया है।

आस्था

334 वाहनों के काफिले के साथ अमरनाथ यात्रा का आठवां जत्था निकला

आठवें जत्थे में 8150 श्रद्धालु जम्मू से हुए रवाना

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और व्यापक प्रशासनिक तैयारियों के बीच गुरुवार को श्री अमरनाथ यात्रा का आठवां जत्था जम्मू स्थित भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से पवित्र गुफा की ओर रवाना हुआ। अधिकारियों के अनुसार इस जत्थे में कुल 8150 श्रद्धालु शामिल थे, जिन्हें 334 वाहनों के काफिले के माध्यम से दक्षिण कश्मीर हिमालय स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर के दोनों प्रमुख आधार शिविरों बालटाल और पहलगाम के लिए भेजा गया। श्रद्धालुओं में 3445 यात्री बालटाल मार्ग से जबकि 4705 श्रद्धालु पारंपरिक पहलगाम मार्ग से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुए। यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए पूरे

मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है तथा हर चरण पर सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासनिक अधिकारी पूरी सतर्कता के साथ तैनात हैं।

भगवती नगर बेस कैंप में तड़के से ही श्रद्धालुओं की चहल-पहल शुरू हो गई थी। निर्धारित समय पर सभी यात्रियों की पहचान और यात्रा संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई।

इसके बाद वाहनों के काफिले को सुरक्षा बलों की निगरानी में क्रमबद्ध तरीके से रवाना किया गया। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए पुलिस केंद्रीय सुरक्षा बल नागरिक प्रशासन स्वास्थ्य विभाग अग्निशमन सेवाओं तथा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के

सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है

मार्ग में चिकित्सा सहायता पेयजल भोजन विश्राम और आपातकालीन सेवाओं की भी समुचित व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष यात्रा को अधिक सुरक्षित और सुचारू बनाने के उद्देश्य से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है तथा पूरे यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

अधिकारियों ने संयुक्त रूप से सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं।

न्यूज ब्रीफ

कैडेट्स ने देशभक्ति प्रस्तुतियों से मोहा मन

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। 2 पंजाब नेवल यूनिट एनसीसी, अमृतसर द्वारा प्रताप वर्ल्ड स्कूल (पीडब्ल्यूएस), पठानकोट में आयोजित 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर (सीएटीसी) का भव्य समापन समारोह के साथ समापन हुआ। शिविर में पंजाब के विभिन्न जिलों से आए 450 से अधिक एनसीसी नेवल कैडेट्स ने भाग लिया। समारोह में जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी) पठानकोट कमलजीत कौर मुख्य अतिथि रहीं। उन्होंने कैडेट्स को अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र सेवा की भावना के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। इस अवसर पर हिंदू कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन सतीश महिंद्रू और अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। शिविर के दौरान कैडेट्स को ड्रिल, शस्त्र प्रशिक्षण, सीमैनशिप, बोट पुलिंग, आपदा प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास और नेतृत्व कौशल का प्रशिक्षण दिया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कैडेट्स ने देशभक्ति प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। विद्यालय की प्रधानाचार्या सुधा रानी और निदेशक सनी महाजन ने शिविर के सफल आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की। समापन अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

24.53 ग्राम चिट्टे सहित 7 आरोपी गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला बिलासपुर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 48 घंटे में तीन अलग-अलग मामलों में सात आरोपियों को गिरफ्तार कर 24.53 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने सभी मामलों में एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहली कार्रवाई थाना सदर पुलिस ने कंदरौर क्षेत्र के एक मकान में गुप्त सूचना के आधार पर की, जहां से 11.20 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दूसरी कार्रवाई एसडीटी टीम ने पद्दा फोरलेन क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान की, जहां मोटरसाइकिल सवार युवक से 8.48 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। तीसरी कार्रवाई थाना बरमाणा पुलिस ने पुराने सलापड़ पुल के पास की, जहां एक व्यक्ति के कब्जे से 4.85 ग्राम चिट्टा मिला। एसपी अभिषेक ने बताया कि पुलिस नशे की सप्लाई चेन और इससे जुड़े अन्य लोगों की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।

घुमारवीं कॉलेज ने रितिका को किया सम्मानित

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं की छात्रा रितिका को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कला संकाय अंतिम वर्ष की परीक्षा में मेरिट सूची में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर महाविद्यालय प्रशासन ने सम्मानित किया। महाविद्यालय के गणित व अर्थशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्राचार्य प्रोफेसर प्रीतम लाल ने रितिका को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि रितिका की यह उपलब्धि पूरे महाविद्यालय के लिए गौरव का विषय है और इससे अन्य विद्यार्थियों को भी मेहनत एवं लगन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। प्राचार्य ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे नियमित अध्ययन और कड़ी मेहनत के माध्यम से अपनी प्रतिभा को निखारें तथा मेरिट में स्थान हासिल करने का प्रयास करें। इस अवसर पर महाविद्यालय के कई शिक्षक उपस्थित रहे।

उपराष्ट्रपति करेंगे आईआईएएस शिमला में प्रदर्शनी और संगोष्ठी का वर्चुअल उद्घाटन

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान (आईआईएएस), शिमला में आयोजित 'वंदे मातरम की यात्रा' पर स्थायी प्रदर्शनी तथा 'सरदार पटेल का विजनः अखंडता, एकजुटता और संघवाद' विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। उपराष्ट्रपति को मूल रूप से शिमला पहुंचकर प्रदर्शनी और संगोष्ठी का उद्घाटन करना था, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका शिमला दौरा रद्द हो गया। अब वे वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन सत्र में शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे।

शाहपुर में 1.78 ग्राम चिट्टे सहित 2 युवक काबू

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। जिला कांगड़ा पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ जारी विशेष अभियान के अन्तर्गत शाहपुर में दो युवकों से चिट्टा बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना शाहपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की है। पुलिस थाना शाहपुर की टीम द्वारा द्रम्मण क्षेत्र में नियमित गश्त एवं वाहन चैकिंग के दौरान सर्विस रोड पर एक मोटरसाइकिल को जांच के लिए रोका गया। इस दौरान मोटरसाइकिल के पीछे बैठे युवक ने अपने कब्जे से एक संदिग्ध पुड़िया सड़क पर फेंक दी तथा उसे पैर से छिपाने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में तलाशी एवं जांच करने पर उक्त पुड़िया से 1.78 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया गया। आरोपी युवकों की पहचान नीरज राणा, निवासी गांव सुधेड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा आयु 25 वर्ष तथा साहिल, निवासी गांव घरोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, आयु 26 वर्ष के रूप में हुई है। एसपी कांगड़ा ने बताया कि उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध पुलिस थाना शाहपुर में अभियोग एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में आगामी कानूनी कार्रवाई एवं जांच नियमानुसार जारी है।

सितंबर तक खनन पर पूर्ण प्रतिबंध नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्ती

कहा- बल्क ड्रग पार्क परियोजना में 20 फीसदी काम पूरा

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में सितंबर माह तक खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने वीरवार को कहा कि राज्य सरकार ने मानसून को देखते हुए खनन पर रोक लगाई है और इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने हिमाचल-पंजाब सीमा पर अवैध खनन के मामलों में भी सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि जहां भी शिकायतें मिलती हैं, वहां संबंधित विभागों की जिम्मेदारी तय की जाती है और कार्रवाई की जाती है। हर्षवर्धन चौहान ने वीरवा को शिमला में पत्रकारों

आस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता व जवाबदेही जरूरी

से बातचीत में कहा कि सरकार अवैध खनन पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों में सामने आने वाले मामलों में संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जाता है और दोष मिलने पर कार्रवाई की जाती है। उनके अनुसार, सितंबर तक प्रदेश में खनन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लागू रहेगी। बल्क ड्रग पार्क परियोजना की प्रगति की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि परियोजना का करीब 15 से 20 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। कुछ टेंडर प्रक्रियाएं अभी पूरी होनी हैं, जिन्हें जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि परियोजना क्षेत्र में बिजली व्यवस्था से जुड़ा लगभग 75 प्रतिशत और पानी की व्यवस्था से जुड़ा करीब 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। सड़क निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को धनराशि जारी कर दी गई है और परियोजना क्षेत्र तक डबल लेन सड़क बनाई जाएगी। राम मंदिर में कथित चढ़ावे की चोरी के मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा पर निशाना साधा। राम मंदिर का निर्माण पूरे देश के लिए गर्व का विषय है और यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। आस्था से जुड़े किसी भी मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए। उनका कहना था कि कांग्रेस को इस मामले में सवाल पूछने का अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम के नाम पर वोट मांगे गए और कहा कि मंदिर किसी एक राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के पास राम के नाम का कोई अधिकार नहीं है और आस्था के मुद्दे पर उठने वाले सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए।

बारिश का दौर जारी, 15 जुलाई तक येलो अलर्ट

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय है और वीरवा सुबह से शिमला सहित कई क्षेत्रों में बारिश जारी रही। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने प्रदेश में 15 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। बीते 24 घंटों में चंबा के जोत में सबसे अधिक 45.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा बिलासपुर, शिमला, सिरमौर, कांगड़ा और किन्नौर जिलों में भी अच्छी वर्षा हुई। बारिश से तापमान में गिरावट आई है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंडक बढ़ गई है। उधर, कुल्लू की लारजी जलविद्युत परियोजना से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन ने व्यास नदी के किनारे रहने वाले लोगों, पर्यटकों और कारोबारियों से सतर्क रहने की अपील की है।

जीवन में स्पष्ट लक्ष्य और अनुशासन ही सफलता की कुंजी : राजेश धर्माणी

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। नगर व ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि स्पष्ट लक्ष्य, अनुशासन, ईमानदारी और निरंतर मेहनत ही जीवन में सफलता की वास्तविक कुंजी हैं।

वह वीरवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला औहर में आयोजित 'विद्यार्थियों के साथ संवाद' कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने विद्यार्थियों से अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार लक्ष्य निर्धारित कर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विद्यालय में प्राप्त शिक्षा तभी सार्थक होती है, जब उसे व्यवहारिक जीवन में अपनाया जाए। शिक्षकों को भी चाहिए कि वे विद्यार्थियों को विषयों के वास्तविक उपयोग और महत्व से अवगत करवाएं, जिससे उनकी समझ और आत्मविश्वास बढ़े। राजेश धर्माणी ने कहा कि दसवीं के बाद विषय चयन भविष्य के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा पहचानने और जीवन के लक्ष्यों की कार्ययोजना तैयार करने के लिए प्रेरित किया। संवाद के दौरान विद्यार्थियों ने मंत्री से उनके जीवन अनुभवों से जुड़े सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने कभी अपना ईमान नहीं बेचा। विद्यालय में बेहतर सुविधाओं के लिए मंत्री ने खेल मैदान और शौचालय निर्माण एवं सुधार कार्यों के लिए 55 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्रधानाचार्य, पंचायत प्रतिनिधि और शिक्षक उपस्थित रहे।

प्रदेश का आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र बनेगा किसानों की आय बढ़ाने का आधार : प्रो. चंद्र कुमार

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। कृषि व पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने धर्मशाला में डीसी कार्यालय में ढगवार में निर्माणाधीन अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के निर्माण कार्य एवं आधारभूत सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। मंत्री ने कहा कि परियोजना की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जा रही है, ताकि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण किए जा सकें। उन्होंने पानी, बिजली तथा सिविल कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। कांगड़ा के ढगवार में स्थापित किया जा रहा अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र प्रारंभिक चरण में प्रतिदिन 1.50 लाख लीटर (एलएलपीडी) दूध प्रसंस्करण क्षमता का होगा, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 3 लाख लीटर प्रतिदिन किया जा सकेगा।

केलांग में बनेगा उच्च हिमालयी चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, 11 जुलाई को जेपी नड्डा करेंगे शिलान्यास

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 11 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति जिले के केलांग में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के उच्च हिमालयी चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास करेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के तहत स्थापित किया जा रहा यह केंद्र देश में उच्च हिमालयी क्षेत्रों और जलवायु से जुड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों पर केंद्रित पहला समर्पित अनुसंधान केंद्र होगा।

आईसीएमआर के अनुसार केलांग में पहले से संचालित फील्ड स्टेशन को उन्नत कर इसे एक पूर्ण विकसित बहुविषयक अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। यहां उच्च हिमालयी क्षेत्रों से जुड़े स्वास्थ्य विषयों पर अनुसंधान, नवाचार और वैज्ञानिक क्षमता विकसित करने का काम किया जाएगा। आईसीएमआर का कहना है कि हिमालयी क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई, कठिन मौसम, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां और जलवायु परिवर्तन जैसी वजहों से स्वास्थ्य सेवाओं के सामने अलग तरह की चुनौतियां हैं। नया केंद्र इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उच्च हिमालयी शरीर की कार्यप्रणाली, पर्वतीय चिकित्सा, जलवायु से प्रभावित और उभरते रोग, संक्रामक और गैर-संचारी बीमारियां, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय और व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा आपदा चिकित्सा जैसे विषयों पर अनुसंधान करेगा। आईसीएमआर के अनुसार केंद्र में दूरदराज के इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म, टेलीमेडिसिन, ड्रोन आधारित स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति प्रणाली और रियल टाइम जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली का भी उपयोग किया जाएगा।

आईसीएमआर का नया केंद्र उच्च हिमालयी चिकित्सा अनुसंधान में निभाएगा अहम भूमिका

आईसीएमआर का कहना है कि यह केंद्र उच्च हिमालयी चिकित्सा से जुड़े वैश्विक अनुसंधान में भी योगदान देगा। यह केंद्र सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (एएफएमएस), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), हिमाचल प्रदेश सरकार और देश-विदेश के शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर भी काम करेगा। इसका उद्देश्य अनुसंधान के निष्कर्षों को स्वास्थ्य नीतियों और व्यावहारिक उपयोग से जोड़ना है।

राजशाही की मानसिकता छोड़ें विक्रमादित्य सिंह लोकतंत्र में जनता तय करती है नेतृत्व : बिंदल

भारतेन्द संवाददाता, शिमला। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के हालिया बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह के बयान यह दिखाते हैं कि वह अभी भी राजशाही की सोच से बाहर नहीं निकल पाए हैं। उनका कहना है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां नेतृत्व का फैसला जनता करती है, किसी परिवार या वंश के आधार पर नहीं होता।

डॉ. बिंदल ने वीरवार को कहा कि संभव है राजपरिवार से आने की वजह से विक्रमादित्य सिंह को लगता हो कि सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति राजनीति और समाज सेवा में आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को नेतृत्व करने का समान अधिकार है और अंतिम फैसला जनता के हाथ में होता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वह विक्रमादित्य सिंह की मौजूदा उम्र से भी अधिक समय से हिमाचल प्रदेश में जनसेवा और समाज सेवा से जुड़े रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनका परिवार आजादी से कई दशक पहले से समाज सेवा करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रमाण किसी से लेने की जरूरत नहीं है। डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया कि विक्रमादित्य सिंह लगातार व्यक्तिगत टिप्पणियां और झूठे आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी मंत्री ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं, जिसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मानहानि का दावा दायर किया था। उनका कहना है कि बाद में विक्रमादित्य सिंह ने व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क कर वह दावा वापस लेने का आग्रह किया था।

राष्ट्रीय शिक्षा सम्मान से सम्मानित हुए प्रताप वर्ल्ड स्कूल इंदौरा के निदेशक डॉ. विशाल

भारतेन्दु संवाददाता, इंदौरा। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, नवाचारपूर्ण कार्यों और प्रभावी नेतृत्व के लिए प्रताप वर्ल्ड स्कूल , इंदौरा के निदेशक डॉ. विशाल महाजन को प्रतिष्ठित 'डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन नेशनल अवॉर्ड-2026' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास तथा आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया।

इस उपलब्धि से प्रताप वर्ल्ड स्कूल परिवार में हर्ष का माहौल है। विद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और क्षेत्रवासियों ने डॉ. विशाल महाजन को बधाई देते हुए इसे पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय बताया। सम्मान प्राप्त करने के बाद डॉ. विशाल महाजन ने कहा, 'सच्ची सफलता पुरस्कारों से नहीं, बल्कि उन जीवनों से मापी जाती है, जिन्हें हम सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और उस भविष्य से जिसे हम मिलकर बेहतर बनाते हैं।' उन्होंने यह सम्मान विद्यालय के सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और सहयोगियों को समर्पित करते हुए कहा कि यह उपलब्धि उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक समर्पण एवं नई ऊर्जा के साथ कार्य करने की प्रेरणा देगी। उन्होंने कहा कि प्रताप वर्ल्ड स्कूल का उद्देश्य केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना भी है, ताकि वे भविष्य में देश और समाज के जिम्मेदार नागरिक बन सकें। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि डॉ. विशाल महाजन के नेतृत्व में प्रताप वर्ल्ड स्कूल ने शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के क्षेत्र में निरंतर नई उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रबंधन ने विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में विद्यालय भविष्य में भी शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा।

स्नातकोत्तर विषयों में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 10 जुलाई

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर में सत्र 2026-27 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। एमए इकोनॉमिक्स, एमए इंग्लिश, एमकॉम, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथ्स, एमएससी फिजिक्स और पीजीडीसीए में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. पीएस कटवाल ने बताया कि प्रवेश के लिए ऑनलाइन पोर्टल खुला हुआ है। पहली काउंसलिंग 13 जुलाई को संबंधित विभागों में आयोजित होगी, जबकि पहली मेरिट सूची 14 जुलाई को जारी की जाएगी। चयनित विद्यार्थियों को 15 और 16 जुलाई तक फीस जमा करनी होगी। दूसरी मेरिट सूची 17 जुलाई को जारी होगी। उन्होंने बताया कि सभी पीजी पाठ्यक्रमों में 30-30 सीटें उपलब्ध हैं और प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। विद्यार्थियों को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, मूल प्रमाण पत्र तथा आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां साथ लानी होंगी।

स्वच्छ, सुंदर व स्वस्थ इंदौरा के संकल्प के साथ चला व्यापक स्वच्छता अभियान, विधायक मलेंद्र ने किया नेतृत्व

भारतेन्दु संवाददाता, इंदौरा। स्वच्छ, सुंदर व स्वस्थ इंदौरा के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से इंदौरा उपमंडल की सभी 58 ग्राम पंचायतों में 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के अंतर्गत उपमंडल की सभी ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थलों, पंचायत परिसरों, संपर्क मार्गों तथा अन्य सामुदायिक स्थानों पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। पंचायतों में स्वच्छता रैलियां निकालकर लोगों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं जनभागीदारी का संदेश दिया गया।

इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मलेंद्र राजन ने ग्राम पंचायत इंदौरा में आयोजित मुख्य स्वच्छता रैली में भाग लिया। यह रैली पीएनबी बैंक इंदौरा से तारा खड्ड पुल तक निकाली गई। रैली में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों तथा स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इस अवसर पर विधायक मलेंद्र राजन ने कहा कि स्वच्छता केवल एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर, मोहल्ले और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के प्रति सजग रहेगा तो स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज का निर्माण स्वतः संभव होगा। उन्होंने सभी नागरिकों से इस अभियान को जनआंदोलन बनाने और नियमित रूप से स्वच्छता गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान किया।

भारतेन्दु Classifieds

नाम परिवर्तन

मैं निर्मला देवी पुत्री स्वर्गीय सुंदर सिंह निवासी छजोली डाकघर डंगार तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश घोषणा करती हूं कि मेरा सही नाम निर्मला देवी है तथा आधारकार्ड और स्कूल प्रमाण पत्र में भी निर्मला देवी ही दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड मौजा छजोली पटवार सर्कल दधोल में मेरा नाम गलती से कांता देवी दर्ज हो गया है। इसे दुरूस्त कर कांता देवी से निर्मला देवी किया जाए।

संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की सक्रियता ही सफलता का आधार: अनुराग

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा ने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने की दिशा में गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत भाजपा का दो दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग वीरवार को बाबा बालक नाथ की तपोभूमि शाहतलाई में शुरू हुआ।

प्रशिक्षण वर्ग के पहले दिन सात सत्र आयोजित किए गए, जिनमें भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने विभिन्न विषयों पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के बाद जिला अध्यक्ष कृष्णलाल चंदेल के स्वागत भाषण और प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य के उद्घाटन संबोधन से हुआ। प्रथम सत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने 'देश के समक्ष राजनीतिक एवं सामाजिक चुनौतियां' विषय पर विचार रखते हुए कार्यकर्ताओं से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने और जनसंपर्क को मजबूत करने का आह्वान किया। पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने 'बूथ प्रबंधन' विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि मजबूत बूथ व्यवस्था ही संगठन और चुनावी सफलता का आधार है। संगठन मंत्री सिद्धार्थन ने 'कार्यकर्ता विकास, संभाल एवं दायित्व बोध' विषय पर कहा कि कार्यकर्ता ही संगठन की सबसे बड़ी शक्ति हैं। विधायक त्रिलोक जम्वाल ने 'वैचारिक अधिष्ठान, एकात्म मानव दर्शन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एवं पंच निष्ठाएं' विषय पर कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से अवगत करवाया। वहीं, प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक सुशील राठौर और जिला आईटी संयोजक सुनील राणा ने डिजिटल मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रभावी सूचना तंत्र के उपयोग पर जानकारी दी।

कार्यालय ग्राम पंचायत गुराण विकास खंड बालीचौकी जिला मंडी हि.प्र.

निविदा सूचना

ग्राम पंचायत गुराण विकास खंड बालीचौकी जिला मंडी हि0प्र0 द्वारा वित बर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न विकास कार्यो के निष्पादन हेतु आवश्यकता अनुसार अधिकृत विक्रेताओ से मोहरबंद निविदाए आमन्त्रित कि जाती है जो की रजिस्ट्रीड डाक के माध्यम से पंचायत में आनी चाहिए । निविदाए दिनांक 21-07-2026 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे सायः 5 बजे तक पहुँच जानी चाहिए । निविदाए दिनांक 23-07-2026 को प्रातः 11:00 बजे के बाद ग्राम पंचायत की बैठक में कमेटी (पंचायत कोरम) व निविदादाताओं के समक्ष पंचायत कार्यालय में खोली जाएगी। प्रशासकीय कारणों से इस तिथि को बदलाब करने का अधिकार ग्राम पंचायत गुराण के पास सुरक्षित रहेगा। इस दशा में सूचना समाचार पत्र में प्रदर्शित नहीं की जाएगी । सूचना ग्रांम पंचायत के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी । **गाड़ी के स्टेशन** -1 निशेयनी 2 खईधार 3 गुराण । **घोडा ढलवान के स्टेशन** -1 निशेयनी से दुधला 2. निशेयनी से थाना गाँव 3. निशेयनी से बनैला 4. खईधार से खानेरी 5. खईधार से खनोरुधार 6. घिरडा से खनोरूधार 7. खईधार से पिरशुडर 8. खईधार से लोअर बनैला 9. मैन रोड से राकनी 10. खईधार से जोगनीधार 11. कोला गाँव से सलारड़ू 12. कोला गाँव से कुठाहडा 13. दुआडा से वीर मन्दिर।

क्र.स.	सामग्री का विवरण	मात्रा जिसमें मूल्य वांछित है
1	रेत (खड्डु /नदी/क्रशर की)	प्रति घन मीटर
2	बजरी 10 एमएम, 20एमएम,40एमएम	प्रति घन मीटर
3	सोलिंग /बोल्डर पत्थर खरीद/ कैरिज	प्रति घन मीटर
4	पकी ईंटें (मिटटी के भटे की)	प्रति इंट
5	साइन बोर्ड CIB 2 '3, 3 '4/वाल राइटिंग/पेंटिंग	प्रति बोर्ड
6	घोडा ढलवान (रेत,बजरी,सिमेंट,इंट,पेवर ,पत्थर)etc	प्रति घन मीटर/प्रति बैग/दूरी अनुसार
7	शटरिंग लकड़ी व् लोहा	प्रति फुट
8	हार्डवेयर Items सरिया 8mm.10mm.12mm,16mm एंग,चैनल साईज वार,टाईल,पेंट,रीलिंग लोहा, Building Fitting,PVC,HDPE पाईप विभिन्न साईज,सेनीटरी फिटिंग्स लेवर रेट आदि	आईटम वार /प्रति किलों/प्रति पॉइंट
9	GI SHEET 45mm 50mm कलरकोटेड शीट्स व् सीलिंग शीट्स etc.	प्रति शीट/साईज वार
10	डस्टबीन	प्रति पीस
11	मशीन द्वारा कटान (cutting through jcb & L&T mashine)	प्रति घन मीटर/ प्रति घंटा
12	क्रेट वायर 4mm ,5 mm	प्रति चत्र/प्रति सेट
13	स्टेशनरी	विभिन्न रजिस्टर.कागज इत्यादि सभी आईटम्स
15	सिमेंट ढलवान by vehicle बालीचौकी से गुराण (स्टोरिंग,लोडिंग व् अनलोडिंग)	प्रति बैग
16	लकड़ी लोहा.एलुमिनियम फिटिंग्स व् डोर विंडो	आईटम वार/प्रति घन फुट
17	पलाईबोर्ड शीटे/Other फेंसी आइटम्स/पैलिंग PVC फटे Sheets	आईटम वार/साईज वार
18	लेबर रेट पेलिंग PVC व् बुडन	प्रति स्केयर फुट
19	सोलर स्ट्रीट लाईट 9,12 वाट लाईटस मुरम्मत,	प्रति एक Configuration सहित
20	RCC कलवर्ट Pipe	साईज वार
21	फर्नीचर आइटम्स (सभी प्रकार की फर्निचर वस्तुए	प्रति Itemsपूर्ण विवरण सहित
22	बेल्डिंग वर्क्स	प्रति किलो /कविंटल
23	पेंटर दिवार लेखन	प्रति दिन/स्केयर फुट
24	सेव,पलम,नाशपाती,जापानी,खुमानी के पौधे (उद्यान विभाग व् प्रमाणित नर्सरी)	प्रति पौधा
25	इलेक्ट्रिकल फिटिंग सामग्री व् लेबर	आईटम वार/प्रति पॉइंट
26	बैंच पार्क हेतू	आईटम वार
27	LCD बड़ी,माइक,कंप्यूटर.PS,प्रोजेक्टर etc.	साईज वार कपंनी नाम सहित
28	स्वच्छता प्रबंधन हेतू विभिन्न आईटम(प्लास्टिक कचरा संग्रहण शेड)	आईटम वार/साईज वार
29	अन्य सामग्री जो पंचायत की कार्य में प्रयुक्त होनी है उपरण दर्शाई हो	आईटम वार

नियम व् शर्ते :-1 निविदादाताओ के पास अपना पंजीकरण GST no. होना चाहिए । 2 ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को खनन विभाग से हस्ताक्षरित M-Form जमा करवाने होंगे। 3.निर्माण सामग्री कार्य स्थल/सड़क तक उपलब्ध करवानी होगी । 4 सामग्री समय पर नही देने पर स्वीकृत वेंडर को रद्द करके दुसरे वेंडर को सप्लाई आदेश दिया जायेगा। 5.किसी भी त्रुटी पाई जाने पर कुटेशन रद्द करने का अधिकार पंचायत के पास सुरक्षित होगा । 6 निविदा केवल डाक के माध्यम से मान्य होगी । 7 सामग्री की दरें साफ शब्दों में लिखी होनी चाहिए । 8.सामग्री खरीद का अन्तिम मूल्य विभाग जी JUSTIFICATION व अनुमोदित निविदाताओं के साथ NEGOTITION अनुसार ही किया जायगा

प्रधान/सचिव कार्यालय ग्राम पंचायत गुराण विकास खंड बालीचौकी जिला मंडी हि.प्र.

कार्यालय ग्राम पंचायत पन्जाई विकास खंड बालीचौकी जिला मंडी हि.प्र.

निविदा सूचना

ग्राम पंचायत पन्जाई विकास खंड बालीचौकी जिला मंडी हि0प्र0 द्वारा वित बर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न विकास कार्यो के निष्पादन हेतु आवश्यकता अनुसार अधिकृत विक्रेताओ से मोहरबंद निविदाए आमन्त्रित कि जाती है जो की रजिस्ट्रीड डाक के माध्यम से पंचायत में आनी चाहिए । निविदाए दिनांक 24-07-2026 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे सायः 5 बजे तक पहुँच जानी चाहिए । निविदाए दिनांक 27-07-2026 को प्रातः 11:00 बजे के बाद ग्राम पंचायत की बैठक में कमेटी (पंचायत कोरम) व निविदादाताओ के समक्ष पंचायत कार्यालय में खोली जाएगी। प्रशासकीय कारणों से इस तिथि को बदलाब करने का अधिकार ग्राम पंचायत पन्जाई के पास सुरक्षित रहेगा। इस दशा में सूचना समाचार पत्र में प्रदर्शित नहीं की जाएगी। सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी। **गाड़ी स्टेशन के नामः**- 1. पन्जाई बस स्टैंड 2 पन्जाई केंची 3 काशुनाला 4 रोपा.5 जंजीगाड. 6.बुहंदा 7. आनना । **घोडा ढलवान के स्टेशनों के नामः**-1 जंगलीपुंज से डोभा 2.जंगलीपुंज से झुलका 3..रोड से काशु मन्दिर 4.रोड से गहूधारठी 5 .रोड से जुघरी 6. रोड से आनना 7. रोड से डाहणी 8. रोड से दली 9. रोड से ठाहरी 10. थाची रोड से शेगला 11.मैंन रोड से रोपा 12. डडवाडी रोड(गाँव) से तीन बाबड़ी 13.मैंन रोड से गाँव डोभा

क्र.स.	सामग्री का विवरण	मात्रा जिसमें मूल्य वांछित है
1	रेत (खड्डु /नदी/क्रशर की)	प्रति घन मीटर
2	बजरी 10 एमएम, 20एमएम,40एमएम	प्रति घन मीटर
3	सोलिंग /बोल्डर पत्थर खरीद/ कैरिज	प्रति घन मीटर
4	पकी ईंटें (मिटटी के भटे की)	प्रति इंट
5	साइन बोर्ड CIB 2 '3, 3 '4/वाल राइटिंग/पेंटिंग	प्रति बोर्ड
6	घोडा ढलवान (रेत,बजरी,सिमेंट,इंट,पेवर ,पत्थर)etc	प्रति घन मीटर/प्रति बैग/दूरी अनुसार
7	शटरिंग लकड़ी व् लोहा	प्रति फुट
8	हार्डवेयर Items सरिया 8mm.10mm.12mm,16mm एंग,चैनल साईज वार,टाईल,पेंट,रीलिंग लोहा, Building Fitting,PVC,HDPE पाईप विभिन्न साईज,सेनीटरी फिटिंग्स लेवर रेट आदि	आईटम वार /प्रति किलों/प्रति पॉइंट
9	GI SHEET 45mm 50mm कलरकोटेड शीट्स व् सीलिंग शीट्स etc.	प्रति शीट/साईज वार
10	डस्टबीन	प्रति पीस
11	मशीन द्वारा कटान (cutting through jcb & L&T mashine)	प्रति घन मीटर/ प्रति घंटा
12	क्रेट वायर 4mm ,5 mm	प्रति चत्र/प्रति सेट
13	स्टेशनरी	विभिन्न रजिस्टर.कागज इत्यादि सभी आईटम्स
15	सिमेंट ढलवान by vehicle बालीचौकी से पन्जाई (स्टोरिंग,लोडिंग व् अनलोडिंग)	प्रति बैग
16	लकड़ी लोहा.एलुमिनियम फिटिंग्स व् डोर विंडो	आईटम वार/प्रति घन फुट
17	पलाईबोर्ड शीटे/Other फेंसी आइटम्स/पैलिंग PVC फटे Sheets	आईटम वार/साईज वार
18	लेबर रेट पेलिंग PVC व् बुडन	प्रति स्केयर फुट
19	सोलर स्ट्रीट लाईट 9,12 वाट लाईटस मुरम्मत,	प्रति एक Configuration सहित
20	RCC कलवर्ट Pipe	साईज वार
21	फर्नीचर आइटम्स (सभी प्रकार की फर्निचर वस्तुए	प्रति Itemsपूर्ण विवरण सहित
22	बेल्डिंग वर्क्स	प्रति किलो /कविंटल
23	पेंटर दिवार लेखन	प्रति दिन/स्केयर फुट
24	सेव,पलम,नाशपाती,जापानी,खुमानी के पौधे (उद्यान विभाग व् प्रमाणित नर्सरी)	प्रति पौधा
25	इलेक्ट्रिकल फिटिंग सामग्री व् लेबर	आईटम वार/प्रति पॉइंट
26	बैंच पार्क हेतू	आईटम वार
27	LCD बड़ी,माइक,कंप्यूटर.PS,प्रोजेक्टर etc.	साईज वार कपंनी नाम सहित
28	स्वच्छता प्रबंधन हेतू विभिन्न आईटम(प्लास्टिक कचरा संग्रहण शेड)	आईटम वार/साईज वार
29	अन्य सामग्री जो पंचायत की कार्य में प्रयुक्त होनी है उपरण दर्शाई हो	आईटम वार

नियम व् शर्ते :-1 निविदादाताओ के पास अपना पंजीकरण GST no. होना चाहिए । 2 ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को खनन विभाग से हस्ताक्षरित M-Form जमा करवाने होंगे। 3.निर्माण सामग्री कार्य स्थल/सड़क तक उपलब्ध करवानी होगी । 4 सामग्री समय पर नही देने पर स्वीकृत वेंडर को रद्द करके दुसरे वेंडर को सप्लाई आदेश दिया जायेगा। 5.किसी भी त्रुटी पाई जाने पर कुटेशन रद्द करने का अधिकार पंचायत के पास सुरक्षित होगा । 6 निविदा केवल डाक के माध्यम से मान्य होगी । 7 सामग्री की दरें साफ शब्दों में लिखी होनी चाहिए । 8.सामग्री खरीद का अन्तिम मूल्य विभाग जी JUSTIFICATION व अनुमोदित निविदाताओं के साथ NEGOTITION अनुसार ही किया जायगा

प्रधान/सचिव कार्यालय ग्राम पंचायत पन्जाई विकास खंड बालीचौकी जिला मंडी हि.प्र.

गार्बिन मुगुरुजा का खूबसूरत अंदाज

स्पेन। गार्बिन मुगुरुजा स्पेन की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने फ्रेंच ओपन और विंबलडन जैसे ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। अपनी शानदार तकनीक, आक्रामक खेल शैली और मेहनत के दम पर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय टेनिस में विशेष पहचान बनाई है।

फीफा विश्व कप फाइनल में होगा संगीत का महाकुंभ

हाफटाइम शो में मैडोना, शकीरा, जस्टिन बीबर समेत कई दिग्गज कलाकार देंगे प्रस्तुति

एजेंसी, लंदन

फीफा विश्व कप-2026 का फाइनल फुटबॉल के साथ-साथ संगीत की दुनिया में भी नया इतिहास रचने जा रहा है। पहली बार विश्व कप फाइनल में हाफटाइम शो आयोजित होगा, जिसमें वैश्विक पॉप स्टार जस्टिन बीबर, मैडोना, शकीरा और बीटीएस जैसे दिग्गज कलाकार एक ही मंच पर प्रस्तुति देंगे। यह आयोजन 19 जुलाई को न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम में विश्व कप फाइनल के दौरान होगा।

फीफा और ग्लोबल सिटिजन ने आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि जस्टिन बीबर इस ऐतिहासिक शो के सह-हेडलाइनर होंगे। उनके अलावा नाइजीरियाई गायक बर्ना बॉय, विश्व प्रसिद्ध ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर गुस्तावो डुडामेल, पीएस-22 कोरस और रॉक बैंड कोल्डप्ले भी प्रस्तुति देंगे। पूरे शो का क्यूरेशन कोल्डप्ले के फ्रंटमैन क्रिस मार्टिन ने किया है।

यह हाफटाइम शो केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहेगा। इसका उद्देश्य फीफा ग्लोबल सिटिजन एजुकेशन फंड के लिए 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाना है। यह फंड दुनिया भर के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और फुटबॉल से जुड़ने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। अब तक 5 करोड़ डॉलर से अधिक की राशि जुटाई जा चुकी है। साथ ही विश्व कप 2026 के प्रत्येक टिकट की बिक्री से एक अमेरिकी डॉलर इस फंड में दान किया जाएगा।

फीफा अध्यक्ष जियानी इनफैनटिनो ने कहा कि शिक्षा दुनिया की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है और यह हाफटाइम शो फुटबॉल, संगीत तथा मानवीय मूल्यों के साथ शिक्षा के उद्देश्य को भी आगे बढ़ाएगा।

जस्टिन बीबर ने कहा कि विश्व कप पूरी दुनिया को जोड़ने वाला मंच है और इस ऐतिहासिक शो का हिस्सा बनना उनके लिए गर्व की बात है। वहीं बर्ना बॉय ने इसे अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान बताते हुए कहा कि यह आयोजन फुटबॉल और संस्कृति के उत्सव के साथ दुनिया भर के बच्चों की शिक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

भारतीय स्पिनर साई किशोर फिर खेलेंगे काउंटी क्रिकेट, ग्लॉस्टरशायर से किया करार

एजेंसी, नई दिल्ली

भारत के बाएं हाथ के स्पिनर आर साई किशोर एक बार फिर इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। 29 वर्षीय साई किशोर ने ग्लॉस्टरशायर के साथ 2026 काउंटी चैंपियनशिप सीजन के अंतिम छह मुकाबलों के लिए अनुबंध किया है। वह 20 अगस्त से वॉर्सेस्टरशायर के खिलाफ चेल्टनहैम में होने वाले मैच से टीम के साथ जुड़ेंगे।

इसके बाद वह डर्बीशायर और मिडिलसेक्स के खिलाफ ब्रिस्टल में तथा डरहम, लंकाशायर और केंट के खिलाफ होने वाले अवे मुकाबलों में भी ग्लॉस्टरशायर का प्रतिनिधित्व करेंगे। साई किशोर ने तमिलनाडु के लिए 54 प्रथम श्रेणी मैचों में 223 विकेट लिए हैं। इस दौरान उन्होंने 14 बार पांच विकेट और 11 बार चार विकेट लेने का कारनामा किया है। इससे पहले वह 2025 में सरे की ओर से काउंटी चैंपियनशिप खेल चुके हैं, जहां उन्होंने डरहम के खिलाफ जीत के दौरान प्रतियोगिता में अपना पहला पांच विकेट हॉल हासिल किया था।

साई किशोर ने क्लब की ओर से जारी बयान में कहा, 'मैं जॉन और ग्लॉस्टरशायर के सभी लोगों का दिल से आभारी हूं जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया। ग्लॉस्टरशायर एक समृद्ध इतिहास वाला क्लब है और यहां का शानदार माहौल मुझे बेहद उत्साहित करता है।' उन्होंने आगे कहा कि मैं हमेशा इंग्लैंड की परिस्थितियों में अपने खेल को परखना चाहता था। प्रबंधन से बातचीत के बाद मुझे लगा कि यही मेरे लिए सही जगह है। मैं ग्लॉस्टरशायर की जर्सी पहनने, ब्रिस्टल और चेल्टनहैम में प्रशंसकों से मिलने और टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने का इंतजार कर रहा हूं।

ग्लॉस्टरशायर के मुख्य कोच जॉन लुईस ने कहा कि हम साई किशोर का टीम में स्वागत करते हुए बेहद उत्साहित हैं। वह एक अनुभवी और साबित खिलाड़ी हैं, जो हमारी टीम को काफी मजबूती देंगे। क्लब अंतिम छह काउंटी चैंपियनशिप मैचों में बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह देखना दिलचस्प होगा कि इस चरण में एक विदेशी स्पिनर टीम पर कितना प्रभाव डालता है। उन्होंने आगे कहा, 'सीजन के इस समय इंग्लैंड की पिचें आमतौर पर स्पिन गेंदबाजी के लिए अनुकूल होती हैं। हमें उम्मीद है कि साई किशोर टीम के लिए अहम योगदान देंगे और सकारात्मक प्रभाव छोड़ेंगे।'

स्पोर्ट्स विंडो

पलानी, उस्मानी, रूडी आईसीसी एसोसिएट सदस्यों के बने निदेशक

एजेंसी, एडिनबर्ग। फ्रांस के गुरुमूर्ति पलानी, संयुक्त अरब अमीरात के मुबाशिर उस्मानी और नामीबिया के रूडी वान वूरेन को दो साल के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के एसोसिएट सदस्य देशों का निदेशक चुना गया। यह चुनाव आईसीसी की सालाना कांफ्रेंस के दौरान हुए । पलानी और वान वूरेन पहली बार आईसीसी बोर्ड में शामिल होंगे जबकि उस्मानी को दोबारा चुना गया है। चुनाव पांच उम्मीदवारों के बीच हुए जिनमें उस्मानी, इमरान ख्वाजा, महिंदा वल्लीपुरम, पलानी ओर वान वूरेन शामिल थे । चुनाव में 43 एसोसिएट सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया । अमेरिकी क्रिकेट और क्रिकेट कनाडा आईसीसी सदस्यता से निलंबित होने के कारण मतदान में हिस्सा नहीं ले सके। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने एक बयान में कहा,'' एसोसिएट सदस्य खेल के विकास और वैश्विक प्रसार में अहम भूमिका निभाते हैं । मैं सभी क्षेत्रों में हो रही अच्छी प्रगति को आगे बढ़ाते हुए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।''

हैमस्ट्रिंग चोट के कारण लिटन जिम्बाब्वे के बाकी वनडे मैचों से हुए बाहर

एजेंसी, हरारे। बंगलादेश के बल्लेबाज लिटन कुमार दास हैमस्ट्रिंग चोट के कारण जिम्बाब्वे के खिलाफ शेष एकदिवसीय सीरीज से बाहर हो गये है। बंगलादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने बुधवार को बताया कि हैमस्ट्रिंग की चोट से ठीक न हो पाने के कारण बल्लेबाज लिटन कुमार दास हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ बाकी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। बीसीबी ने बताया कि लिटन की जगह दूसरे और तीसरे वनडे के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज परवेज हुसैन एमोन को टीम में शामिल किया गया है, जबकि लिटन अपने रिहैबिलिटेशन (चोट से उबरने की प्रक्रिया) को जारी रखने के लिए ढाका लौटेंगे। बंगलादेश टीम के फिजियो बायजेदुल इस्लाम खान ने कहा, 'लिटन पहले ही पहला वनडे नहीं खेल पाए थे और अभी भी मैच के लिए पूरी तरह फिट नहीं हैं। आज उनका फिटनेस टेस्ट हुआ और उसका नतीजा संतोषजनक नहीं रहा।

भारतीय महिला टीम लॉर्ड्स टेस्ट मैच का आनंद लेने के लिए है उत्साहित: मजूमदार

एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय महिला टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार का मानना है कि उनकी टीम टी-20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से बाहर होने की निराशा से उबर चुकी है और लॉर्ड्स में कल से शुरु होने वाले पहले महिला टेस्ट मैच के मौके का आनंद लेने के लिए उत्साहित है। भारत शुक्रवार से शुरू होने वाले ऐतिहासिक चार-दिवसीय मैच में इंग्लैंड का सामना करेगा। मेहमान टीम वर्ल्ड कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद नई शुरुआत करना चाहेगी। वहीं, इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया से उपविजेता रहने के बाद इस टेस्ट मैच में उतरेगी। मजूमदार ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि लॉर्ड्स में पहले कभी महिला टेस्ट मैच नहीं खेला गया। उन्होंने इस मौके को एक ऐतिहासिक बताते हुए कहा, 'बिल्कुल, मेरा मतलब है, लेकिन यह बात मुझे हैरान करती है कि लॉर्ड्स में यह पहला टेस्ट मैच है।

खेल महाशक्ति बनने की राह पर भारत

एजेंसी, नई दिल्ली

◆ दो साल में 36 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की सफल मेजबानी, 2028 तक 29 और आयोजनों की तैयारी : खेल मंत्री

भारत वैश्विक खेल आयोजनों का प्रमुख केंद्र बनकर तेजी से उभर रहा है। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की तैयारी और 2036 ओलंपिक-पैरालंपिक की दावेदारी के बीच देश ने जनवरी 2025 से जून 2026 तक 15 से अधिक शहरों में 36 अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया है।

इन आयोजनों में विश्व चैंपियनशिप, एशियाई चैंपियनशिप, विश्व कप और अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग प्रतियोगिताएं शामिल रहीं। एथलेटिक्स, हॉकी, बैडमिंटन, निशानेबाजी, मुक्केबाजी, फुटबॉल, शतरंज, साइक्लिंग और पैरा स्पोर्ट्स समेत कई खेलों की मेजबानी भारत ने की। कई प्रतियोगिताएं पहली बार देश में आयोजित हुईं।

केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी से खिलाड़ियों को घरेलू मैदान पर उच्चस्तरीय प्रतिस्पर्धा मिलती है, खेल अवसंरचना मजबूत होती है और भारत की वैश्विक पहचान बढ़ती है। उन्होंने कहा कि 2030 राष्ट्रमंडल खेलों और 2036 ओलंपिक की तैयारी में यह अनुभव महत्वपूर्ण साबित होगा। जुलाई से दिसंबर 2026 के बीच भारत में 11 और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जबकि 2027-28 के लिए 19 प्रमुख आयोजनों की मेजबानी भी तय हो चुकी है। 2025 से 2028 के बीच 65 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के साथ भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रहा है।

हालैंड को रोकने के लिए इंग्लैंड को बनानी होगी योजना : मॉर्गन रोजर्स

एजेंसी, कैनसस सिटी। इंग्लैंड राष्ट्रीय टीम के मिडफील्डर मॉर्गन रोजर्स का मानना है कि फीफा विश्वकप 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्वे के स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड को रोकने लिए हमें योजना बनानी होगी। मैनचेस्टर सिटी के फॉरवर्ड हालैंड ने नॉर्वे को क्वार्टरफाइनल तक पहुंचाने में सात गोल किए हैं, जहां शनिवार को मियामी में उनका सामना थ्री लायंस से होगा।

हालैंड ने चार सीजन में तीसरी बार प्रीमियर लीग का गोल्डन बूट जीता और 35 मैचों में 27 गोल किए।

एस्टन विला के मिडफील्डर रोजर्स ने कहा कि उनके पास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकरों में से एक है और जब वह मैदान पर होता है, तो कुछ भी हो सकता है।अगर एर्लिंग दो गोल कर दे और उनकी टीम मैच जीत जाए तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। उसने अपने करियर में कई बार ऐसा किया है। वह ऐसा करता ही रहेगा। उस जैसे खिलाड़ी को रोकने, उसकी सप्लाई लाइन को काटने के लिए पूरी टीम के प्रयास की जरूरत होती है और हमें यह देखना होगा कि वे एक टीम के रूप में क्या करते हैं, वे मौके कैसे बनाते हैं और उसे यथासंभव बेअसर करने की कोशिश करनी होगी।

ब्यूमोंट ने कहा क्रिकेट को अलविदा

एजेंसी, नई दिल्ली

◆ भारत के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट होगा इंग्लैंड की स्टार ओपनर का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला

इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की अनुभवी सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 35 वर्षीय ब्यूमोंट भारत के खिलाफ शुक्रवार से लॉर्ड्स में शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच के बाद अपने 17 साल लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत करेंगी।

2009 में इंग्लैंड के लिए पदार्पण करने वाली ब्यूमोंट ने 260 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। वह इंग्लैंड की ओर से वनडे में सर्वाधिक 12 शतक लगाने वाली बल्लेबाज हैं और तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं। 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 208 रन की पारी खेलकर वह इंग्लैंड की पहली महिला टेस्ट दोहरा शतकवीर बनी थीं।

ब्यूमोंट ने कहा कि 17 वर्षों तक इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि वह टीम की जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंपें। उनके अनुसार, लॉर्ड्स में होने वाला पहला महिला टेस्ट उनके अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कहने का सबसे उपयुक्त अवसर है। ब्यूमोंट 2015 में पेशेवर केंद्रीय अनुबंध पाने वाली शुरुआती महिला खिलाड़ियों में शामिल थीं। 2017 महिला वनडे विश्व कप में 410 रन बनाकर उन्होंने इंग्लैंड को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का पुरस्कार भी जीता। हालांकि, ब्यूमोंट घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखेंगी और द ब्लेज़ तथा बर्मिंघम फीनिक्स की ओर से विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगी।

मूसलाधार बारिश से गंगा के तटीय क्षेत्र जलमग्न

एजेंसी, अमरोहा। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में पिछले चौबीस घंटों से जारी मूसलाधार बारिश के चलते अमरोहा जिले में गुरुवार को गंगा नदी के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए है। बिजनौर स्थित चौधरी चरण सिंह बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते तटीय क्षेत्रों में स्थित किसानों के खेत और पुरोहितों की झोपड़ियां पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं।

जिला प्रशासन ने गुरुवार सुबह स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी बाढ़ चौकियों को चौबीसों घंटे स्थिति पर नज़र बनाए रखने के निर्देश किए हैं।पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बुधवार और गुरुवार को भी लगातार जारी भारी वर्षा के कारण गंगा नदी के जलस्तर में 40 सेंटीमीटर से अधिक की बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके बाद मीटर गेज पर पानी का स्तर बढ़कर 199.65 मीटर तक पहुंच गया है। बिजनौर बैराज से निरंतर पानी छोड़े जाने के चलते खादर क्षेत्र के गांवों में तेजी से पानी फैल रहा है, जिससे खड़ी फसलें जलमग्न होने की आशंका से ग्रामीण और किसान बेहद चिंतित हैं।

बाढ़ खंड विभाग के अवर अभियंता सुभाष के मुताबिक इलाके में वर्षा की निरंतरता और बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण स्थिति संवेदनशील बनी हुई है, जिसे देखते हुए सभी प्रभावित क्षेत्रों में मुस्तैदी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं।

ईरान-अमेरिका तनाव बढ़ा, होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर टकराव तेज

ईरान की शर्तों पर ही खुलेगा होर्मुज जलडमरूमध्य : गालिबाफ

एजेंसी, मॉस्को

ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर ग़ालिबाफ ने गुरुवार को कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने का फैसला अमेरिका की धमकियों के आधार पर नहीं बल्कि ईरान की शर्तों और नीतियों के अनुसार लिया जाएगा। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि दबाव और सैन्य कार्रवाई से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। उनके अनुसार किसी भी हमले का जवाब दिया जाएगा और बेवजह संघर्ष की स्थिति पैदा करना दोनों पक्षों के लिए नुकसानदायक साबित होगा।

मोहम्मद बाकर ग़ालिबाफ ने कहा कि अमेरिका को यह समझना होगा कि धमकियों और अपने वादों से पीछे हटने की नीति की कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य ईरान की व्यवस्था और निर्णयों के तहत ही खुलेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी बाहरी दबाव के आधार पर ईरान अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करेगा।

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी तरह का तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते विवाद पर दुनिया के कई देश नजर बनाए हुए हैं।

इससे पहले ईरानी मीडिया ने फारस की खाड़ी स्थित अबू मूसा द्वीप और ईरान के कई शहरों में विस्फोटों की जानकारी दी थी। ईरानी समाचार एजेंसियों के अनुसार ईरानशहर चाबहार कोनारक सिरिक जास्क और बंदर अब्बास जैसे क्षेत्रों में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। बंदर अब्बास में वायु रक्षा बलों द्वारा कार्रवाई किए जाने की भी खबरें सामने आईं। हालांकि इन घटनाओं से जुड़े विस्तृत विवरण को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं।

अमेरिका की ओर से भी ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जानकारी दी गई।

विकास | सड़क और जल परियोजनाओं से राजस्थान के विकास को मिलेगी नई रफ्तार

पूरे देश में सड़कों का मजबूत नेटवर्क हो रहा तैयार : बिरला

एजेंसी, कोटा

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में सड़कों और राजमार्गों का ऐसा मजबूत नेटवर्क तैयार किया है जिसने भारत के विकास को नई गति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार होता है और आधुनिक भारत में सड़क परियोजनाएं विकास की रीढ़ बनकर उभर रही हैं।

कोटा के गोपालपुरा मंडाना में आयोजित आमसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल बड़े शहरों तक विकास सीमित रखना नहीं है बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ऐसी योजनाओं पर काम कर रही हैं जिनसे आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

ओम बिरला ने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह एक्सप्रेसवे आने वाले समय में देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली प्रमुख परियोजनाओं में शामिल होगा। इससे व्यापार और परिवहन को गति मिलेगी तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क से गांवों और शहरों के बीच दूरी कम होती है और किसानों व्यापारियों तथा आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलता है।

उन्होंने कहा कि सड़क परियोजनाओं के विस्तार से राजस्थान जैसे बड़े राज्य में विकास की संभावनाएं और मजबूत होंगी। आधुनिक राजमार्गों के निर्माण से पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। उन्होंने कहा कि मजबूत परिवहन व्यवस्था किसी भी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है।

लोकसभा अध्यक्ष ने राजस्थान सरकार के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जल उपलब्धता बढ़ाने वाली परियोजनाएं राजस्थान के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। यमुना जल समझौता और राम जल सेतु जैसी योजनाएं राज्य को जल सुरक्षा की दिशा में आगे ले जाने में सहायक होंगी।

इससे पहले ओम बिरला ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया।

पेंशन प्रभाग को मई में शिकायत निवारण के मामले में दूसरा स्थान

एजेंसी, नई दिल्ली। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के बैंकिंग और बीमा प्रभागों को मई में शिकायतों के निवारण के मामले में समूह ए में क्रमश: दूसरा और छठा स्थान प्राप्त हुआ। वित्त मंत्रालय की गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार वित्तीय सेवा विभाग को प्रतिवर्ष 2.50 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त होती हैं और नवंबर 2025 से यह विभाग लगातार शिकायत निवारण मूल्यांकन एवं सूचकांक (जीआरएआई) रैंकिंग में शीर्ष 10 मंत्रालयों/ विभागों में शामिल रहा है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी मई 2026 की जीआरएआई रैंकिंग में बीमा प्रभाग ने ग्रुप ए श्रेणी (जहां 500 या उससे अधिक शिकायतें दर्ज होती हैं) में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि बैंकिंग प्रभाग इसी श्रेणी में छठे स्थान पर रहा।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि शिकायत निवारण के मामले में सुधार के लिए सात जनवरी 2024 से वित्तीय सेवा विभाग के सचिव स्वयं आकस्मिक रूप से 20-20 शिकायतों में कृत का की समीक्षा करते रहे हैं। इस प्रक्रिया में शिकायतकर्ताओं के साथ-साथ संबंधित वित्तीय संस्थानों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा वरिष्ठ प्रबंधन भी सीधे भाग लेते हैं। इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों का विश्वास बढ़ाना और शिकायतों का सार्थक एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है।

वित्तीय सेवा विभाग ने भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरणतथा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ 'प्रभावी शिकायत निवारण ढांचा' विषय पर कार्यशालाओं का भी आयोजन किया है। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य शिकायतों के मूल कारणों की पहचान करना तथा उनके समाधान की गुणवत्ता में सुधार लाना था।

अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़ी कंपनियों पर ईडी का शिकंजा

एजेंसी, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ई-कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक के आवास पर छापेमारी की है। इस दौरान रिलायंस अनिल अंबानी समूह से जुड़े संदिग्ध लेनदेन और संपत्तियों से संबंधित कई आपत्तिजनक दस्तावेज व महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए गए हैं। जांच में यह सामने आया है कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड के हजारों करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन को सुनियोजित तरीके से शेल कंपनियों के नेटवर्क के जरिए डायवर्ट किया गया था। ईडी की जांच के अनुसार, समूह से जुड़ी इन कंपनियों को बिना किसी उचित प्रक्रिया या लोन चुकाने की क्षमता की जांच किए बिना भारी कॉर्पोरेट लोन मंजूर किए गए थे। ये शेल कंपनियां केवल कागजों पर मौजूद थीं और इनके बैंक खातों का संचालन रिलायंस समूह के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाता था।